www.raceias.com

RAJESH ACADEMY FOR CIVIL EXAMINATIONS
RACE IAS

RACE IAS

करेंट अफेयर्स

जनवरी, 2025 | ₹ 75/-

संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग तथा अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी

- संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग
- एनएचएआई ठेकेदार रेटिंग प्रणाली
- भारतीय स्टार कछुआ
- स्जोग्रेन रोग
- बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक 2024
- राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एंव प्रशिक्षण परिषद्
- गुरूवायुर मंदिर
- सक्रिय शासन और समय पर कार्यान्वयन (प्रगति) मंच
- संयुक्त संसदीय समिति
- पैन 2.0 परियोजना
- एकलव्य डिजिटल प्लेटफॉर्म
- विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024

Gist of

THE HINDU | pib पत्र सूचना कार्यालय PRESS INFORMATION BUREAU भारत सरकार | The Indian EXPRESS JOURNALISM OF COURAGE | Kurukshetra A JOURNAL ON RURAL DEVELOPMENT | YOJANA

Raghav Publication House

अनुक्रमणिका

भूगोल, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

पेज 1 – 7

- ब्लैक थ्रिप्स
- बार-टेल्ड गॉडविट
- WOH G64 स्टार
- रेड-ब्रेस्टेड फ्लाईकैचर
- एंथ्रेक्स
- सुबाबुल वृक्ष
- केप भैंस
- एनएचएआई ठेकेदार रेटिंग प्रणाली
- नोवा
- भारतीय स्टार कछुआ
- जेनकास्ट मॉडल
- इंडियन रॉक पायथन
- डुलसिबेला कैमंचाका
- डार्क कॉमेट्स
- कैलीप्टोसेफेलेला गेई
- शेर-पूंछ वाला मकाक

द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह

पेज 8 – 9

- संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग
- अभ्यास सिनबाक्स (CINBAX)
- हरिमाउ शक्ति अभ्यास

स्वास्थ्य और शिक्षा

पेज 9 – 9

- स्जोग्रेन रोग

भारतीय अर्थव्यवस्था

पेज 10 – 13

- बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024
- तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 2024
- लिनन निरीक्षण और छंटाई सहायक प्रणाली (LISA)
- अन्ना चक्र
- राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी)
- MuleHunter.AI
- ई-एनडब्ल्यूआर आधारित प्रतिज्ञा वित्तपोषण के लिए ऋण गारंटी योजना

कला और संस्कृति

पेज – 14–15

- गुरुवायुर मंदिर
- पांडुपोल हनुमान मंदिर

राजव्यवस्था और शासन

पेज 16 – 17

- सक्रिय शासन और समय पर कार्यान्वयन (प्रगति) मंच
- किसी न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया
- अल्पसंख्यक अधिकारों पर संविधान
- संयुक्त संसदीय समिति

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

पेज 18 – 20

- डिजाइन कानून संधि
- K-4 बैलिस्टिक मिसाइल
- टंगस्टन
- CE20 क्रायोजेनिक इंजन
- आइडियोपैथिक पलमोनेरी फ़ाइब्रोसिस
- वर्मम थेरेपी
- अगली पीढ़ी का डीएनए अनुक्रमण

विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां, सैन्य अभ्यास

पेज 21 – 22

- सारेक्स-**24**
- सबल-**20** लॉजिस्टिक्स ड्रोन
- अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ

अवसंरचना

पेज 23

- शहरी अवसंरचना विकास निधि

योजना

पेज 24 – 33

- वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना
- राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ)
- गेर्लफू माइंडफुलनेस सिटी (जीएमसी)
- पैन 2.0 परियोजना
- ग्लोबल मैचमेकिंग प्लेटफॉर्म
- "बाल विवाह मुक्त भारत अभियान"
- ई-दाखिल पोर्टल
- एकलव्य डिजिटल प्लेटफॉर्म
- शीस्टेम 2024
- पनडुब्बी केबल लचीलेपन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार निकाय
- पीएम ई-विद्या

RACE IAS

- रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप (RuTAG) पहल
- अमृत ज्ञान कोष पोर्टल
- बीमा सखी योजना
- ब्लूटूथ लो एनर्जी गेटवे
- डीएई- होमी भाभा चेयर योजना
- समर्थ उद्योग भारत 4.0 पहल
- चरक पहल
- विज्ञान और विरासत अनुसंधान पहल
- स्माइल कार्यक्रम
- बैगा जनजाति: जोधइया बाई
- भारत समुद्री विरासत सम्मेलन
- स्पीड गन
- डार्क पैटर्न
- पनामा नहर
- ऑर्डर ऑफ मुबारक अल-कबीर
- असंगठित क्षेत्र के उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण
- ग्रीनलैंड
- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार

विविध

पेज 34 – 47

- जापानी इन्सेफेलाइटिस
- कोरागा जनजाति
- अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 2024
- नाज़्का लाइन्स
- स्वगृह रेटिंग
- घरचोलस साड़ी
- भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम
- राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार
- मेली-एमिली
- भारत कौशल रिपोर्ट 2025
- उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण
- भौगोलिक संकेत टैग किए गए उत्पाद
- विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024
- रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024
- हाइपरलूप ट्रैक
- एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट (एबीपी)
- खोज और बचाव सहायता उपकरण (SARAT)
- राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार
- जलवाहक योजना
- शॉर्ट नेक क्लैम

RACE IAS

करेंट अफेयर्स

भूगोल, पर्यावरण और पारिस्थितिकी

ब्लैक थ्रिप्स

खबरों में क्यों?

एक वर्ष के अंतराल के बाद, कर्नाटक के बल्लारी में मिर्च की फसल में एक बार फिर खतरनाक ब्लैक थ्रिप्स का प्रकोप सामने आया है।

ब्लैक थ्रिप्स के बारे में:

- यह एक आक्रामक कीट प्रजाति है।
- भारत में इसकी पहली बार सूचना 2015 में पपीते पर दी गई थी।
- ये कीट कोमल पत्तियों और फूलों को चीरकर उनके ऊतकों को खा जाते हैं। चीरने से, खास तौर पर फूलों को, फल बनने में बाधा आती है।
- यह बहुभक्षी है, अर्थात् यह विभिन्न वनस्पति प्रजातियों को खा सकता है।
- यह कोमल फूलों को खाता है, बड़े पैमाने पर फूलों को गिराता है, फलों में बौनापन और विकृति पैदा करता है तथा मिर्च में फल गिर जाते हैं, जिससे उपज में भारी कमी आती है।
- मिर्च के अलावा यह कपास, शिमला मिर्च, लाल व काले चने, आम, तरबूज व अन्य फसलों को भी नुकसान पहुंचाता है।
- वर्ष 2015 से यह कीट कृषि, बागवानी और सजावटी फसलों दोनों को खा रहा है तथा आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा और तमिलनाडु में व्यापक रूप से फैला हुआ है।

भारत में इसके बढ़ने के कारण:

- कीट प्रजातियों के प्राकृतिक नियंत्रण के लिए आक्रमण के क्षेत्र में इस विशेष आक्रामक कीट के प्राकृतिक शत्रुओं की अनुपस्थिति तथा रासायनिक कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग और विलम्बित रोपण, उनके प्रकोप के संभावित कारण हैं।

स्रोत: द हिंदू बिजनेस लाइन

बार-टेल्ड गॉडविट

खबरों में क्यों?

एक असामान्य घटना में, हाल ही में एक प्रकृतिविज्ञानी ने पुलिकट झील में पांच बार-टेल्ड गॉडविट्स देखे।

बार-टेल्ड गॉडविट के बारे में:

- यह एक प्रवासी समुद्री पक्षी है जो प्रवास के दौरान अपनी असाधारण सहनशक्ति के लिए प्रसिद्ध है।
- वैज्ञानिक नाम: लिमोसा लैपोनिका

प्रजातियों का वितरण:

- बार-टेल्ड गॉडविट प्रजाति उत्तरी यूरोप और एशिया , पश्चिमी अलास्का, अफ्रीका, फारस की खाड़ी , भारत , दक्षिण-पूर्व एशिया, चीन और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है।
- ये गॉडविट प्रजातियां आर्कटिक क्षेत्र में प्रजनन करती हैं ।
- भारत में, शीत ऋतु में बार-टेल्ड गॉडविट प्रजाति गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है।
- बार-टेल्ड गॉडविट्स बिना रुके उड़ान भरने के लिए विश्व रिकॉर्ड धारक हैं । उन्हें अलास्का से तस्मानिया तक 13,500 किलोमीटर की यात्रा केवल 11 दिनों में 50 किमी/घंटा से अधिक की औसत गति से उड़ते हुए दर्ज किया गया है, और इस दौरान उनके शरीर का लगभग आधा वजन कम हो गया है।

प्रजातियों की विशेषताएँ:

- वे काफी बड़े जलचर हैं, जिनमें मादाएं नर से बड़ी होती हैं ।
- यह मुख्यतः ऊपर से धब्बेदार भूरा तथा नीचे से हल्का और अधिक एकसमान पीला रंग का होता है।
- इसके निचले पंख हल्के सफेद रंग के होते हैं तथा इसकी चोंच लम्बी तथा थोड़ी ऊपर की ओर उठी हुई होती है।
- जैसा कि नाम से पता चलता है, सफेद पूंछ भूरे रंग से धारीदार होती है ।
- आईयूसीएन रेड लिस्ट: निकट संकटग्रस्त

स्रोतः टाइम्स ऑफ इंडिया

WOH G64 स्टार

खबरों में क्यों?

हाल ही में, पहली बार वैज्ञानिकों ने WOH G64 तारे का ज़ूम करके चित्र लेने में सफलता प्राप्त की है, जो किसी अन्य आकाशगंगा में स्थित है।

RACE IAS

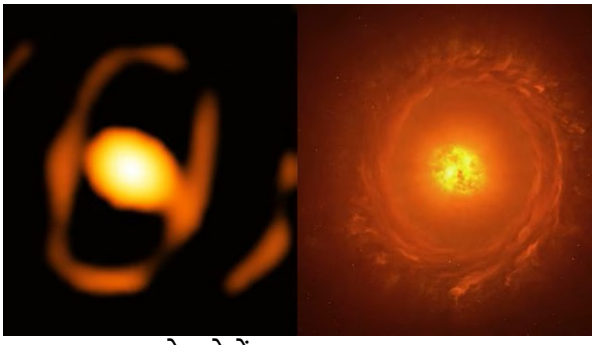

WOH G64 स्टार के बारे में:

- यह वह विशालकाय तारा है जिसका चित्र यूरोपीय दक्षिणी वेधशाला के वेरी लार्ज टेलिस्कोप इंटरफेरोमीटर (ईएसओ के वीएलटीआई) द्वारा उल्लेखनीय तीक्ष्णता के साथ लिया गया है ।
- यह बड़े मैगेलैनिक बादल में स्थित है , जो एक बौना या उपग्रह आकाशगंगा है जो हमारी आकाशगंगा की परिक्रमा करती है, जो हमारे सबसे निकट की आकाशगंगाओं में से एक है।
- इसकी खोज 1970 के दशक में बेंग्ट वेस्टरलंड्स, ओलैंडर और हेडिन ने की थी। संयोग से, इसके नाम में WOH इसके तीन खोजकर्ताओं के नामों का संक्षिप्त रूप है।
- ऐसा माना जाता है कि यह तारा पृथ्वी से लगभग 1,60,000 प्रकाश वर्ष दूर है ।
- अपने आकार के कारण इसे लाल महादानव तारा (रेड सुपरजाइंट) के रूप में वर्गीकृत किया गया है , जो सूर्य से लगभग 2,000 गुना बड़ा है।
- नई तस्वीर से पता चला है कि WOH G64 अपने जीवन के अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा है । हाल के वर्षों में, तारे की बाहरी परत उड़ गई है, और अब यह गैस और धूल की मालाओं और चापों से घिरा हुआ है।

मैगेलैनिक बादल क्या हैं?

- ये अनियमित आकाशगंगाएँ हैं जो एक गैसीय आवरण साझा करती हैं तथा दक्षिणी आकाशीय ध्रुव के पास आकाश में लगभग 22° की दूरी पर स्थित हैं।
- इनमें दो अनियमित आकाशगंगाएँ, बड़े मैगेलैनिक बादल (LMC) और छोटे मैगेलैनिक बादल (SMC) शामिल हैं , जो हर 1,500 मिलियन वर्ष में एक बार आकाशगंगा की परिक्रमा करते हैं और हर 900 मिलियन वर्ष में एक बार एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं।
- इन साथी आकाशगंगाओं का नाम पुर्तगाली नाविक फर्डिनेंड मैगेलन के नाम पर रखा गया था, जिनके दल ने विश्व की पहली यात्रा (1519-22) के दौरान इनकी खोज की थी।
- मैगेलैनिक बादलों का निर्माण लगभग उसी समय हुआ था जब मिल्की वे आकाशगंगा का निर्माण हुआ था, अर्थात लगभग 13 अरब वर्ष पहले।
- वे वर्तमान में मिल्की वे आकाशगंगा के चारों ओर की कक्षाओं में कैद हैं और एक दूसरे के साथ तथा आकाशगंगा के साथ कई बार ज्वार-भाटे का सामना कर चुके हैं।
- इनमें अनेक युवा तारे और तारा समूह हैं , साथ ही कुछ बहुत पुराने तारे भी हैं।

स्रोतः इंडियन एक्सप्रेस

रेड-ब्रेस्टेड फ्लाईकैचर

खबरों में क्यों?

हाल ही में, कठोर सर्दियों से बचने के लिए पूर्वी यूरोप से प्रवास करने वाला रेड-ब्रेस्टेड फ्लाईकैचर पक्षी हैदराबाद की अमीनपुर झील में पाया गया।

रेड-ब्रेस्टेड फ्लाईकैचर के बारे में:

- रेड-ब्रेस्टेड फ्लाईकैचर का वैज्ञानिक नाम फिसिडुला पर्व है।
- यह ओल्ड वर्ल्ड फ्लाईकैचर परिवार का एक छोटा (11-12 सेमी) गौरैया पक्षी है।
- इसे कभी-कभी हमारे शहरी उद्यानों में अंजीर (बरगद, पीपल) खाते हुए देखा जा सकता है।
- **स्वरूप:** नर का गला लाल-नारंगी होता है जो ऊपरी स्तन तक फैला होता है, जबकि मादा का रंग समग्रतः भूरा होता है।
- उन्हें अन्य आदेशों से उनके पंजों की व्यवस्था से अलग किया जा सकता है - तीन आगे की ओर और एक पीछे की ओर, एक ऐसा डिजाइन जो उन्हें शाखाओं पर कुशलतापूर्वक चिपके रहने में मदद करता है।
- यह आमतौर पर पूर्वी यूरोप से वहां की कठोर सर्दियों से बचने के लिए प्रवास करता है और दक्षिण एशिया में प्रचुर मात्रा में भोजन के साथ मध्यम तापमान का आनंद लेता है।
- **प्रजनन:** यह पक्षी पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया के पर्णपाती मिश्रित जंगलों में वसंत से गर्मियों तक प्रजनन करता है । सर्दियों के महीनों (ज्यादातर सितंबर से मार्च) में , यह भारतीय उपमहाद्वीप के जंगलों, वुडलैंड्स, बागों, पार्कों और सड़क के किनारे के पेड़ों की ओर पलायन करता है।
- यह प्रायद्वीपीय भारत में अक्टूबर से मार्च तक शीत ऋतु के दौरान पाया जा सकता है।

संरक्षण की स्थिति

- आईयूसीएन: कम चिंताजनक

स्रोत: द हिंदू

एंथ्रेक्स

खबरों में क्यों?

हाल ही में बांदीपुर टाइगर रिजर्व में संदिग्ध एंथ्रेक्स के कारण एक मादा हाथी की मौत हो गई।

एंथ्रेक्स के बारे में:

- एंथ्रेक्स एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी है जो बीजाणु बनाने वाले जीवाणु, बैसिलस एन्थ्रेसिस के कारण होती है।

- यह दुनिया भर की मिट्टी में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है और आम तौर पर पशुओं और जंगली जानवरों को प्रभावित करता है। बैक्टीरिया बीजाणु पैदा करते हैं जो सालों तक जमीन में रह सकते हैं ।

रोग का संचरण :

- पशुधन और जंगली जानवर संक्रमित हो सकते हैं जब वे दूषित मिट्टी, पौधों या पानी में मौजूद जीवाणुओं के बीजाणुओं को सांस के माध्यम से अंदर लेते हैं, खाते हैं या पीते हैं ।
- आमतौर पर लोग एंथ्रेक्स से बीमार हो जाते हैं यदि वे संक्रमित जानवरों या दूषित पशु उत्पादों के संपर्क में आते हैं।
- लोग भोजन , पानी या मिट्टी के माध्यम से भी सीधे बीजाणुओं से संक्रमित हो सकते हैं।
- एंथ्रेक्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, लेकिन त्वचा के घाव संपर्क से संक्रामक हो सकते हैं ।
- मनुष्यों में संक्रमण प्रायः त्वचा, जठरांत्र मार्ग या फेफड़ों को प्रभावित करता है।
- संक्रमण के मार्ग के आधार पर यह रोग तीन रूपों में प्रकट होता है : त्वचीय, जठरांत्रीय, और श्वसन।
- **लक्षण**: प्रकार के आधार पर, लक्षण इस प्रकार हैं:
  - ○सीने में दर्द और सांस लेने में परेशानी।
  - ○बुखार और अत्यधिक पसीना आना।
  - ○सिरदर्द या मांसपेशियों में दर्द।
  - ○खुजली वाले छाले या गांठें।
  - ○त्वचा का अल्सर (घाव) जिसका केंद्र काला हो ।
  - ○मतली और उल्टी, पेट दर्द, और खूनी दस्त।
  - ○सूजी हुई लिम्फ नोड्स |

रोग का उपचार:

- एंटीबायोटिक उपचार प्रभावी है । डॉक्सीसाइक्लिन, एमोक्सिसिलिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन आदि आमतौर पर उपचार के लिए उपयोग किए जाते हैं।
- एंथ्रेक्स के विरुद्ध टीकाकरण की सिफारिश केवल जोखिम वाले व्यक्तियों के लिए की जाती है , जैसे कि एंथ्रेक्स प्रभावित क्षेत्रों में काम करने वाले लोग।

स्रोतः टाइम्स ऑफ इंडिया

सुबाबुल वृक्ष

खबरों में क्यों?

शोधकर्ताओं ने टाइप II मधुमेह से संबंधित इंसुलिन प्रतिरोध के प्रबंधन में पारंपरिक औषधीय पौधे सुबाबुल के बीज की चिकित्सीय क्षमता की पहचान की है और इससे एक मार्कर-सहायता प्राप्त अंश और चार सक्रिय यौगिक विकसित किए हैं।

सुबाबुल वृक्ष के बारे में:

- यह एक तेजी से बढ़ने वाला फलीदार वृक्ष है जो सामान्यतः उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है ।
- यह मेक्सिको से उत्पन्न होने वाला एक छोटा, बारहमासी, काष्ठीय, अत्यधिक शाखाओं वाला से लेकर मध्यम आकार का वृक्ष है जिसके तने छोटे और स्पष्ट होते हैं।
- इसे बागानों में आवरण फसल के रूप में तथा चारे और ईंधन के लिए उगाया गया था।
- यह मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा और तमिलनाडु में पाया जाता है ।
- पत्तियों और अपरिपक्व बीजों को सूप या सलाद के रूप में कच्चा और पकाकर खाया जाता है, जिससे प्रोटीन और फाइबर का समृद्ध स्रोत मिलता है, जिसके कारण विभिन्न जातीय समुदायों द्वारा मानव और पशु भोजन में इसका पारंपरिक उपयोग किया जाता है।
- यह अपनी लकड़ी के लिए मूल्यवान है , जिसका उपयोग अच्छी गुणवत्ता वाले चारकोल, छोटे फर्नीचर और कागज की लुगदी बनाने के लिए किया जाता है।

मधुमेह क्या है?

- यह एक दीर्घकालिक रोग है जो या तो तब होता है जब अग्न्याशय पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है या जब शरीर अपने द्वारा उत्पादित इंसुलिन का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर पाता है।
- इंसुलिन एक हार्मोन है जो रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है।
- टाइप 2 डायबिटीज़: इस स्थिति में मानव शरीर इंसुलिन का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाता और रक्त शर्करा को सामान्य स्तर पर नहीं रख पाता। यह कई वर्षों में विकसित होता है और आमतौर पर वयस्कों में इसका निदान किया जाता है (लेकिन बच्चों, किशोरों और युवा वयस्कों में यह अधिक होता है)।

स्रोत: पीआईबी

केप भैंस

खबरों में क्यों?

तंजानिया के नगोरोंगोरो संरक्षण क्षेत्र (एनसीए) के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक अध्ययन ने उप-सहारा अफ्रीका में होने वाले मानव-केप भैंसा संघर्ष के पीछे के कारणों के बारे में जानकारी प्रदान की है।

केप भैंस के बारे में:

- अफ्रीकी या केप भैंसा (सिंसेरस कैफ़र) एक दुर्जेय और आक्रामक प्रजाति है।
- यह सहारा के दक्षिण में पाई जाने वाली अफ्रीकी भैंस की चार उप-प्रजातियों में से एक है, अन्य उप-प्रजातियां हैं वन भैंस, पश्चिम अफ्रीकी सवाना भैंस और मध्य अफ्रीकी सवाना भैंस।
- विशेषताएं:

○अन्य बड़े बोविड्स की तुलना में, अफ्रीकी भैंसों का शरीर लंबा लेकिन गठीला तथा पैर छोटे लेकिन मोटे होते हैं, जिसके कारण खड़े होने पर उनकी ऊंचाई अपेक्षाकृत कम होती है।
○वयस्क भैंस के सींग इसकी विशिष्ट विशेषता हैं : उनके आधार जुड़े हुए होते हैं, जो सिर के शीर्ष पर एक सतत अस्थि कवच बनाते हैं जिसे "बॉस" कहा जाता है।

- वितरण: केप भैंसा पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका के सवाना में पाया जाता है।
- निवास स्थान: वे दलदलों और बाढ़ के मैदानों के साथ-साथ मोपेन घास के मैदानों और अफ्रीका के प्रमुख पहाड़ों के जंगलों में रहते हैं।
- वे घने आवरण वाले आवास को पसंद करते हैं, जैसे नरकट और झाड़ियाँ, लेकिन वे खुले वनों, पर्वतीय घास के मैदानों, तथा जंगलों, सवाना और नम निचले वर्षावनों में भी पाए जा सकते हैं।
- अफ्रीकी भैंस दिन और रात भर सक्रिय रह सकती हैं । वे सामाजिक हैं और झुंड में रहते हैं जिसमें संबंधित मादाएं और उनकी संतानें शामिल होती हैं, जो लगभग रैखिक प्रभुत्व पदानुक्रम में होती हैं।
- आहार: अफ्रीकी भैंस पूरी तरह शाकाहारी होते हैं । वे विभिन्न प्रकार की घास, सेज, पत्ते और अन्य पौधे खाते हैं।
- ये विशालकाय जानवर उत्कृष्ट तैराक भी होते हैं और अक्सर बेहतर चारा की तलाश में नदियों को पार करते हैं।
- संरक्षण की स्थिति
  ○आईयूसीएन: निकट संकटग्रस्त

स्रोत: डाउन टू अर्थ

एनएचएआई ठेकेदार रेटिंग प्रणाली

खबरों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास और रखरखाव में लगे रियायतग्राहियों के प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए एक व्यापक रेटिंग प्रणाली शुरू की है।

एनएचएआई ठेकेदार रेटिंग प्रणाली के बारे में :

- यह एनएचएआई द्वारा रियायतदाताओं की रेटिंग के लिए एक विस्तृत पद्धति तैयार की गई है।
- इसके तहत हर छह महीने में रियायतकर्ताओं का मूल्यांकन किया जाएगा और रेटिंग एनएचएआई की वेबसाइट और उसके सोशल मीडिया हैंडल पर अपलोड की जाएगी।

मूल्यांकन पद्धति:

- मूल्यांकन फुटपाथ स्थिति सूचकांक (पीसीआई) के साथ-साथ एनएचएआई वन ऐप पर दोष सुधार अनुपालन पर आधारित होगा , जहां 95 से अधिक दोषों को अधिसूचित किया जा सकता है और डिजिटल रूप से निगरानी भी की जा सकती है, जो रेटिंग मूल्यांकन का एक हिस्सा होगा।
- एनएचएआई वन ऐप पर पीसीआई को 80 प्रतिशत तथा अनुपालन को 20 प्रतिशत महत्व दिया जाएगा।
- आईआरसी 82:2023 दिशानिर्देशों के अनुसार, पीसीआई, 0 से 100 तक का एक वैज्ञानिक मीट्रिक है , जो फुटपाथ की स्थिति को ' उत्कृष्ट' से 'विफल' तक दर्शाता है।
- पीसीआई की गणना छह कार्यात्मक मापदंडों के आधार पर की जाएगी
- मूल्यांकित 'कंसेशनेयर रेटिंग वैल्यू' के अनुसार, कंसेशनेयर्स को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा।
- 100 में से 70 से कम रेटिंग प्राप्त करने वाले ठेकेदारों को 'गैर-निष्पादक' घोषित कर दिया जाएगा , इस प्रकार वे अपनी रेटिंग में सुधार होने तक नई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं प्राप्त करने के लिए अयोग्य हो जाएंगे।
- रियायतग्राहियों का मूल्यांकन दो स्तरों पर किया जाएगा , पहला व्यक्तिगत परियोजना स्तर पर और दूसरा रियायतग्राही स्तर पर।
- परियोजना स्तर पर रेटिंग मूल्य के साथ-साथ संयुक्त रियायतकर्ता रेटिंग मूल्य की समीक्षा हर 6 महीने में एनएसवी सर्वेक्षण के प्रत्येक चक्र के साथ की जाएगी। रेटिंग मूल्य की गणना के लिए एनएचएआई वन ऐप पर दोष सुधार अनुपालन से संबंधित डेटा का भी उपयोग किया जाएगा।

महत्व:

- इससे जवाबदेही बढ़ेगी तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और रखरखाव की गुणवत्ता का आकलन होगा।
- इससे राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित, सुगम और निर्बाध यात्रा का अनुभव मिलेगा।

स्रोत: पीआईबी

नोवा

खबरों में क्यों?

भारतीय खगोलभौतिकी संस्थान (आईआईए) के खगोलविदों ने पड़ोसी एंड्रोमेडा आकाशगंगा में पहली बार नोवा से सुदूर पराबैंगनी (एफयूवी) उत्सर्जन देखा है।

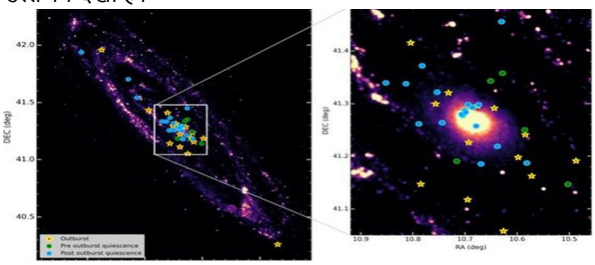

नोवा के बारे में:

- यह एक विशेष प्रकार की क्षणिक खगोलीय घटना है , जिसके कारण एक चमकदार, स्पष्टतः नया तारा अचानक प्रकट होता है, जो अपने विस्फोट के दौरान, कुछ सप्ताहों या महीनों में धीरे-धीरे लुप्त हो जाता है।
- नोवा द्वितारा प्रणालियों में पाया जाता है , जहां एक घना, पृथ्वी के आकार का सफेद बौना तारा, सूर्य जैसे साथी के साथ निकटता से परिक्रमा करता है।

- श्वेत वामन का प्रबल गुरुत्वाकर्षण बल उसके साथी से पदार्थ को खींच लेता है, जिससे उसकी सतह पर पदार्थों का अत्यधिक संचय हो जाता है।
- इस प्रक्रिया से शक्तिशाली तापनाभिकीय अभिक्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं, जिससे अचानक एक चमकीला विस्फोट उत्पन्न होता है, जो नवतारा के रूप में दिखाई देता है।
- एक नोवा अपने विस्फोट के कुछ घंटों के भीतर अधिकतम चमक तक पहुंच जाता है और कई दिनों तक तीव्रता से चमक सकता है

अनुसंधान का महत्व:

- शोधकर्ताओं ने 42 नोवा (तारों के एक विशेष वर्ग) से पराबैंगनी उत्सर्जन की खोज की , तथा उनमें से चार को विस्फोट की क्रिया में ही पकड़ भी लिया।
- इससे वैज्ञानिकों को हमारे निकटतम पड़ोसी आकाशगंगा में इन परस्पर क्रियाशील द्वितारा प्रणालियों के जीवन के विभिन्न चरणों का अध्ययन करने में सहायता मिल सकती है , जिनमें से कुछ अपने साथी आकाशगंगा से पदार्थ एकत्रित करते हैं, जबकि अन्य इसे अंतरिक्ष में फेंक देते हैं।

एंड्रोमेडा आकाशगंगा के बारे में:

- एंड्रोमेडा आकाशगंगा, जिसे मेसियर 31 या M31 भी कहा जाता है , आकाशगंगा की सबसे निकटतम प्रमुख आकाशगंगा है।
- यह पृथ्वी से 5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है और स्थानीय समूह, आकाशगंगाओं के हमारे स्थानीय संग्रह का दूसरा प्रमुख सदस्य है।
- आकाशगंगा की तरह, यह एक पट्टीदार सर्पिल आकाशगंगा है , जिसे इसके केंद्र में तारों द्वारा बनाई गई पट्टीनुमा संरचना के कारण ऐसा कहा जाता है

स्रोत: द हिंदू

भारतीय स्टार कछुआ

खबरों में क्यों?

हाल ही में, शोधकर्ताओं ने भारतीय स्टार कछुआ प्रजातियों के दो आनुवंशिक रूप से अलग समूहों की पहचान की है, अर्थात् उत्तर-पश्चिमी और दक्षिणी।

भारतीय स्टार कछुए के बारे में :

- इसका नाम इसके ऊंचे गुम्बददार खोल पर बने तारे जैसे पैटर्न के कारण पड़ा है।
- इसके बहुत ही विशिष्ट पैटर्न हैं और इसका अत्यधिक गोलाकार खोल इसे विदेशी पालतू जानवरों के विश्व व्यापार में लोकप्रिय बनाता है।

स्टार कछुए का प्राकृतिक वास:

- वे विभिन्न प्रकार के आवासों में निवास करते हैं, जिनमें अर्ध-शुष्क निचले वन, कांटेदार झाड़ीदार वन, अर्ध-रेगिस्तान और शुष्क घास के मैदान शामिल हैं ।
- इस प्रजाति में मौसमी नमी या सूखे आवासों के प्रति उच्च सहनशीलता होती है, तथा इसकी कई प्रजातियां ऐसे क्षेत्रों में निवास करती हैं जहां मानसून या बरसात का मौसम होता है, जिसके बाद लंबी गर्म और शुष्क अवधि होती है।
- यह उपमहाद्वीप के लिए स्थानिक है और उत्तर-पश्चिम भारत (पाकिस्तान की सीमा), दक्षिण भारत और श्रीलंका के शुष्क इलाकों में पाया जाता है। हालाँकि, इस प्रजाति के सदस्य कनाडा और अमेरिका जैसे दूर-दराज के इलाकों में भी लोगों के घरों में पाए गए हैं।
- यह आमतौर पर सांध्यकालीन होता है, जिसका अर्थ है कि वे शुष्क, गर्म मौसम के दौरान सुबह जल्दी और देर दोपहर में सक्रिय होते हैं।
- भारतीय स्टार कछुए मुख्य रूप से शाकाहारी होते हैं और ज्यादातर घास, शाकीय पत्तियां, फूल आदि खाते हैं।
- **संरक्षण की स्थिति:**
  - ○आईयूसीएन: संवेदनशील
  - ○सीआईटीईएस: परिशिष्ट ।
  - ○वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972: अनुसूची ।
- खतरे: इस प्रजाति के अत्यधिक खंडित आवास पर, इसके पूरे क्षेत्र में शहरीकरण और कृषि पद्धतियों के बढ़ते स्तर का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है।

स्रोत: द हिंदू

जेनकास्ट मॉडल

खबरों में क्यों?

गूगल डीपमाइंड शोधकर्ताओं द्वारा नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक शोध पत्र के अनुसार, जेनकास्ट नामक एक नया मशीन-लर्निंग मौसम पूर्वानुमान मॉडल कम से कम कुछ स्थितियों में सर्वोत्तम पारंपरिक पूर्वानुमान प्रणालियों से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है।

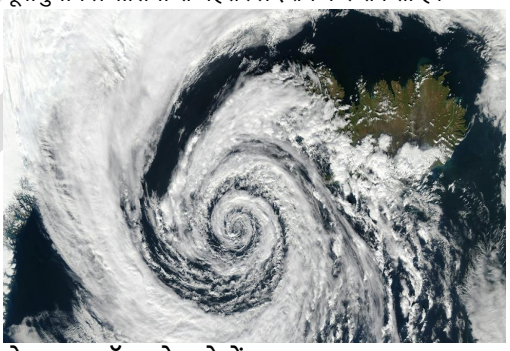

जेनकास्ट मॉडल के बारे में:

- यह एक नया मशीन-लर्निंग मौसम पूर्वानुमान मॉडल है।
- यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) छवि जनरेटर के समान प्रसार मॉडल दृष्टिकोण का उपयोग करता है ।
- यह सिस्टम वायुमंडल के जटिल व्यवहार को पकड़ने के लिए कई पूर्वानुमान तैयार करता है । यह पारंपरिक तरीकों के लिए आवश्यक समय और कंप्यूटिंग संसाधनों के एक अंश के साथ ऐसा करता है।
- यह गूगल के अगली पीढ़ी के AI-आधारित मौसम मॉडल के बढ़ते समूह का एक हिस्सा है।
- यह केवल 8 मिनट में 15 दिनों के मौसम का पूर्वानुमान लगा सकता है । मौसम का पूर्वानुमान लगाने के पारंपरिक तरीके में आमतौर पर घंटों का समय लगता है।

जेनकास्ट मॉडल का कार्य:

- एआई-संचालित कार्यक्रम को 2018 तक के चार दशकों के ऐतिहासिक आंकड़ों पर प्रशिक्षित किया गया था , जिसे यूरोपीय मध्यम-अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र (ईसीएमडब्ल्यूएफ) के ऐतिहासिक अभिलेखागार से लिया गया था।
- जेनकास्ट मॉडल सतह पर तथा 13 विभिन्न ऊंचाइयों पर तापमान, दबाव, आर्द्रता और वायु की गति जैसे कई चरों के

बारे में पूर्वानुमान लगाता है, तथा एक ग्रिड पर विश्व को 0.25 डिग्री अक्षांश और देशांतर क्षेत्रों में विभाजित करता है।

- महत्व: यह वर्तमान अग्रणी प्रणाली से बेहतर प्रदर्शन करता है, संभावित मौसम परिदृश्यों की एक श्रृंखला की भविष्यवाणी करने के लिए संभाव्यता समूह पूर्वानुमान का उपयोग करता है, तथा आगामी परिस्थितियों की अधिक व्यापक तस्वीर पेश करता है।

स्रोत: द हिंदू

इंडियन रॉक पायथन

खबरों में क्यों?

ऐसा माना जाता है कि भारतीय रॉक पायथन प्रजाति पूरे तमिलनाडु में कम हो गई है, सिवाय मोयार घाटी के, जहां अजगर पनप रहे हैं।

इंडियन रॉक पायथन के बारे में :

- यह एक बड़ी, विषहीन अजगर प्रजाति है।
- इसे सामान्यतः ब्लैक-टेल्ड पाइथन और एशियन रॉक पाइथन के नाम से जाना जाता है।

इंडियन रॉक पायथन की उपस्थिति:

- भारतीय अजगर आमतौर पर सफेद या पीले रंग के होते हैं, जिनमें धब्बेदार पैटर्न भूरे से गहरे भूरे रंग के होते हैं।
- यह भूभाग और आवास के अनुसार बदलता रहता है। पश्चिमी घाट और असम के पहाड़ी जंगलों से प्राप्त नमूने गहरे रंग के होते हैं, जबकि दक्कन के पठार और पूर्वी घाट से प्राप्त नमूने आमतौर पर हल्के रंग के होते हैं।
- निवास स्थान: वे निवास स्थान की एक विस्तृत श्रृंखला में रहते हैं, जिसमें घास के मैदान और सवाना, दलदल, दलदली भूमि , चट्टानी तलहटी, वुडलैंड्स, खुले जंगल और नदी घाटियाँ शामिल हैं
- वितरण: भारतीय अजगर भारत, दक्षिणी नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश और संभवतः म्यांमार के उत्तर में पाए जाते हैं।
- वे रात्रिचर और मुख्य रूप से स्थलीय जीव हैं। हालांकि, वे बहुत अच्छे पर्वतारोही भी हैं और अक्सर पेड़ों की शाखाओं पर लटके हुए देखे जा सकते हैं। भारतीय अजगर बेहतरीन तैराक होते हैं।
- संरक्षण की स्थिति
  - ○आईयूसीएन: निकट संकटग्रस्त
  - ○सीआईटीईएस: परिशिष्ट II
- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची I।
- खतरे : आवास का विनाश और अवैध व्यापार

स्रोत: द हिंदू

डुलसिबेला कैमंचाका

खबरों में क्यों?

चिली के कन्सेप्सिओन विश्वविद्यालय और अमेरिका के वुड्स होल ओशनोग्राफिक इंस्टीट्यूशन के शोधकर्ताओं ने अटाकामा ट्रेंच में डुल्सिबेला कैमंचाका की खोज की है।

डुलसिबेला कैमंचाका के बारे में :

- यह एक नई शिकारी उभयपाद प्रजाति है।
- यह अटाकामा ट्रेंच में 7,902 मीटर की गहराई पर पाया गया था ।
- इसे यूसिरिडे परिवार में वर्गीकृत किया गया है और यह एक नव-पहचानी गई प्रजाति का प्रतिनिधित्व करता है, जो गहरे समुद्र की जैव विविधता की सूची में एक महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाता है।

डुलसिबेला कैमंचाका की विशेषताएँ:

- इसका आकार 4 सेंटीमीटर से थोड़ा कम है और यह अपने निकटतम रिश्तेदारों से बड़ा है तथा इसमें अनोखी विशेषताएं हैं, जैसे कि ग्नैथोपोड्स नामक शिकारी उपांग , जो छोटे जीवों के शिकार के लिए उपयोग किए जाते हैं।
- खाइयों में सामान्यतः पाए जाने वाले अपमार्जक उभयचरों के विपरीत, यह प्रजाति सक्रिय रूप से अन्य उभयचरों का शिकार करती है, तथा गहरे समुद्र के खाद्य जाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- यह एक तेज गति से तैरने वाला शिकारी पक्षी है , जिसका नाम हमने एंडीज क्षेत्र के लोगों की भाषा में 'अंधकार' के नाम पर रखा है।
- इसका रंग हल्का पीला है, जो गहरे समुद्र में रहने वाली प्रजातियों में पाया जाने वाला एक सामान्य गुण है, जो इसके घने अंधेरे वातावरण में पनपने की क्षमता को बढ़ाता है।

अटाकामा ट्रेंच के बारे में मुख्य बातें

- अटाकामा ट्रेंच पूर्वी दक्षिण प्रशांत महासागर के साथ-साथ फैली हुई है, जो उत्तरी चिली के तट से 8,000 मीटर से अधिक गहराई तक फैली हुई है ।
- यह हडल क्षेत्र का हिस्सा है , जो तीव्र दबाव, लगभग शून्य तापमान और पूर्ण अंधकार से युक्त क्षेत्र है ।
- यह भौगोलिक दृष्टि से सबसे अलग-थलग हडल संरचनाओं में से एक है और यह यूट्रोफिक सतही जल के नीचे स्थित है तथा इसकी विशेषता उच्च तलछट भार है।

स्रोत: द इकोनॉमिक टाइम्स

डार्क कॉमेट्स

खबरों में क्यों?

नासा के वैज्ञानिक "डार्क कॉमेट्स" के नाम से जाने जाने वाले खगोलीय पिंडों के एक नए वर्ग का बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं।

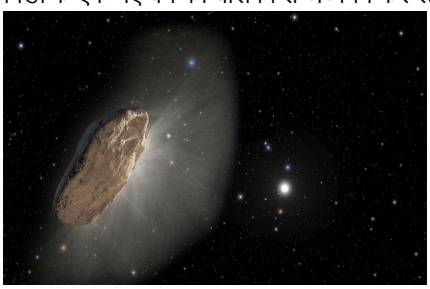

डार्क कॉमेट्स के बारे में:

- ये ऐसे खगोलीय पिंड हैं जिनमें चमकदार पूंछ नहीं होती (जो धूमकेतुओं की एक विशिष्ट विशेषता है) और ये क्षुद्रग्रहों जैसे दिखते हैं।
- वे प्रायः छोटे होते हैं, कुछ मीटर से लेकर कुछ सौ मीटर तक चौड़े।
- इनमें पदार्थ के बाहर निकलने तथा सामान्य धूमकेतुओं पर दिखाई देने वाली सुन्दर पूंछ बनाने के लिए सतही क्षेत्रफल कम होता है।
- लेकिन अचानक गति होने के कारण वे क्षुद्रग्रह नहीं हैं।
- वे प्रायः काफी तेजी से घूमते हैं और बची हुई गैस और धूल को सभी दिशाओं में फैला देते हैं, जिससे वे कम दिखाई देते हैं।
- वे लम्बे, अण्डाकार पथों का अनुसरण करते हैं जो उन्हें सूर्य के करीब लाते हैं और फिर सौरमंडल के सुदूरतम क्षेत्रों की ओर वापस लौट जाते हैं।
- अंधकारमय धूमकेतुओं का पहला संकेत 2016 में मिला , जब क्षुद्रग्रह 2003 आरएम ने असामान्य कक्षीय विचलन प्रदर्शित किया।
- तब से, खगोलविदों ने अंधकारमय धूमकेतुओं के अस्तित्व की पुष्टि की है, तथा एक नया अध्ययन प्रकाशित हुआ है जिसमें 14 ऐसे धूमकेतुओं का पता चला है।
- ये धूमकेतु दो मुख्य श्रेणियों में आते हैं: "बाहरी अंधकारमय धूमकेतु", जिनकी कक्षाएँ विलक्षण होती हैं और वे बड़े होते हैं, और "आंतरिक अंधकारमय धूमकेतु", जो छोटे होते हैं और सूर्य के करीब होते हैं, तथा जिनकी कक्षाएँ लगभग वृत्ताकार होती हैं।

स्रोत: द हिंदू

कैलीप्टोसेफेलेला गेई

खबरों में क्यों?

जलवायु परिवर्तन और मानवीय हस्तक्षेप के कारण विशालकाय मेंढक प्रजाति कैलीप्टोसेफैलेला गेई अब अपने मूल स्थान चिली में अपना अस्तित्व खो रही है, क्योंकि इसके प्राकृतिक आवास को नुकसान पहुंच रहा है।

कैलीप्टोसेफैलेला गेई के बारे में:

- यह दुनिया के सबसे बड़े मेंढकों में से एक है, जिसकी लंबाई 30 सेमी (1 फुट) से अधिक तथा वजन 1 किलोग्राम (2.2 पाउंड) तक होता है।
- इसे हेलमेटेड वॉटर टॉड के नाम से भी जाना जाता है जो डायनासोर के साथ-साथ उछलता था और इसे " जीवित जीवाश्म" माना जाता है।
- **विशेषताएं**: यह एक मजबूत प्रजाति है जिसका सिर चौड़ा और मुंह बड़ा होता है। यह बहुत बड़ा होता है, और नर में थूथन से वेंट तक की लंबाई 15.5 सेमी (6 इंच) और मादा में 32 सेमी (13 इंच) तक हो सकती है।
- निवास स्थान: वे जलीय वातावरण जैसे झीलों, नदियों और तालाबों में रहते हैं ।
- वितरण: वे चिली के निचले इलाकों में 500 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं।
- **संरक्षण की स्थिति**
  - ○आईयूसीएन: संवेदनशील
- खतरे: जलवायु परिवर्तन, आवास में बाधा, पर्यावरणीय गिरावट और प्रदूषण जैसे कारकों के कारण हेलमेटेड वॉटर टॉड की संख्या में कमी आई है।

स्रोत: द हिंदू

शेर-पूंछ वाला मकाक

खबरों में क्यों?

एक हालिया अध्ययन में मानव-वन्यजीव संपर्क में वृद्धि के कारण शेर-पूंछ वाले मैकाक जैसे गैर-मानव प्राइमेट्स के लिए बढ़ते खतरे की चेतावनी दी गई है।

शेर-पूंछ वाले मकाक के बारे में :

- यह एक लुप्तप्राय प्राइमेट प्रजाति है जो भारत के पश्चिमी घाट के सदाबहार वर्षा वनों में पाई जाती है और इसका क्षेत्र कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के तीन राज्यों से होकर गुजरता है।
- इसे वान्डेरू के नाम से भी जाना जाता है, यह एक पुरानी दुनिया का बंदर है।
  ○पुरानी दुनिया के बंदर सेरकोपिथेसिडे परिवार के प्राइमेट हैं। इनमें बबून, लाल कोलोबस और मैकाक शामिल हैं।
- यह एक वृक्षीय और दिनचर प्राणी है , वे रात में पेड़ों पर सोते हैं (आमतौर पर, वर्षावन की छतरी के नीचे)।
- यह प्रादेशिक और बहुत ही मिलनसार जानवर है । इस प्रजाति की एक विशिष्ट विशेषता यह है कि नर अपनी घरेलू सीमाओं की सीमाओं को कॉल द्वारा परिभाषित करते हैं।
- कुल मिलाकर, उनकी संचार प्रणाली में 17 स्वर शामिल हैं।
- केरल के पालघाट के पहाड़ों में लगभग 40 किलोमीटर के अंतराल पर वे दो उप-आबादियों में विभाजित हैं ।
- यह सर्वाहारी है और विभिन्न प्रकार के भोजन खाता है, हालांकि फल इनके आहार का प्रमुख हिस्सा होते हैं।
- शानदार शेर-पूंछ वाले मैकाक का नाम इसकी शेर जैसी, लंबी, पतली और गुच्छेदार पूंछ के कारण रखा गया है। इसके अलावा, उनके चेहरे के चारों ओर भूरे रंग के अयाल भी उनकी पहचान हैं।
- इस बीच, यह जानवर दुनिया की सबसे छोटी मैकाक प्रजातियों में से एक है।
- **संरक्षण की स्थिति:**
  ○आईयूसीएन: लुप्तप्राय
  ○सीआईटीईएस: परिशिष्ट ।
  ○वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची ।
- खतरे: यह प्राइमेट्स में सबसे अधिक खतरे में है, पश्चिमी घाट में स्थानिक है। इसकी आबादी को आवास की कमी, विखंडन और मानव अतिक्रमण से खतरा है।

स्रोत: द हिंदू

संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग

खबरों में क्यों?

हाल ही में, भारत को 2025-2026 के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग (पीबीसी) में पुनः चुना गया है।

संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग के बारे में:

- इसकी स्थापना 20 दिसंबर 2005 को संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों द्वारा की गई थी।
- इसकी वेबसाइट के अनुसार, यह एक अंतर-सरकारी सलाहकार निकाय है जो संघर्ष प्रभावित देशों में शांति प्रयासों का समर्थन करता है तथा व्यापक शांति एजेंडे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की क्षमता में महत्वपूर्ण योगदान देता है।
- पीबीसी में 31 सदस्य देश शामिल हैं, जो महासभा, सुरक्षा परिषद और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद से चुने जाते हैं।
- संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में सर्वाधिक वित्तीय योगदान देने वाले देश तथा सर्वाधिक सैन्य योगदान देने वाले देश भी इसके सदस्य हैं।
- भारत संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में वर्दीधारी कार्मिक भेजने वाले सबसे बड़े देशों में से एक है।
- वर्तमान में इसने अबेई, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, साइप्रस, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, लेबनान, मध्य पूर्व, सोमालिया, दक्षिण सूडान और पश्चिमी सहारा में संयुक्त राष्ट्र अभियानों के लिए लगभग 6,000 सैन्य और पुलिस कर्मियों को तैनात किया है।

आयोग को अधिदेशित किया गया:

- संसाधनों को संगठित करने के लिए सभी प्रासंगिक पक्षों को एक साथ लाना तथा संघर्ष के बाद शांति स्थापना और पुनर्प्राप्ति के लिए एकीकृत रणनीतियों पर सलाह देना और प्रस्ताव देना;
- संघर्ष से उबरने के लिए आवश्यक पुनर्निर्माण और संस्था निर्माण प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना तथा सतत विकास की नींव रखने के लिए एकीकृत रणनीतियों के विकास का समर्थन करना।
- संयुक्त राष्ट्र के भीतर और बाहर सभी प्रासंगिक अभिनेताओं के समन्वय को बेहतर बनाने के लिए सिफारिशें और जानकारी प्रदान करना,
- आयोग ने कहा कि इसका उद्देश्य सर्वोत्तम प्रथाओं का विकास करना, शीघ्र पुनर्प्राप्ति गतिविधियों के लिए पूर्वानुमानित वित्तपोषण सुनिश्चित करने में सहायता करना तथा संघर्षोपरांत पुनर्प्राप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा दिए जाने वाले ध्यान की अवधि को बढ़ाना है।
- आयोग शांति निर्माण के लिए एक एकीकृत, रणनीतिक और सुसंगत दृष्टिकोण को बढ़ावा देने पर भी ध्यान केंद्रित करता है।

स्रोत: द हिंदू

अभ्यास सिनबाक्स (CINBAX)

खबरों में क्यों?

संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास, सिनबाक्स का पहला संस्करण विदेशी प्रशिक्षण नोड, पुणे में शुरू हुआ।

अभ्यास सिनबाक्स (CINBAX) के बारे में:

- यह अभ्यास भारतीय सेना और कम्बोडियाई सेना के बीच आयोजित किया जाता है।
- इसका उद्देश्य संयुक्त आतंकवाद निरोधी (सीटी) अभियान चलाना है।
- इसमें खुफिया, निगरानी और टोही के लिए संयुक्त प्रशिक्षण कार्य बल की स्थापना के अलावा सीटी वातावरण में संचालन की योजना से संबंधित चर्चाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- अभ्यास में सूचना संचालन, साइबर युद्ध, हाइब्रिड युद्ध, रसद और हताहत प्रबंधन, एचएडीआर संचालन पर भी चर्चा शामिल होगी।
- इस अभ्यास में भारतीय मूल के हथियारों और उपकरणों का प्रदर्शन भी किया जाएगा, जो रक्षा उत्पादन में 'आत्मनिर्भरता' और स्वदेशी क्षमताओं को बढ़ावा देंगे।
- यह तीन चरणों में आयोजित किया जाएगा।
  - ○चरण-I में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों के दौरान सीटी संचालन के लिए प्रतिभागियों की तैयारी और अभिविन्यास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
  - ○चरण-II में टेबल टॉप अभ्यास का आयोजन शामिल होगा
  - ○चरण-III में योजनाओं को अंतिम रूप देना और सारांश तैयार करना शामिल होगा। इससे थीम-आधारित प्रशिक्षण के व्यावहारिक पहलू सामने आएंगे और प्रतिभागियों को स्थिति-आधारित चर्चाओं और सामरिक अभ्यासों के माध्यम से प्रक्रियाओं को समझने में सक्षम बनाना है।

स्रोत: पीआईबी

हरिमाउ शक्ति अभ्यास

खबरों में क्यों?

हरिमाउ शक्ति अभ्यास का चौथा संस्करण मलेशिया के पहांग जिले के बेंटोंग शिविर में शुरू हुआ।

हरिमाउ शक्ति अभ्यास के बारे में:

- यह भारत और मलेशिया के बीच आयोजित एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है।
- भारतीय सैन्य टुकड़ी का प्रतिनिधित्व महार रेजिमेंट की एक बटालियन द्वारा किया जा रहा है।
- यह एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो भारत और मलेशिया में बारी-बारी से आयोजित किया जाता है । पिछला संस्करण नवंबर 2023 में भारत के मेघालय में उमरोई छावनी में आयोजित किया गया था।
- संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र अधिदेश के अध्याय VII के तहत जंगल क्षेत्र में आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने के लिए दोनों पक्षों की संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना है। यह अभ्यास जंगल के वातावरण में अभियानों पर केंद्रित होगा।
- 2024 का अभ्यास दो चरणों में आयोजित किया जाएगा ।
- पहले चरण में दोनों सेनाओं के बीच क्रॉस ट्रेनिंग पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसमें व्याख्यान, प्रदर्शन और जंगल इलाकों में विभिन्न अभ्यासों का अभ्यास शामिल होगा।
- अंतिम चरण में दोनों सेनाएं एक कृत्रिम अभ्यास में सक्रिय रूप से भाग लेंगी, जिसमें सेनाएं विभिन्न अभ्यासों को अंजाम देंगी , जिसमें एंटी-एमटी एंबुश, बंदरगाह पर कब्जा, टोही गश्त, घात लगाना और आतंकवादियों द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्र पर हमला शामिल है।
- महत्व: इससे दोनों पक्षों को संयुक्त अभियान चलाने की रणनीति, तकनीक और प्रक्रियाओं में सर्वोत्तम अभ्यास साझा करने में मदद मिलेगी । इससे दोनों सेनाओं के बीच अंतर-संचालन, सौहार्द और सौहार्द विकसित करने में मदद मिलेगी।

स्रोत: पीआईबी

स्वास्थ्य और शिक्षा

स्जोग्रेन रोग

खबरों में क्यों?

विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में स्जोग्रेन रोग एक मूक महामारी है, जिसका निदान ठीक से नहीं किया गया है तथा इसे ठीक से समझा नहीं गया है।

स्जोग्रेन रोग के बारे में:

- यह एक दीर्घकालिक विकार है जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से शरीर की नमी पैदा करने वाली ग्रंथियों को निशाना बनाती है।
- यह एक अल्प-पहचानी गई स्वप्रतिरक्षी स्थिति है, जिसका अक्सर वर्षों तक निदान नहीं हो पाता।
- प्रबलता: यह पुरुषों की तुलना में महिलाओं में लगभग 10 गुना अधिक आम है और आमतौर पर 30 और 40 की उम्र में प्रकट होता है, हालांकि यह किसी भी उम्र में दिखाई दे सकता है, यहां तक कि बच्चों में भी।

स्जोग्रेन रोग के लक्षण:

- सबसे आम शिकायतें सूखी आंखें और शुष्क मुँह हैं, जो जीवन की गुणवत्ता को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती हैं।
- सूखी आंखों के कारण, विशेष रूप से जागने पर और लंबे समय तक स्क्रीन का उपयोग करने पर, आंखों में रेत जैसा महसूस हो सकता है, जबकि शुष्क मुंह के कारण निगलने में कठिनाई हो सकती है और दंत समस्याओं का जोखिम काफी बढ़ सकता है।
- स्जोग्रेन रोग जोड़ों में दर्द, थकान और लार ग्रंथियों में सूजन के साथ प्रकट हो सकता है, जिससे यह एक जटिल, बहु-प्रणाली रोग बन जाता है।

स्जोग्रेन रोग का इलाज:

- इसमें लार उत्तेजक और प्रतिस्थापन और जीवनशैली समायोजन के साथ सूखापन का प्रबंधन करना शामिल है। प्रणालीगत लक्षणों के लिए, प्रतिरक्षादमनकारी दवाओं का उपयोग किया जाता है।
- मरीजों को एयर कंडीशनिंग और अत्यधिक स्क्रीन समय जैसी चीजों से बचना चाहिए।
- यूवी सुरक्षा वाले धूप के चश्मे और जेल-आधारित चिकनाई वाली बूंदों के लगातार उपयोग से महत्वपूर्ण अंतर आ सकता है।

स्रोत: द हिंदू

बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024

खबरों में क्यों?

लोकसभा ने हाल ही में बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 को ध्वनिमत से पारित कर दिया।

बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 के बारे में:

- यह बैंकिंग क्षेत्र में प्रशासन में सुधार लाने तथा ग्राहक सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रस्तुत करता है।
- विधेयक में पांच अधिनियमों में संशोधन का प्रावधान है: भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934; बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949; भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955; बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970; और बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1980।

विधेयक की मुख्य विशेषताएं:

- प्रमुख प्रावधानों में बैंक खाताधारकों को अपने खातों के लिए अधिकतम चार व्यक्तियों को नामांकित करने की अनुमति देना शामिल है, जिसमें क्रमिक या एक साथ नामांकन का विकल्प भी शामिल है।
- तथापि, लॉकर धारकों को लगातार नामांकन तक ही सीमित रखा जाएगा ।
- विधेयक में निदेशक पद के लिए "पर्याप्त ब्याज" की परिभाषा में संशोधन का भी प्रस्ताव है , जिसके तहत सीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
- इसके अतिरिक्त, सहकारी बैंकों में निदेशकों (अध्यक्षों और पूर्णकालिक निदेशकों को छोड़कर) का कार्यकाल संविधान (सत्तानवेवें संशोधन) अधिनियम, 2011 के अनुरूप 8 वर्ष से बढ़कर 10 वर्ष हो जाएगा।
- यह विधेयक केन्द्रीय सहकारी बैंक के निदेशक को राज्य सहकारी बैंक के बोर्ड में सेवा देने की अनुमति देगा।
- विधेयक में वैधानिक लेखा परीक्षकों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक के निर्णय में बैंकों को अधिक स्वतंत्रता देने का भी प्रावधान है।
- इसमें बैंकों के लिए विनियामक अनुपालन हेतु रिपोर्टिंग तिथियों को दूसरे और चौथे शुक्रवार के स्थान पर प्रत्येक माह की 15वीं और अंतिम तिथि निर्धारित करने का भी प्रस्ताव है ।
- विधेयक में दावा न किए गए लाभांश, शेयर और ब्याज या बांडों के मोचन को निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (IEPF) में स्थानांतरित करने का भी प्रावधान है, जिससे व्यक्तियों को कोष से स्थानांतरण या धन वापसी का दावा करने की अनुमति मिलेगी, जिससे निवेशकों के हितों की रक्षा होगी।

स्रोतः इंडियन एक्सप्रेस

तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 2024

खबरों में क्यों?

राज्यसभा ने हाल ही में तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 2024 को ध्वनिमत से पारित कर दिया, जिससे भारत के तेल और गैस अन्वेषण कानूनों में महत्वपूर्ण बदलाव का मार्ग प्रशस्त हो गया।

तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 2024 के बारे में:

- यह तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 में संशोधन करने वाला विधेयक है, जिसका उद्देश्य तेल और गैस अन्वेषण और उत्पादन में निवेश को बढ़ावा देना है।
- यह विधेयक प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के अन्वेषण और निष्कर्षण को विनियमित करेगा ।
- संशोधित विधेयक में खनिज तेलों की परिभाषा का विस्तार करते हुए इसमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को भी शामिल किया गया है ।
- संशोधित विधेयक में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन, कोल बेड मीथेन और शेल गैस/तेल को खनिज तेलों की श्रेणी में शामिल किया गया है ।
- हालांकि, इसमें स्पष्ट किया गया है कि खनिज तेलों में कोयला, लिग्नाइट या हीलियम शामिल नहीं होंगे।
- इसमें खनन पट्टों का भी प्रावधान है - इसमें अन्वेषण, पूर्वेक्षण, उत्पादन, खनिज तेलों का व्यापार योग्य बनाना और निपटान जैसी विभिन्न गतिविधियां शामिल होंगी ।
- तेल और गैस क्षेत्रों की खोज में पूर्वेक्षण प्रारंभिक चरण है, जिसमें बड़े क्षेत्रों में संभावित पेट्रोलियम संचय का आकलन शामिल है।
- नया विधेयक खनन पट्टे की जगह पेट्रोलियम पट्टे को लागू करेगा , ताकि इसी तरह की गतिविधियों को शामिल किया जा सके। हालांकि, पुराने कानून के तहत दिए गए मौजूदा खनन पट्टे वैध बने रहेंगे ।
- नया विधेयक केंद्र सरकार को कई मामलों पर नियम बनाने का अधिकार देगा, जैसे पट्टे देने, विलय, पट्टे की शर्तों और नियमों को विनियमित करना, जिसमें न्यूनतम और अधिकतम क्षेत्र और पट्टे की अवधि, खनिज तेलों का संरक्षण और विकास, तेल उत्पादन के तरीके और रॉयल्टी, शुल्क और करों आदि के संग्रह का तरीका शामिल है।
- इसका उद्देश्य "दण्ड, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा न्यायनिर्णयन, तथा न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के आदेश के

विरुद्ध अपील" की व्यवस्था करके मूल 1948 के कानून के कुछ प्रावधानों को अपराधमुक्त करना है ।

- नियमों के उल्लंघन के मामलों में सजा और जुर्माने को वर्तमान 1000 रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने का प्रावधान विधेयक में किया गया है।
- वैध पट्टे के बिना अन्वेषण, पूर्वेक्षण और उत्पादन के मामलों में 25 लाख रुपये का जुर्माना और उल्लंघन जारी रहने पर प्रतिदिन 10 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा।
- विवाद समाधान के लिए, केंद्र सरकार दंड निर्धारण हेतु संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी की नियुक्ति करेगी ।
- न्यायनिर्णयन अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस बोर्ड विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 में निर्दिष्ट अपीलीय न्यायाधिकरण में दायर की जा सकती है ।

स्रोत: द इकोनॉमिक टाइम्स

लिनन निरीक्षण और छंटाई सहायक प्रणाली (LISA)

खबरों में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री ने लिनन निरीक्षण एवं छंटाई सहायक (एलआईएसए) प्रणाली का उद्घाटन किया।

लिनन निरीक्षण और छंटाई सहायक प्रणाली (LISA) के बारे में:

- यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-आधारित प्रणाली है , जो वातानुकूलित कोचों में यात्रियों को प्रदान की जाने वाली चादरें और तौलिये आदि का निरीक्षण और छंटाई करती है ।
- इसे ट्रेनों में इस्तेमाल की जाने वाली चादरों की 100% गुणवत्ता निरीक्षण सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- उन्नत एआई एल्गोरिदम सटीक और विश्वसनीय निरीक्षण परिणाम सुनिश्चित करते हैं और यह बड़ी मात्रा में लिनेन को शीघ्रता से संसाधित कर सकता है, जिससे परिचालन दक्षता में काफी सुधार होता है।
- इसे भारतीय रेलवे के पुणे डिवीजन द्वारा विकसित किया गया और घोरपडी इंटीग्रेटेड कोचिंग कॉम्प्लेक्स (जीआईसीसी) में स्थापित किया गया।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है?

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता से तात्पर्य मशीनों द्वारा मानव जैसे कार्य करने से है।
- इसके मुख्य घटक हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जो डेटा पर प्रशिक्षण देते हैं, न्यूरल नेटवर्क जो मस्तिष्क की संरचना की नकल करते हैं, तथा प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण जो मानव भाषा को समझता है।

स्रोत: द न्यू इंडियन एक्सप्रेस

अन्ना चक्र

खबरों में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने 'अन्न चक्र' और स्कैन (एनएफएसए के लिए सब्सिडी दावा आवेदन) पोर्टल लॉन्च किया।

अन्ना चक्र के बारे में:

- यह एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन उपकरण है।
- इसका नेतृत्व खाद्य सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा किया जाता है, जो पूरे देश में पीडीएस लॉजिस्टिक्स नेटवर्क की दक्षता को बढ़ाता है।
- इसे विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) और फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर (एफआईटीटी), आईआईटी-दिल्ली के सहयोग से विकसित किया गया है।

पोर्टल का कार्य:

- यह परियोजना इष्टतम मार्गों की पहचान करने तथा आपूर्ति श्रृंखला नोड्स में खाद्यान्नों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए उन्नत एल्गोरिदम का लाभ उठाती है ।
- इस परिमाण के कार्य में एक जटिल आपूर्ति श्रृंखला शामिल होती है, जो किसानों से लेकर उचित मूल्य की दुकानों तक अनेक हितधारकों पर निर्भर करती है।
- राज्यों के बीच पीडीएस आवागमन के अनुकूलन के लिए अंतर-राज्यीय मार्ग अनुकूलन उपकरण विकसित किया गया है और इसे यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूएलआईपी) के माध्यम से रेलवे के एफओआईएस (फ्रेट ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम) पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है ।
- इस प्रयास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म के साथ अनुकूलन उपकरण का एकीकरण है, जो अब राज्यों में एफपीएस और गोदामों के भौगोलिक स्थानों को दर्शाता है।

स्कैन (एनएफएसए के लिए सब्सिडी दावा आवेदन) पोर्टल के बारे में:

- इसमें राज्यों द्वारा सब्सिडी दावों को एकल खिड़की के माध्यम से प्रस्तुत करने , दावों की जांच करने और डीएफपीडी द्वारा अनुमोदन करने की व्यवस्था होगी, जिससे निपटान प्रक्रिया में तेजी आएगी।
- यह पोर्टल नियम-आधारित प्रसंस्करण का उपयोग करके खाद्य सब्सिडी जारी करने और निपटान के लिए सभी प्रक्रियाओं के अंत-से-अंत वर्कफ़्लो स्वचालन को सुनिश्चित करेगा।

स्रोत: पीआईबी

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी)

खबरों में क्यों?

एक ऐतिहासिक घटनाक्रम में, राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (आईएन-स्पेस) को पुरस्कार देने वाली संस्था (दोहरी) के रूप में आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है।

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) के बारे में:

- इसे 2018 में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE), भारत सरकार द्वारा एक नियामक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था , जिसका उद्देश्य तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (TVET) क्षेत्र में गुणवत्ता सुनिश्चित करना था।
- इसने राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (एनएसडीए) और पूर्ववर्ती राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) द्वारा निभाई जा रही भूमिकाओं को अपने हाथ में ले लिया है ।
- इसे दीर्घकालिक और अल्पकालिक व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में शामिल व्यावसायिक शिक्षा संस्थाओं के विकास, गुणात्मक सुधार और विनियमन का कार्य सौंपा गया है, साथ ही उनके संचालन के लिए न्यूनतम मानक भी स्थापित करना है ।
- एनसीवीईटी के प्रमुख कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:
  - ○पुरस्कार देने वाली संस्थाओं को मान्यता देना, निगरानी करना, अनुशासित करना तथा उनकी मान्यता रद्द करना।
  - ○मूल्यांकन एजेंसियों को मान्यता देना, निगरानी करना, अनुशासित करना और उनकी मान्यता रद्द करना।
  - ○कौशल सूचना प्रदाताओं को मान्यता देना, निगरानी करना, अनुशासित करना तथा उनकी मान्यता रद्द करना।
  - ○योग्यताओं के अनुमोदन के लिए दिशानिर्देश तैयार करना तथा ऐसे दिशानिर्देशों में निर्धारित तरीके से योग्यताओं को अनुमोदित करना।
  - ○मान्यता प्राप्त निकायों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण की प्रणाली बनाना और उसकी निगरानी करना।

स्रोत: पीआईबी

MuleHunter.AI

खबरों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से अपनी पहल MuleHunter.AI के साथ सहयोग करने को कहा, ताकि वित्तीय धोखाधड़ी करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले म्यूल खातों को समाप्त किया जा सके।

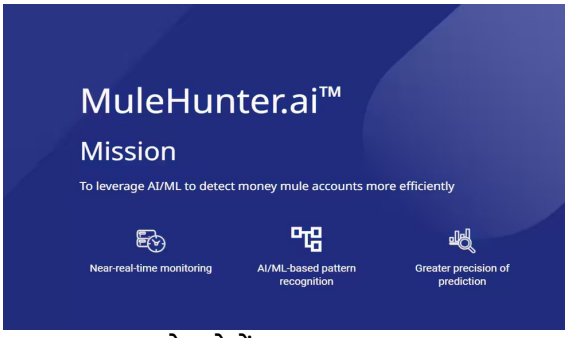

MuleHunter.AI के बारे में:

- यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस/मशीन लर्निंग आधारित मॉडल है।
- इसे रिजर्व बैंक इनोवेशन हब (आरबीआईएच) द्वारा विकसित किया गया है, जो भारतीय रिजर्व बैंक की एक सहायक कंपनी है।
- यह मॉडल कुशल तरीके से खच्चर बैंक खातों का पता लगाने में सक्षम बनाता है। दो बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ किए गए पायलट प्रोजेक्ट से उत्साहजनक परिणाम मिले हैं।

MuleHunter.AI के लाभ:

- **म्यूल खातों की पहचान:** यह खच्चर खातों की पहचान करने और उन पर नज़र रखने पर ध्यान केंद्रित करता है, जिनका उपयोग अक्सर धोखाधड़ी वाले लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता है। लेन-देन के पैटर्न का विश्लेषण करके, सिस्टम उन संदिग्ध खातों को चिह्नित कर सकता है जिनका उपयोग अवैध रूप से प्राप्त धन को स्थानांतरित करने के लिए किया जा रहा है।
- **वास्तविक समय की निगरानी:** यह लेनदेन की वास्तविक समय की निगरानी को सक्षम बनाता है , जिससे बैंकों और वित्तीय संस्थानों को संदिग्ध गतिविधियों का तुरंत पता लगाने और उन पर प्रतिक्रिया करने में मदद मिलती है। यह तत्काल कार्रवाई आगे होने वाले धोखाधड़ी वाले लेनदेन को रोक सकती है।
- **डेटा एनालिटिक्स**: यह बड़ी मात्रा में लेनदेन डेटा का आकलन करने के लिए उन्नत डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करता है। यह धोखाधड़ी गतिविधियों से जुड़े रुझानों और पैटर्न को पहचानने में मदद करता है, जिससे संभावित घोटालों को पहले से ही रोकना आसान हो जाता है।
- **संस्थाओं के बीच सहयोग:** यह प्लेटफ़ॉर्म बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करता है। पहचाने गए खच्चर खातों के बारे में जानकारी साझा करने से डिजिटल धोखाधड़ी के खिलाफ़ अधिक व्यापक बचाव बनाने में मदद मिलती है।
- **विनियामक अनुपालन:** यह वित्तीय संस्थाओं को धन शोधन निवारण (एएमएल) और आतंकवाद के वित्तपोषण (सीएफटी) से निपटने से संबंधित विनियामक आवश्यकताओं के अनुपालन में सहायता करता है, जिससे वित्तीय प्रणाली की समग्र अखंडता बढ़ती है।

म्यूल बैंक खाता क्या है?

- यह एक बैंक खाता है, जिसका उपयोग अपराधियों द्वारा अवैध गतिविधियों के लिए किया जाता है, जिसमें अवैध धन का शोधन भी शामिल है।
- म्यूल खाते को आमतौर पर अपराधियों द्वारा उनके मूल उपयोगकर्ताओं से खरीदा जाता है, जो प्रायः निम्न आय वर्ग से होते हैं, या तकनीकी साक्षरता का निम्न स्तर रखते हैं।
- इससे संबंधित शब्द "मनी म्यूल" का प्रयोग उन निर्दोष पीड़ितों के लिए किया जाता है , जिनका उपयोग अपराधी अपने बैंक

खातों के माध्यम से चोरी या अवैध धन को सफेद करने के लिए करते हैं।

- जब ऐसी घटनाएं रिपोर्ट की जाती हैं, तो धन का लेन-देन करने वाले पुलिस जांच का लक्ष्य बन जाते हैं, क्योंकि इसमें उनके खाते ही शामिल होते हैं, जबकि वास्तविक अपराधी पकड़ में नहीं आते।

स्रोतः बिजनेस स्टैंडर्ड

ई-एनडब्ल्यूआर आधारित प्रतिज्ञा वित्तपोषण के लिए ऋण गारंटी योजना

खबरों में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने ई-एनडब्ल्यूआर आधारित प्रतिज्ञा वित्तपोषण (सीजीएस-एनपीएफ) के लिए ऋण गारंटी योजना का शुभारंभ किया।

ई-एनडब्ल्यूआर आधारित प्रतिज्ञा वित्तपोषण के लिए ऋण गारंटी योजना के बारे में :

- इसका उद्देश्य छोटे किसानों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराना है ताकि उन्हें संकटपूर्ण विक्रय से बचाया जा सके।
- यह किसानों को भंडारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए) से मान्यता प्राप्त गोदामों में माल जमा करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य गोदाम रसीदों (ई-एनडब्ल्यूआर) के आधार पर फसलोत्तर वित्त पोषण के लिए 1,000 करोड़ रुपये का कोष उपलब्ध कराता है ।
- कवरेज: कृषि प्रयोजनों के लिए 75 लाख रुपये तक का ऋण और गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए 200 लाख रुपये तक का ऋण।
- पात्र संस्थाएँ: सभी अनुसूचित बैंक और सभी सहकारी बैंक।
- पात्र उधारकर्ता: लघु एवं सीमांत किसान (एसएमएफ)/महिलाएं/एससी/एसटी/दिव्यांग किसान, अन्य किसान, एमएसएमई, व्यापारी, एफपीओ और किसान सहकारी समितियां।
- कवर किए गए जोखिम: ऋण और वेयरहाउसमैन जोखिम
- गारंटी कवरेज: छोटे एवं सीमांत किसानों/महिलाओं/एससी/एसटी/दिव्यांगों के लिए 3 लाख रुपये तक के ऋण के लिए 85% और 3 से 75 लाख रुपये तक के ऋण के लिए 80% तथा अन्य उधारकर्ताओं के लिए 75%।
- ऋण गारंटी योजनाओं से लक्षित लाभार्थियों के लिए वित्त की उपलब्धता और पहुंच में वृद्धि होने की उम्मीद है , क्योंकि वे आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- इससे ई-एनडब्ल्यूआर के तहत फसलोपरांत ऋण देने में वृद्धि होगी और इस प्रकार किसानों की आय में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

स्रोत: पीआईबी

RACE IAS

गुरुवायुर मंदिर

खबरों में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में गुरुवायुर मंदिर प्रशासन के पक्ष में केरल उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ एक याचिका पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की है, जिसने भीड़ प्रबंधन के मुद्दों का हवाला देते हुए एकादशी पर "उदयस्थमन पूजा" के प्राचीन अनुष्ठान को बंद करने का फैसला किया था।

गुरुवायुर मंदिर के बारे में:

- गुरुवायूर श्री कृष्ण स्वामी मंदिर , जिसे दक्षिण का द्वारका भी कहा जाता है, भगवान कृष्ण को समर्पित एक हिंदू मंदिर है।
- यह केरल के त्रिशूर जिले के छोटे से शहर गुरुवायुर में स्थित है।
- मंदिर के सबसे पुराने अभिलेख 17वीं शताब्दी के हैं , लेकिन अन्य साहित्यिक ग्रंथों और किंवदंतियों से संकेत मिलता है कि मंदिर लगभग 5000 वर्ष पुराना हो सकता है।
- 1716 ई. में डचों ने मंदिर को लूटा और आग लगा दी। 1747 ई. में इसका पुनर्निर्माण किया गया।
- प्रतिदिन आने वाले श्रद्धालुओं की दृष्टि से यह भारत का चौथा सबसे बड़ा तीर्थस्थल है।

मंदिर की विशेषताएँ:

- भगवान कृष्ण या गुरुवायूरप्पन इस मंदिर के मुख्य देवता हैं।
- यह मंदिर पारंपरिक केरल स्थापत्य शैली में बनाया गया है।
- ऐसा माना जाता है कि मंदिर के केंद्रीय मंदिर का पुनर्निर्माण वर्ष 1638 ई. में किया गया था।
- मंदिर परिसर में नालम्बलम (गर्भगृह के चारों ओर मंदिर संरचना), बालिक्कल (बलि का पत्थर) और दीपस्तंभम (प्रकाश स्तंभ) जैसी संरचनाएं स्थित हैं।
- गर्भगृह की दीवारें 17 वीं शताब्दी के प्राचीन भित्तिचित्रों से सुसज्जित हैं।
- यहाँ का एक और प्रसिद्ध स्थल है ध्वजस्तंभ । यह लगभग 70 फीट ऊँचा ध्वजस्तंभ है जो पूरी तरह सोने से ढका हुआ है।
- गुरुवायुर मंदिर में तुलाभरम सबसे लोकप्रिय प्रसादों में से एक है । इस अनुष्ठान में, भक्तों को गुड़, नारियल, चीनी या केले के साथ एक विशाल तराजू पर तौला जाता है। यह मात्रा फिर भगवान को प्रसाद के रूप में दी जाती है।
- यह मंदिर बंदी एशियाई नर हाथियों की एक बड़ी आबादी का घर होने के लिए भी जाना जाता है।
- पुन्नथुर कोट्टा हाथी अभयारण्य , जहां 56 हाथी रहते हैं, मंदिर के बहुत निकट है।

स्रोत: इंडिया टुडे

पांडुपोल हनुमान मंदिर

खबरों में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में सरिस्का बाघ अभयारण्य के वन्यजीवों के संरक्षण और पांडुपोल हनुमान मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता पर बल दिया।

पांडुपोल हनुमान मंदिर के बारे में:

- यह एक 5000 साल पुराना तीर्थस्थल है जो राजस्थान के अलवर में सरिस्का बाघ अभयारण्य के हरे-भरे विस्तार में स्थित है ।
- पांडुपोल हनुमान मंदिर का इतिहास हिंदू पौराणिक कथाओं से गहराई से जुड़ा हुआ है।
- ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल के दौरान पांडवों ने अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ काफी समय वनवास में बिताया था ।
- ऐसा माना जाता है कि अपने निर्वासन के दौरान वे इस क्षेत्र में आये थे, जिसे उस समय विराटनगर के नाम से जाना जाता था।
- ऐसा माना जाता है कि यह वह स्थान है जहां भीम की भगवान हनुमान से मुलाकात हुई थी।
- मंदिर का नाम, " पांडुपोल ", "पांडव" शब्द से लिया गया है , जो इस पौराणिक कथा से इसके संबंध को दर्शाता है।
- मंदिर के नाम में "हनुमान" शब्द भगवान हनुमान के सम्मान में है।
- मंदिर का मुख्य आकर्षण भगवान हनुमान की लेटी हुई मूर्ति है , जिसे पांडवों ने यहां स्थापित किया था।

सरिस्का बाघ अभयारण्य के बारे में मुख्य तथ्य:

- यह राजस्थान में स्थित है ।
- यह अरावली पहाड़ियों में बसा हुआ है और इसका क्षेत्रफल 800 वर्ग किलोमीटर है।
- 1955 में प्राकृतिक रिजर्व तथा 1979 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किये जाने से पहले यह कभी अलवर के महाराजा का शिकारगाह था।
- यह बाघों को सफलतापूर्वक स्थानांतरित करने वाला विश्व का पहला रिजर्व है ।
- यह पुराने मंदिरों, महलों और झीलों जैसे पांडु पोल, भानगढ़ किला, अजबगढ़, प्रतापगढ़, सिलीसेढ़ झील और जयसमंद झील के लिए भी प्रसिद्ध है।

- वनस्पति : इसकी वनस्पति उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों और उत्तरी उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों के अनुरूप है ।
- वनस्पति : यह ढोक वृक्षों से आच्छादित है। यहां पाई जाने वाली अन्य प्रजातियों में सालार, कड़ाया, गोल, बेर, बरगद, गुगल, बांस, कैर, अडूस्ता आदि शामिल हैं।
- जीव-जंतु : बाघ के अलावा इस रिजर्व में तेंदुआ, सांभर, चीतल, नीलगाय, चार सींग वाले मृग, जंगली सूअर आदि जैसे कई अन्य जंगली जानवर पाए जाते हैं ।

स्रोतः टाइम्स ऑफ इंडिया

सक्रिय शासन और समय पर कार्यान्वयन (प्रगति) मंच

खबरों में क्यों?

ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सैद बिजनेस स्कूल और गेट्स फाउंडेशन की एक रिपोर्ट में हाल ही में कहा गया है कि सरकार के सक्रिय शासन और समय पर कार्यान्वयन (प्रगति) मंच ने देश की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के क्रियान्वयन में बदलाव ला दिया है।

प्रगति प्लेटफॉर्म के बारे में:

- यह एक बहुउद्देश्यीय और बहु-मॉडल मंच है जिसका उद्देश्य आम आदमी की शिकायतों का समाधान करना और साथ ही भारत सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और परियोजनाओं के साथ-साथ राज्य सरकारों द्वारा चिह्नित परियोजनाओं की निगरानी और समीक्षा करना है।
- यह प्रमुख हितधारकों के बीच वास्तविक समय उपस्थिति और आदान-प्रदान के साथ ई-पारदर्शिता और ई-जवाबदेही लाने के लिए एक मजबूत प्रणाली भी है।
- यह प्लेटफॉर्म 25 मार्च 2015 को लॉन्च किया गया था।
- यह एक त्रिस्तरीय प्रणाली है (पीएमओ, केंद्र सरकार के सचिव और राज्यों के मुख्य सचिव)।
- प्रधानमंत्री डेटा और भू-सूचना विज्ञान दृश्यों द्वारा सक्षम वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत सरकार के सचिवों और मुख्य सचिवों के साथ बातचीत करने के लिए एक मासिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं ।
- इस प्रणाली को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) की सहायता से पीएमओ टीम द्वारा आंतरिक रूप से डिजाइन किया गया है ।

  प्रगति प्लेटफॉर्म में तीन नवीनतम प्रौद्योगिकियां सम्मिलित हैं : डिजिटल डेटा प्रबंधन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी।

स्रोतः बिजनेस स्टैंडर्ड

किसी न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया

खबरों में क्यों?

हाल ही में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव को हटाने के लिए राज्यसभा के 55 सांसदों द्वारा राज्यसभा के सभापति को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

किसी न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया क्या है?

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 और 217 के तहत , राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश को 'सिद्ध कदाचार' या 'अक्षमता' के आधार पर हटाया जा सकता है । इस प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों में पारित किया जाना चाहिए:
  - ○सदन की कुल सदस्यता के बहुमत से , तथा
  - ○उसी सत्र में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से (विशेष बहुमत)।
- भारत का संविधान 'सिद्ध कदाचार' या 'अक्षमता' जैसे शब्दों को परिभाषित नहीं करता । हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णयों के माध्यम से स्पष्ट किया है कि जानबूझकर कदाचार , भ्रष्टाचार , ईमानदारी की कमी या नैतिक पतन से जुड़े अपराध जैसे कार्य कदाचार के अंतर्गत आते हैं।
- अक्षमता से तात्पर्य ऐसी चिकित्सीय स्थिति से है जिसमें शारीरिक या मानसिक सीमाएं शामिल होती हैं जो न्यायाधीश को अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने से रोकती हैं।

न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के तहत विस्तृत प्रक्रिया

न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 में विस्तार से बताई गई है , जिसके अनुसार:

- निष्कासन के प्रस्ताव पर राज्य सभा में कम से कम 50 सदस्यों या लोक सभा में 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए ।
- राज्य सभा के सभापति या लोक सभा के अध्यक्ष को परामर्श के बाद प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का विवेकाधिकार प्राप्त है ।
- यदि स्वीकृति मिल जाती है तो एक तीन सदस्यीय समिति गठित की जाती है, जिसमें शामिल होंगे:
  - ○सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश,
  - ○एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, और
  - ○एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता.
- समिति आरोपों की जांच करती है। यदि न्यायाधीश को कदाचार या अक्षमता से मुक्त कर दिया जाता है , तो प्रस्ताव को छोड़ दिया जाता है और आगे नहीं बढ़ाया जाता है।
- यदि समिति न्यायाधीश को दुर्व्यवहार या अक्षमता का दोषी पाती है , तो रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में पेश की जाती है , जहां प्रस्ताव को विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए ।
- न्यायाधीश को हटाने के लिए राष्ट्रपति को एक संबोधन प्रस्तुत किया जाता है।
- अंततः राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का आदेश पारित करते हैं।

स्रोत: द हिंदू

अल्पसंख्यक अधिकारों पर संविधान

खबरों में क्यों?

18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो राष्ट्रीय, जातीय, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा (1992 में अपनाया गया) की याद दिलाता है।

भारत में अल्पसंख्यकों की अवधारणा:

- परिभाषा: भारत के संविधान में "अल्पसंख्यक" शब्द का उल्लेख है लेकिन इसे परिभाषित नहीं किया गया है ।
- सर्वोच्च न्यायालय का रुख: अल्पसंख्यकों को राज्य स्तर पर परिभाषित किया जाना चाहिए :
  ○उदाहरण: पंजाब, कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में हिंदू धार्मिक अल्पसंख्यक हैं ।
- धार्मिक अल्पसंख्यक: राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम की धारा 2(सी) के तहत , निम्नलिखित छह समुदायों को आधिकारिक तौर पर अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता दी गई है: मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख, जैन और पारसी।
- भाषाई अल्पसंख्यक: वे लोग हैं जिनकी मातृभाषा किसी राज्य की प्रमुख भाषा से भिन्न होती है।
- धारा 350-ए भाषाई अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों के लिए मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करती है ।

अल्पसंख्यक अधिकारों से संबंधित प्रमुख लेख:

- अनुच्छेद 29: भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण
- अनुच्छेद 29(1): विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को उसे संरक्षित करने का अधिकार प्रदान करता है ।
- यह सांस्कृतिक बहुलवाद और विविध समाज में समूह पहचान के महत्व को स्वीकार करता है।
- अल्पसंख्यक समूहों को अपनी विशिष्ट संस्कृतियों की रक्षा के लिए स्पष्ट संरक्षण की आवश्यकता है।
- अनुच्छेद 30: शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार
- अनुच्छेद 30(1): सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार देता है ।
- अनुच्छेद 30(1ए): अल्पसंख्यक संस्थाओं से संबंधित संपत्ति अर्जित करने पर मुआवजे से संबंधित है।
- अनुच्छेद 30(2): सहायता प्रदान करते समय अल्पसंख्यक-प्रबंधित संस्थाओं के विरुद्ध भेदभाव पर रोक लगाता है ।

न्यायिक व्याख्याएं:

- केरल शिक्षा विधेयक (1957) के संबंध में: सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों के लिए "विकल्प" शब्द की केन्द्रीयता की पुष्टि की।
- जेवियर्स कॉलेज सोसाइटी (1974): सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 30 का उद्देश्य बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समूहों के बीच समानता सुनिश्चित करना है ।
- केशवानंद भारती केस (1973): सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 30 को संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा घोषित किया , जिसे बदला नहीं जा सकता।
- अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय केस (2024): अनुच्छेद 30 को समानता और गैर-भेदभाव के पहलू के रूप में मान्यता दी गई ।

अनुच्छेद 350-ए और 350-बी के बारे में मुख्य तथ्य:

- अनुच्छेद 350-ए: राज्यों को भाषाई अल्पसंख्यक बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने के लिए बाध्य करता है ।
- अनुच्छेद 350-बी: भाषाई अल्पसंख्यकों की शिकायतों के समाधान हेतु एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान करता है ।

स्रोत: द हिंदू

संयुक्त संसदीय समिति

खबरों में क्यों?

संविधान (129वें) संशोधन विधेयक की समीक्षा के लिए 31 सांसदों वाली एक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का गठन किया जाएगा।

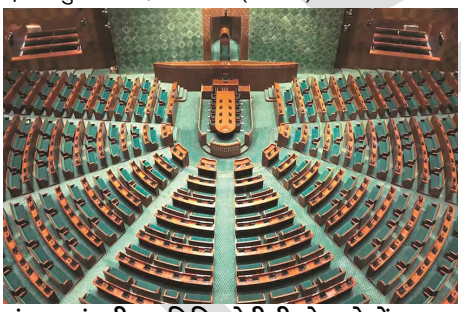

संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के बारे में:

- यह एक तदर्थ निकाय है, जो एक निश्चित समय सीमा के भीतर किसी विशिष्ट मामले की विस्तृत जांच करने के लिए एक लघु संसद के रूप में कार्य करता है। इसका कार्यकाल समाप्त होने या इसका कार्य पूरा हो जाने के बाद इसे भंग कर दिया जाता है।
- इसका गठन संसद द्वारा किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है , जैसे किसी विषय या विधेयक की विस्तृत जांच करना।
- इसमें दोनों सदनों के अलावा सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य भी शामिल हैं।
- इसकी स्थापना संसद के एक सदन द्वारा प्रस्ताव पारित करने तथा दूसरे सदन द्वारा उस पर सहमति जताने के बाद की जाती है।
- जेपीसी के सदस्यों का निर्णय संसद द्वारा किया जाता है।
- जेपीसी का अधिदेश उसके गठन के प्रस्ताव पर निर्भर करता है।जेपीसी की सिफारिशें सरकार पर बाध्यकारी नहीं हैं।
- पहले भी कुछ संयुक्त संसदीय समितियां गठित की जा चुकी हैं, जिनके पास जांच संबंधी शक्तियां हैं:
  ○दूरसंचार लाइसेंस और स्पेक्ट्रम के आवंटन और मूल्य निर्धारण से संबंधित मामलों की जांच करना।
  ○शीतल पेय, फलों के रस और अन्य पेय पदार्थों में कीटनाशक अवशेषों और सुरक्षा मानक पर
  ○शेयर बाजार घोटाले और उससे संबंधित मामलों पर
  ○प्रतिभूति और बैंकिंग लेनदेन में अनियमितताओं की जांच करना
  ○बोफोर्स अनुबंध की जांच करना

स्रोत: द हिंदू

डिजाइन कानून संधि

खबरों में क्यों?

लगभग दो दशकों की बातचीत के बाद, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) के सदस्य देशों ने ऐतिहासिक डिजाइन कानून संधि (डीएलटी) को अपनाया।

डिज़ाइन कानून संधि के बारे में:

- इसका उद्देश्य औद्योगिक डिजाइन संरक्षण के लिए प्रक्रियागत ढांचे में सामंजस्य स्थापित करना, विभिन्न न्यायक्षेत्रों में पंजीकरण प्रक्रियाओं की दक्षता और पहुंच में सुधार करना है।
- इस संधि को लागू करने के लिए 15 अनुबंधकारी पक्षों की आवश्यकता है।

डिज़ाइन कानून संधि की प्रमुख विशेषताऐं:

- इसमें डिजाइन के प्रथम प्रकटीकरण के बाद 12 महीने की छूट अवधि का प्रावधान है, जिसके दौरान ऐसे प्रकटीकरण से पंजीकरण के लिए इसकी वैधता प्रभावित नहीं होगी।
- यह आवेदकों को राहत उपाय प्रदान करता है तथा समय-सीमा चूक जाने पर उनके अधिकारों को खोने से बचाने के लिए कुछ लचीलापन प्रदान करता है।
- यह डिज़ाइन पंजीकरण के नवीनीकरण के अनुरोध की प्रक्रिया को सरल बनाता है।
- यह डिजाइनों के लिए ई-फाइलिंग प्रणाली की शुरूआत और प्राथमिकता वाले दस्तावेजों के इलेक्ट्रॉनिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देता है।
- यह संधि के कार्यान्वयन के लिए विकासशील और अल्पविकसित देशों को तकनीकी सहायता की उपलब्धता सुनिश्चित करता है।

डिज़ाइन कानून संधि के फ़ायदे:

- इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सुव्यवस्थित डिजाइन संरक्षण के लाभ सभी हितधारकों के लिए सुलभ हों, विशेष रूप से लघु और मध्यम आकार के उद्यमों (एसएमई), स्टार्टअप और स्वतंत्र डिजाइनरों पर जोर दिया जाएगा।
- प्रक्रियागत आवश्यकताओं को मानकीकृत करके, डीएलटी प्रशासनिक बोझ को कम करता है, जिससे डिजाइन में वैश्विक रचनात्मकता को बढ़ावा मिलता है।
- स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम और स्टार्टअप बौद्धिक संपदा संरक्षण (एसआईपीपी) योजना जैसी पहलों के साथ संयुक्त होने पर, ये प्रावधान स्टार्टअप्स और एसएमई को वैश्विक स्तर पर डिजाइन अधिकार हासिल करने में सशक्त बनाने, उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने और बाजार के विकास को समर्थन देने में मदद करेंगे।
- भारत ने हाल ही में इस संधि के अंतिम अधिनियम पर हस्ताक्षर किये हैं।

स्रोत: पीआईबी

K-4 बैलिस्टिक मिसाइल

खबरों में क्यों?

हाल ही में भारत ने विशाखापत्तनम तट पर पनडुब्बी आईएनएस अरिघाट से K4 मिसाइल का परीक्षण किया है।

K-4 बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में:

- यह एक परमाणु-सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता लगभग 3,500 किलोमीटर है ।
- यह एक ठोस ईंधन चालित मिसाइल है जिसका पिछले कुछ वर्षों में पनडुब्बी प्लेटफार्मों से कम से कम पांच बार परीक्षण किया गया है।
- के-4 मिसाइल के सफल प्रक्षेपण से भारत की परमाणु त्रिकोण में एक और ताकत जुड़ गई है, जिसमें भूमि-आधारित मिसाइलें, हवा से प्रक्षेपित परमाणु हथियार और पनडुब्बी से प्रक्षेपित किए जाने वाले प्लेटफार्म शामिल हैं।
- इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा विकसित किया गया है।
- महत्व: इससे भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता और सामरिक क्षमताओं को काफी बढ़ावा मिलेगा।

आईएनएस अरिघाट के बारे में मुख्य तथ्य

- इसे अगस्त 2024 में चालू किया जाएगा।
- यह भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत के बाद भारत की दूसरी परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी (एसएसबीएन) है।

- इसका निर्माण विशाखापत्तनम स्थित भारतीय नौसेना के जहाज निर्माण केंद्र (एसबीसी) में किया गया।
- यह 3500 किलोमीटर से अधिक रेंज वाली चार परमाणु-सक्षम K-4 SLBM (पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल) या लगभग 750 किलोमीटर रेंज वाली बारह पारंपरिक वारहेड K-15 SLBM ले जा सकता है।

स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स

टंगस्टन

खबरों में क्यों?

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने हाल ही में प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मदुरै जिले के नायकरपट्टी टंगस्टन ब्लॉक में टंगस्टन खनन के लिए एक निजी फर्म को केंद्र द्वारा दिए गए अधिकारों को रद्द करने की मांग की।

टंगस्टन के बारे में:

- टंगस्टन एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक W तथा

परमाणु संख्या 74 है।

- संक्रमण धातु के रूप में वर्गीकृत टंगस्टन कमरे के तापमान पर ठोस है ।
- यह एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला तत्व है । यह चट्टानों और खनिजों में अन्य रसायनों के साथ मिलकर पाया जाता है, लेकिन कभी भी शुद्ध धातु के रूप में नहीं । यह प्रकृति में वोलफ्रेमाइट और स्केलाइट जैसे खनिज रूपों में पाया जाता है।
- मौलिक टंगस्टन एक सफेद से लेकर स्टील ग्रे रंग की धातु है (शुद्धता के आधार पर) जिसका उपयोग शुद्ध रूप में या अन्य धातुओं के साथ मिश्रित कर मिश्र धातु बनाने के लिए किया जा सकता है।
- प्रमुख उत्पादक: चीन (वैश्विक उत्पादन पर हावी), वियतनाम, रूस और उत्तर कोरिया।
- भारत सरकार द्वारा इसे महत्वपूर्ण खनिज के रूप में वर्गीकृत किया गया है ।

टंगस्टन की विशेषताएँ:

- सबसे सघन धातुओं में से एक , जिसका घनत्व 19.3 ग्राम/सेकेंड है
- सभी धातुओं का उच्चतम गलनांक 3410 °C
- 3410 °C पर सभी धातुओं में सबसे कम वाष्प दाब 4.27 Pa
- 1650 °C से अधिक तापमान पर सभी धातुओं में उच्चतम तन्य शक्ति

टंगस्टन के उपयोग :

- टंगस्टन मिश्र धातुएं मजबूत और लचीली होती हैं , घिसाव का प्रतिरोध करती हैं , तथा बिजली का अच्छा संचालन करती हैं।
- टंगस्टन का उपयोग एक्स-रे ट्यूब, प्रकाश बल्ब, उच्च गति वाले उपकरण, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड, टरबाइन ब्लेड, गोल्फ क्लब, डार्ट, मछली पकड़ने के वजन, जाइरोस्कोप पहियों, फोनोग्राफ सुइयों, गोलियों और कवच भेदक जैसे उत्पादों में किया जाता है ।
- इसका उपयोग रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तीव्र करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में भी किया जाता है।
- टंगस्टन के रासायनिक यौगिकों का उपयोग कई प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
- सीमेंटेड टंगस्टन कार्बाइड एक कठोर पदार्थ है जिसका उपयोग पीसने वाले पहिये और काटने या आकार देने वाले उपकरण बनाने के लिए किया जाता है ।
- अन्य टंगस्टन यौगिकों का उपयोग सिरेमिक पिगमेंट में, कपड़ों के लिए अग्निरोधी कोटिंग्स के रूप में, तथा कपड़ों के लिए रंग-प्रतिरोधी रंगों के रूप में किया जाता है।

स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स

CE20 क्रायोजेनिक इंजन

खबरों में क्यों?

हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने अपने सीई20 क्रायोजेनिक इंजन का समुद्र तल पर गर्म परीक्षण सफलतापूर्वक किया है।

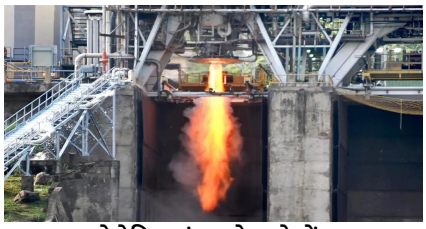

CE20 क्रायोजेनिक इंजन के बारे में :

- यह इसरो के द्रव प्रणोदन प्रणाली केंद्र द्वारा विकसित स्वदेशी इंजन है ।
- यह एल.वी.एम.3 प्रक्षेपण यान के ऊपरी चरण को शक्ति प्रदान कर रहा है तथा इसे 19 टन के थ्रस्ट स्तर पर संचालित करने के लिए योग्य बनाया गया है।
- इस इंजन ने अब तक छह एलवीएम3 मिशनों के ऊपरी चरण को सफलतापूर्वक संचालित किया है।
- हाल ही में, इंजन को गगनयान मिशन के लिए 20 टन के थ्रस्ट स्तर के साथ योग्य घोषित किया गया था , तथा भविष्य के C32 चरण के लिए 22 टन के उन्नत थ्रस्ट स्तर के साथ भी योग्य घोषित किया गया था, जिससे LVM3 प्रक्षेपण यान की पेलोड क्षमता में वृद्धि होगी।
- इसमें एक अभिनव नोजल संरक्षण प्रणाली है जो इंजन परीक्षण में पिछली जटिलताओं को दूर करती है।
- परीक्षण की प्रमुख उपलब्धियों में 100 नोजल क्षेत्र अनुपात वाले इंजन का सफल परीक्षण, केवल प्रथम तत्व को सक्रिय करके बहु-तत्व इग्नाइटर का मूल्यांकन, तथा सामान्य इंजन और सुविधा प्रदर्शन की पुष्टि शामिल है।
- **महत्व**: यह परीक्षण इसरो के स्वदेशी इंजन विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो जटिल रॉकेट प्रणोदन चुनौतियों पर काबू पाने की इसकी क्षमता को प्रदर्शित करता है।

स्रोत: द हिंदू

आइडियोपैथिक पलमोनेरी फ़ाइब्रोसिस

खबरों में क्यों?

हाल ही में, प्रसिद्ध तबला वादक और पांच बार ग्रैमी पुरस्कार विजेता का सैन फ्रांसिस्को में इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस (आईपीएफ) के कारण निधन हो गया।

इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस के बारे में :

- यह एक गंभीर दीर्घकालिक रोग है जो फेफड़ों में वायुकोषों या एल्वियोली के आसपास के ऊतकों को प्रभावित करता है ।
- अज्ञात कारणों से फेफड़े के ऊतक मोटे और कठोर हो जाते हैं - जिससे समय के साथ फेफड़ों में स्थायी निशान बन जाते हैं।
- फाइब्रोसिस के कारण रोगी के लिए सांस लेना धीरे-धीरे अधिक कठिन हो सकता है।
- आईपीएफ की जटिलताओं में फुफ्फुसीय उच्च रक्तचाप और श्वसन विफलता शामिल है , जो तब होती है जब फेफड़े बिना सहारे के रक्तप्रवाह में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाते हैं। इससे मस्तिष्क और अन्य अंगों को आवश्यक ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है।
- धूम्रपान करने वाले या आईपीएफ के पारिवारिक इतिहास वाले व्यक्तियों को इसका जोखिम अधिक होता है। उम्र बढ़ने के साथ जोखिम भी बढ़ता है, जिससे वृद्ध व्यक्तियों में इस बीमारी के विकसित होने की संभावना अधिक होती है।

बीमारी के लक्षण:

- सामान्य लक्षणों में सांस लेने में तकलीफ और सूखी खांसी शामिल है - और समय के साथ दोनों ही बदतर हो सकते हैं।
- मरीजों को मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द के साथ-साथ अत्यधिक थकान भी महसूस हो सकती है।
- धीरे-धीरे, अनजाने में वजन कम होना और सामान्य रूप से अस्वस्थ

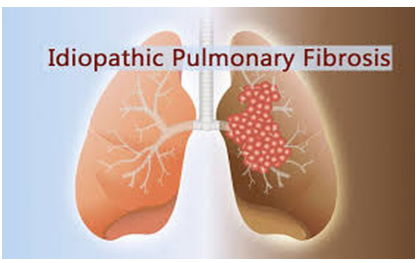

महसूस करना। लक्षणों में तेज़, उथली साँस लेना और क्लबिंग शामिल है - उंगलियों या पैर की उंगलियों के सिरे चौड़े और गोल हो जाना।

बीमारी का इलाज:

- आईपीएफ का कोई इलाज नहीं है , लेकिन कुछ उपचार फेफड़ों की क्षति को धीमा करने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद कर सकते हैं।
- निंटेडानिब या पिरफेनिडोन जैसी दवाएं फेफड़ों को बेहतर ढंग से कार्य करने में मदद कर सकती हैं और सूजन को कम कर सकती हैं।
- ऑक्सीजन थेरेपी से श्वास और व्यायाम क्षमता में सुधार हो सकता है, जबकि गंभीर मामलों में वेंटिलेटर सहायता की आवश्यकता हो सकती है।

स्रोतः इंडियन एक्सप्रेस

वर्मम थेरेपी

खबरों में क्यों?

हाल ही में, राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान (एनआईएस) ने एक साथ 567 व्यक्तियों को वर्मम थेरेपी प्रदान करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है।

वर्मम थेरेपी के बारे में:

- यह सिद्ध चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत एक अद्वितीय और पारंपरिक उपचार पद्धति है, जो विभिन्न स्वास्थ्य स्थितियों के उपचार में अपनी प्रभावशीलता के लिए लंबे समय से प्रतिष्ठित है।
- यह एक दवा रहित, गैर-आक्रामक, सरल चिकित्सा है जिसका उपयोग दर्द प्रबंधन में किया जाता है।
- वर्मम को मानव शरीर में स्थित महत्वपूर्ण जीवन ऊर्जा बिंदु माना जाता है। सिद्धरों द्वारा इसकी पहचान 108 बिंदुओं के रूप में की गई है।

- यह चिकित्सा विशेष रूप से मस्कुलोस्केलेटल दर्द, चोटों और तंत्रिका संबंधी विकारों में तेजी से राहत प्रदान करने की अपनी क्षमता के लिए प्रसिद्ध है ।
- यह एक वैज्ञानिक आधारित चिकित्सीय पद्धति है जिसका उपयोग स्ट्रोक, गठिया और आघात-संबंधी चोटों सहित तीव्र और दीर्घकालिक बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है।
- उपलब्धि का महत्व: यह सिद्ध चिकित्सा और इसकी उपचार क्षमता की बढ़ती वैश्विक मान्यता का प्रमाण है।

सिद्ध चिकित्सा:

- यह चिकित्सा की एक पारंपरिक प्रणाली है जिसकी उत्पत्ति दक्षिण भारत में हुई और इसे भारत की सबसे पुरानी चिकित्सा प्रणालियों में से एक माना जाता है।
- संगम युग के साहित्यिक साक्ष्यों से पता चलता है कि इस प्रणाली की उत्पत्ति लगभग 10,000 ईसा पूर्व हुई थी।
- यह प्रणाली सिद्धों के काम पर आधारित थी, जो ज़्यादातर तमिलनाडु से थे। इसी वजह से इसे सिद्ध चिकित्सा प्रणाली कहा जाता है।

स्रोत: पीआईबी

अगली पीढ़ी का डीएनए अनुक्रमण

खबरों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई), देहरादून में पश्मीना प्रमाणीकरण और अगली पीढ़ी के डीएनए अनुक्रमण सुविधा के लिए उन्नत सुविधा का उद्घाटन किया।

अगली पीढ़ी के डीएनए अनुक्रमण के बारे में :

- यह एक क्रांतिकारी तकनीक है जो लाखों डीएनए अनुक्रमों का एक साथ विश्लेषण करते हुए संपूर्ण जीनोम की तीव्र और उच्च-थ्रूपुट डिकोडिंग को सक्षम बनाती है ।
- इससे शोधकर्ताओं को आनुवंशिक विविधता, विकासवादी संबंधों और जनसंख्या स्वास्थ्य के बारे में गहन जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलती है ।

  ○वन्यजीव संरक्षण में, एनजीएस आनुवंशिक विविधता के संबंध में जनसंख्या आनुवंशिक स्वास्थ्य की पहचान करने, आनुवंशिक बाधाओं की जानकारी और आबादी पर उनके प्रभाव, अद्वितीय अनुकूलन और अद्वितीय विकासवादी इतिहास वाली प्रजातियों, रोग के प्रकोप को समझने , अवैध वन्यजीव व्यापार का पता लगाने और जैव विविधता पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ।
- यह अत्याधुनिक एनजीएस सुविधा भारतीय वन्यजीव संस्थान को वन्यजीव संरक्षण में आणविक और आनुवंशिक अनुसंधान के लिए एक अग्रणी केंद्र के रूप में स्थापित करती है।

पश्मीना प्रमाणन केंद्र के बारे में मुख्य बातें:

- इसकी स्थापना डब्ल्यूआईआई और हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीएच) के बीच सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत की गई थी।

- इसकी स्थापना निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए की गई थी:

  ○पश्मीना व्यापार को सुव्यवस्थित करना।

  ○संबद्ध निर्माताओं, निर्यातकों और व्यापारियों को किसी भी प्रतिबंधित फाइबर से मुक्त असली पश्मीना उत्पाद को प्रमाणित करने के लिए वन-स्टॉप परीक्षण सुविधा प्रदान करना।

  ○सभी परीक्षण किए गए उत्पादों पर एक पहचान योग्य विशिष्ट आईडी टैग तथा व्यक्तिगत ई-प्रमाणपत्र अंकित किए जाएंगे , जिससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ऐसे उत्पादों का निर्बाध व्यापार संभव हो सकेगा।
- पश्मीना प्रमाणन के लिए उन्नत उन्नत सुविधा में अब ऊर्जा फैलाव स्पेक्ट्रोस्कोपी (ईडीएस) के साथ एक समर्पित स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप (एसईएम) शामिल है, जो ऊन परीक्षण और प्रमाणन की सटीकता और विश्वसनीयता को बढ़ाता है।
- उन्नत सुविधा में निम्नलिखित सुविधाएं शामिल हैं:

  ○उन्नत फाइबर विश्लेषण: पश्मीना फाइबर की सटीक पहचान और प्रमाणीकरण के लिए SEM-EDS प्रौद्योगिकी।

  ○सुव्यवस्थित प्रमाणन: पता लगाने और गुणवत्ता आश्वासन के लिए विशिष्ट आईडी टैगिंग और ई-प्रमाणपत्र।

  ○वैश्विक व्यापार सुविधा: प्रमाणित उत्पादों का परेशानी मुक्त आवागमन, निकास बिंदुओं पर फाइबर जांच के कारण होने वाली देरी और वित्तीय नुकसान को समाप्त करना।

स्रोत: पीआईबी

सारेक्स-24

खबरों में क्यों?

भारतीय तटरक्षक बल के राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास और कार्यशाला (SAREX-24) का 11वां संस्करण 28-29 नवंबर, 2024 को कोच्चि, केरल में होगा।

सारेक्स-24 के बारे में:

- इसका आयोजन राष्ट्रीय समुद्री खोज एवं बचाव बोर्ड के तत्वावधान में किया जाता है ।
- अभ्यास का विषय है 'क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से खोज और बचाव क्षमताओं को बढ़ाना' ।
- यह भारतीय खोज एवं बचाव क्षेत्र तथा इससे परे, स्थान, राष्ट्रीयता या परिस्थितियों की परवाह किए बिना बड़े पैमाने पर आकस्मिकताओं के दौरान सहायता प्रदान करने के लिए आईसीजी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- इस कार्यक्रम में विभिन्न कार्यक्रम शामिल होंगे, जिनमें टेबल-टॉप अभ्यास, कार्यशाला और सेमिनार शामिल होंगे, जिसमें सरकारी एजेंसियों, मंत्रालयों और सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न हितधारक और विदेशी प्रतिनिधि भाग लेंगे।
- दो बड़े पैमाने की आकस्मिकताओं से युक्त यह समुद्री अभ्यास कोच्चि तट पर किया जाएगा, जिसमें भारतीय तटरक्षक, नौसेना, भारतीय वायु सेना के जहाज और विमान, कोचीन बंदरगाह प्राधिकरण के यात्री जहाज और टग तथा सीमा शुल्क विभाग की नौकाएं भाग लेंगी।
- समुद्री अभ्यास में प्रतिक्रिया मैट्रिक्स में संकटग्रस्त यात्रियों को निकालने के विभिन्न तरीके शामिल होंगे , जिसमें उपग्रह-सहायता प्राप्त संकट बीकन का उपयोग करते हुए नए युग की प्रौद्योगिकी का आगमन, जीवन रक्षक ब्वॉय तैनात करने के लिए ड्रोन, हवा से गिराए जाने वाले जीवन रक्षक राफ्ट, रिमोट नियंत्रित जीवन रक्षक ब्वॉय के संचालन का प्रदर्शन किया जाएगा।
- इस अभ्यास का उद्देश्य न केवल परिचालन की दक्षता और राष्ट्रीय हितधारकों के साथ समन्वय का मूल्यांकन करना है, बल्कि तटीय और मित्र देशों के साथ सहयोगात्मक जुड़ाव पर भी ध्यान केंद्रित करना है।

स्रोत: पीआईबी

सबल-20 लॉजिस्टिक्स ड्रोन

खबरों में क्यों?

भारतीय सेना की सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, निजी ड्रोन निर्माता कंपनी एंड्योरएयर ने पूर्वी सैन्य क्षेत्र में अपने नवीनतम सबल 20 सैन्य ड्रोन की आपूर्ति की है।

सबल-20 लॉजिस्टिक्स ड्रोन के बारे में:

- यह परिवर्तनीय पिच प्रौद्योगिकी पर आधारित एक विद्युत-मानवरहित हेलीकॉप्टर है, जिसे विशेष रूप से हवाई रसद के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- इसका निर्माण निजी ड्रोन निर्माता कंपनी द्वारा किया गया था।
- इसे परिचालन संबंधी कठिन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, तथा यह सटीक रसद, उच्च ऊंचाई पर परिचालन और लंबी दूरी की डिलीवरी सहित कार्यों में सहायता करता है।

ड्रोन की विशेषताएँ:

- ड्रोन में टेंडम रोटर कॉन्फ़िगरेशन की सुविधा है और इसका डिज़ाइन "उल्लेखनीय स्थिरता, उच्च ऊंचाई पर बेहतर प्रदर्शन, न्यूनतम अशांति जोखिम और विभिन्न इलाकों में उत्कृष्ट उठाने की क्षमता सुनिश्चित करता है"।
- यह 20 किलोग्राम तक का पेलोड ले जाने में सक्षम है , जो इसके स्वयं के वजन के 50 प्रतिशत के बराबर है, तथा इसमें भविष्य की आवश्यकताओं के लिए स्केलेबल विकल्प भी मौजूद हैं।
- यह सीमित और ऊबड़-खाबड़ इलाकों में भी काम कर सकता है, जबकि इसका कम आरपीएम (आरपीएम) डिजाइन शोर को कम करता है, जिससे संवेदनशील मिशनों में चुपके से काम करने की क्षमता बढ़ जाती है।
- सबल 20 की सबसे प्रमुख विशेषता इसकी वर्टिकल टेक-ऑफ और लैंडिंग (वीटीओएल) तकनीक है , जो ड्रोन को सीमित स्थानों और कठिन वातावरण में भी संचालित करने की अनुमति देती है ।
- इसमें अत्याधुनिक स्वायत्त उड़ान क्षमताएं और उपयोगकर्ता-अनुकूल नियंत्रण भी हैं, जो जटिल कार्यों को सरल बनाते हैं, तथा ऑपरेटर की दृष्टि से परे होने पर भी विश्वसनीय प्रदर्शन सुनिश्चित करते हैं।

स्रोत: फाइनेंशियल एक्सप्रेस

अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ

खबरों में क्यों?

हाल ही में, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) को सऊदी अरब के रियाद में अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा एसोसिएशन (आईएसएसए) द्वारा आयोजित एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय सामाजिक सुरक्षा फोरम (आरएसएसएफ एशिया-पैसिफिक) में अपने मोबाइल एप्लिकेशन (आस्क एन अप्वाइंटमेंट - एएए+) के लिए निर्णायक मंडल से विशेष उल्लेख के साथ एक योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।

आईएसएसए के बारे में:

- इसकी स्थापना 1927 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के तत्वावधान में की गई थी।
- यह पेशेवर दिशा-निर्देशों, विशेषज्ञ ज्ञान, सेवाओं और समर्थन के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रशासन में उत्कृष्टता को बढ़ावा देता है, ताकि इसके सदस्य गतिशील सामाजिक सुरक्षा प्रणालियां विकसित करने में सक्षम हो सकें।

शासन:

- आम सभा: यह वास्तव में एसोसिएशन की संविधान सभा है और सर्वोच्च वैधानिक निकाय है। इसमें ISSA के सभी सदस्यों का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व होता है। इसकी बैठक हर तीन साल में होती है।
- परिषद: यह संघ का निर्वाचित निकाय है , जो प्रत्येक देश के नाममात्र प्रतिनिधियों से बना होता है, जिसमें ISSA का कम से कम एक संबद्ध सदस्य होता है, तथा इनमें से प्रत्येक देश का एक नाममात्र प्रतिनिधि होता है।
- ब्यूरो: यह एसोसिएशन का प्रशासनिक प्राधिकरण है , जिसमें ISSA के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, महासचिव और विश्व के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले निर्वाचित सदस्य शामिल हैं।
- नियंत्रण आयोग: यह एसोसिएशन के वित्तीय अभिलेखों और कोषाध्यक्ष द्वारा ब्यूरो को प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट और विवरणों की जांच करता है, तथा सत्यापित करता है कि सभी वित्तीय लेनदेन वित्तीय विनियमों के अनुरूप किए गए हैं।
- भारत इस संगठन का सदस्य देश है
- मुख्यालय: जिनेवा, स्विटजरलैंड

अपॉइंटमेंट पूछें ऐप के बारे में:

- यह बीमाकृत व्यक्तियों, लाभार्थियों, कर्मचारियों और ईएसआई पेंशनभोगियों को सेवा प्रदान करता है, और अंग्रेजी, हिंदी और छह क्षेत्रीय भाषाओं सहित 8 भाषाओं में उपलब्ध है।
- इसे स्वास्थ्य सेवाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, यह ऐप उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करने, कतार में इंतजार किए बिना चेक-इन करने और अपने ई-स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुंचने की सुविधा देता है।
- लाभार्थियों के लिए आधार सीडिंग , घर से नमूना संग्रह अनुरोध और विभिन्न ईएसआई लाभों के लिए पात्रता जांच जैसी अन्य सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं।
- इसके अतिरिक्त, फार्मेसी काउंटरों पर नुस्खों को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे AAA+ अपॉइंटमेंट के लिए कुशल सेवा सुनिश्चित होती है।

स्रोत: पीआईबी

RACE IAS

शहरी अवसंरचना विकास निधि

खबरों में क्यों?

हाल ही में आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री ने लोकसभा में बताया कि सरकार ने टियर 2 और टियर 3 शहरों में शहरी बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण की कमी का उपयोग करके शहरी बुनियादी ढांचा विकास कोष (यूआईडीएफ) की स्थापना की है।

शहरी अवसंरचना विकास निधि के बारे में:

- इसकी स्थापना प्राथमिकता क्षेत्र ऋण की कमी के उपयोग के माध्यम से की गई थी ।
- इसका उपयोग सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा टियर-2 और टियर-3 शहरों में शहरी बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए किया जाएगा।
- इसका उद्देश्य सार्वजनिक/राज्य एजेंसियों, नगर निगमों और शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से कार्यान्वित शहरी बुनियादी ढांचे के विकास कार्यों के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को पूरक बनाना है , ताकि सीवरेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल आपूर्ति और स्वच्छता , नालियों/तूफान जल नालियों आदि के निर्माण और सुधार जैसी बुनियादी सेवाएं प्रदान करने के लिए वित्तपोषण का एक स्थिर और अनुमानित स्रोत उपलब्ध कराया जा सके।
- इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाता है ।
- इस कोष की प्रारंभिक राशि ₹10,000 करोड़ है।
- इसकी स्थापना ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) की तर्ज पर की गई है ।
- राज्यों को यूआईडीएफ का उपयोग करते समय उचित उपयोगकर्ता शुल्क अपनाने के लिए 15वें वित्त आयोग के अनुदानों के साथ-साथ मौजूदा योजनाओं से संसाधनों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- वर्तमान में यह 459 टियर-2 शहरों और 580 टियर-3 शहरों को कवर करता है।

यूआईडीएफ ऋण:

○यूआईडीएफ ऋण पर ब्याज दर बैंक दर से घटाकर 1.5 प्रतिशत रखी गई है।

○ऋण (मूलधन) को ड्रॉ की तिथि से सात वर्षों के भीतर पांच समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाएगा , जिसमें दो वर्ष की स्थगन अवधि भी शामिल होगी।

○ब्याज तिमाही आधार पर देय होगा।

स्रोत: पीआईबी

वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना

खबरों में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना को मंजूरी दी है।

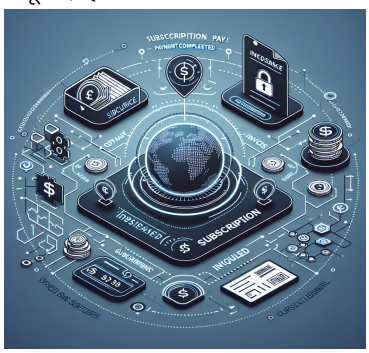

वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के बारे में:

- यह विद्वानों के शोध लेखों और पत्रिका प्रकाशन तक देशव्यापी पहुंच प्रदान करने के लिए एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना है।
- इस योजना को सरल, उपयोगकर्ता अनुकूल और पूर्णतः डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से संचालित किया जाएगा।
- यह सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों और केंद्रीय सरकार के अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं के लिए "एक राष्ट्र एक सदस्यता" सुविधा होगी ।
- यह अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने तथा सरकारी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं में अनुसंधान और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एएनआरएफ) पहल का पूरक होगा।
- एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना का लाभ केंद्र या राज्य सरकार के प्रबंधन के तहत सभी उच्च शिक्षण संस्थानों और केंद्र सरकार के अनुसंधान एवं विकास संस्थानों को एक केंद्रीय एजेंसी, अर्थात् सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क (INFLIBNET), जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) का एक स्वायत्त अंतर-विश्वविद्यालय केंद्र है, द्वारा समन्वित राष्ट्रीय सदस्यता के माध्यम से प्रदान किया जाएगा ।
- उच्च शिक्षा विभाग के पास एक एकीकृत पोर्टल "वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन" होगा , जिसके माध्यम से संस्थान पत्रिकाओं तक पहुंच सकेंगे।
- एएनआरएफ समय-समय पर इन संस्थाओं के भारतीय लेखकों के प्रकाशनों और वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के उपयोग की समीक्षा करेगा।
- वित्त पोषण: एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में 3 कैलेंडर वर्षों, 2025, 2026 और 2027 के लिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के लिए कुल लगभग 6,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं ।

वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का महत्व:

- यह भारत के युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक पहुंच को अधिकतम करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में पिछले दशक में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पहलों के दायरे और पहुंच को आगे बढ़ाएगा ।
- इस पहल से सभी विषयों के छात्रों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों के विशाल समुदाय को विद्वत्तापूर्ण पत्रिकाओं तक पहुंच का विस्तार होगा, जिसमें टियर 2 और टियर 3 शहरों के लोग भी शामिल हैं , जिससे देश में मुख्य और अंतःविषय अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा।

स्रोत: पीआईबी

राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ)

खबरों में क्यों?

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ) शुरू करने को मंजूरी दी।

राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के बारे में:

- यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक केन्द्र प्रायोजित योजना है।
- इसे पूरे देश में मिशन मोड में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक स्वतंत्र योजना के रूप में शुरू किया गया है।
- इसका उद्देश्य सभी के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना है।
- यह योजना किसानों को खेती की इनपुट लागत और बाहर से खरीदे जाने वाले इनपुट पर निर्भरता को कम करने में सहायता देने के लिए बनाई गई है ।

राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन की विशेषताएँ:

- अगले दो वर्षों में, एनएमएनएफ को इच्छुक ग्राम पंचायतों के 15,000 समूहों में क्रियान्वित किया जाएगा, तथा 1 करोड़ किसानों तक पहुंचा जाएगा तथा 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती (एनएफ) शुरू की जाएगी।
- प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों, एसआरएलएम/पीएसीएस/एफपीओ आदि को प्राथमिकता दी जाएगी।
- इसके अलावा, किसानों को उपयोग के लिए तैयार प्राकृतिक कृषि इनपुट की आसान उपलब्धता और पहुंच प्रदान करने के लिए आवश्यकता आधारित 10,000 जैव-इनपुट संसाधन केंद्र (बीआरसी) स्थापित किए जाएंगे।
- एनएमएनएफ के अंतर्गत, कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके), कृषि विश्वविद्यालयों (एयू) और किसानों के खेतों पर लगभग 2000 एनएफ मॉडल प्रदर्शन फार्म स्थापित किए जाएंगे , और इन्हें अनुभवी और प्रशिक्षित किसान मास्टर प्रशिक्षकों द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।
- इच्छुक किसानों को उनके गांवों के नजदीक केवीके, कृषि विश्वविद्यालयों और प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के खेतों में प्राकृतिक खेती के पैकेज, प्राकृतिक खेती के इनपुट तैयार करने आदि पर मॉडल प्रदर्शन फार्मों में प्रशिक्षण दिया जाएगा ।

- 75 लाख प्रशिक्षित इच्छुक किसान अपने पशुओं का उपयोग करके या बीआरसी से खरीद कर जीवामृत, बीजामृत आदि जैसे इनपुट तैयार करेंगे । क्लस्टरों में इच्छुक किसानों के बीच जागरूकता पैदा करने, उन्हें संगठित करने और उनकी सहायता करने के लिए 30,000 कृषि सखियों/सीआरपी को तैनात किया जाएगा ।
- किसानों को एक आसान सरल प्रमाणन प्रणाली और समर्पित सामान्य ब्रांडिंग प्रदान की जाएगी ताकि उन्हें अपने प्राकृतिक कृषि उत्पादों को बाजार तक पहुंच प्रदान की जा सके। एनएमएनएफ कार्यान्वयन की वास्तविक समय की जियो-टैग और संदर्भित निगरानी एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी।
- स्थानीय पशुधन जनसंख्या को बढ़ाने, केंद्रीय मवेशी प्रजनन फार्मों / क्षेत्रीय चारा स्टेशनों पर एनएफ मॉडल प्रदर्शन फार्मों का विकास करने , स्थानीय किसानों के बाजारों, एपीएमसी (कृषि उपज बाजार समिति) मंडियों, हाटों, डिपो आदि के लिए अभिसरण के माध्यम से जिला / ब्लॉक / जीपी स्तरों पर बाजार संपर्क प्रदान करने के लिए भारत सरकार / राज्य सरकारों / राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की मौजूदा योजनाओं और सहायता संरचनाओं के साथ अभिसरण की संभावना तलाशी जाएगी।
- इसके अतिरिक्त, छात्रों को RAWE कार्यक्रम और NF पर समर्पित स्नातक, स्नातकोत्तर और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के माध्यम से NMNF में शामिल किया जाएगा ।
- वित्तपोषण: इस योजना का 15वें वित्त आयोग (2025-26) तक कुल परिव्यय 2481 करोड़ रुपये (भारत सरकार का हिस्सा – 1584 करोड़ रुपये; राज्य का हिस्सा – 897 करोड़ रुपये) है।

स्रोत: पीआईबी

गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी (जीएमसी)

खबरों में क्यों?

आगामी गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी को भूटान की सबसे बड़ी "सहकारी परियोजना" बताते हुए भूटानी प्रधानमंत्री ने हाल ही में कहा कि वे विकसित किए जा रहे 2,500 वर्ग किलोमीटर के "शून्य कार्बन" शहर में भारत के समर्थन के लिए आभारी हैं।

गेलेफु माइंडफुलनेस सिटी (जीएमसी) के बारे में:

- यह एक नवोन्मेषी शहरी विकास परियोजना है जो आर्थिक विकास को जागरूकता, समग्र जीवन और स्थिरता के साथ एकीकृत करती है।
- जीएमसी परियोजना की परिकल्पना भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने की है।
- यह भूटान के दक्षिण-मध्य भाग में स्थित है और इसका क्षेत्रफल 2500 वर्ग किलोमीटर (सिंगापुर से भी बड़ा) है।
- यह भूटान में अपनी तरह का पहला विशेष प्रशासनिक क्षेत्र (एसएआर) है।

जीएमसी की विशेषताएं:

- शहर को रहने योग्य पुलों की एक श्रृंखला के आसपास बसाया जाएगा।
- यह एक कम ऊंचाई वाला शहर होने की उम्मीद है , जिसमें पश्चिमी और पारंपरिक चिकित्सा दोनों के लिए अपना विश्वविद्यालय और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं होंगी।
- नियोजित शहर में ग्यारह "रिबननुमा पड़ोस " होंगे, जिनमें क्षेत्र की 35 नदियाँ और जलधाराएँ शामिल होंगी।
- पड़ोस को मंडल की तरह डिजाइन किया जाएगा , जिसमें एक केंद्रीय सार्वजनिक स्थान के चारों ओर दोहराए गए पैटर्न व्यवस्थित होंगे ।
- शहर का अपना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा।
- इसमें कई बाजार और आध्यात्मिक केंद्र भी होंगे।
- बाढ़ से बचाव के लिए नदियों के किनारे धान के खेत बनाए जाएंगे, जिससे "शहरी सीढ़ीनुमा खेत बनेंगे जो पहाड़ियों से घाटी तक नीचे की ओर बहेंगे"।
- इसकी अपनी सरकार होगी और इसे अपने कानून बनाने की स्वतंत्रता होगी , साथ ही एक स्वतंत्र न्यायपालिका भी होगी ।
- इसमें दो संरक्षित क्षेत्र होंगे - एक राष्ट्रीय उद्यान और एक वन्यजीव अभयारण्य।

स्रोत: द हिंदू

पैन 2.0 परियोजना

खबरों में क्यों?

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने पैन 2.0 परियोजना को अपनी मंजूरी दे दी है।

पैन 2.0 परियोजना के बारे में:

- यह करदाताओं के बेहतर डिजिटल अनुभव के लिए पैन/टैन सेवाओं के प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन के माध्यम से करदाता पंजीकरण सेवाओं की व्यावसायिक प्रक्रियाओं को पुनः तैयार करने के लिए एक ई-गवर्नेंस परियोजना है।
- यह वर्तमान PAN/TAN 1.0 पारिस्थितिकी तंत्र का उन्नयन होगा, जो मुख्य और गैर-मुख्य PAN/TAN गतिविधियों के साथ-साथ PAN सत्यापन सेवा को भी समेकित करेगा।
- यह आयकर विभाग की एक परियोजना है ।
- पैन 2.0 परियोजना करदाता पंजीकरण सेवाओं में प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन को सक्षम बनाती है और इसके महत्वपूर्ण लाभ इस प्रकार हैं:
- बेहतर गुणवत्ता के साथ आसान पहुंच और त्वरित सेवा वितरण;
- सत्य का एकल स्रोत और डेटा संगतता
- पर्यावरण अनुकूल प्रक्रियाएं और लागत अनुकूलन; तथा
- अधिक चपलता के लिए बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और अनुकूलन ।
- पैन 2.0 परियोजना, डिजिटल इंडिया में निहित सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो निर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों की सभी

डिजिटल प्रणालियों के लिए सामान्य पहचानकर्ता के रूप में पैन के उपयोग को सक्षम बनाती है।

स्थायी खाता संख्या (पैन) क्या है?

- पैन दस अक्षरों का एक अल्फ़ान्यूमेरिक पहचानकर्ता है , जो आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है।
- यह किसी भी "व्यक्ति" को आवेदन करने पर प्रदान किया जाता है या औपचारिक अनुरोध के बिना विभाग द्वारा सीधे आवंटित किया जाता है।
- आयकर विभाग किसी व्यक्ति से जुड़े सभी लेन-देन की निगरानी और उन्हें जोड़ने के लिए पैन का उपयोग करता है। इसमें कर भुगतान, टीडीएस/टीसीएस क्रेडिट, आय रिटर्न, विशिष्ट लेन-देन और आधिकारिक संचार जैसी विभिन्न गतिविधियाँ शामिल हैं।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

ग्लोबल मैचमेकिंग प्लेटफॉर्म

खबरों में क्यों ?

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूएनआईडीओ) और क्लाइमेट क्लब ने ग्लोबल मैचमेकिंग प्लेटफॉर्म (जीएमपी) लॉन्च किया।

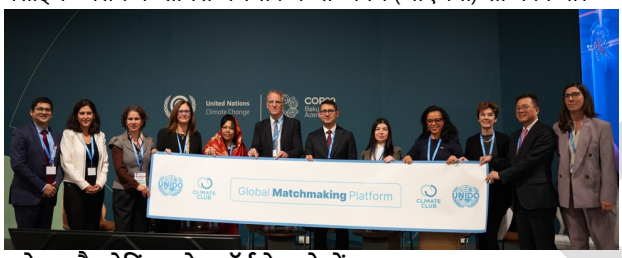

ग्लोबल मैचमेकिंग प्लेटफॉर्म के बारे में:

- इसे उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में भारी उत्सर्जन वाले उद्योगों के डीकार्बोनाइजेशन को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- ग्लोबल मैचमेकिंग प्लेटफॉर्म का विचार दिसंबर 2023 में 28वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP28) में क्लाइमेट क्लब के शुभारंभ के साथ पैदा हुआ था।
- यह ऊर्जा और उत्सर्जन-गहन औद्योगिक क्षेत्रों में उत्सर्जन को कम करने के लिए देश-विशिष्ट आवश्यकताओं को वैश्विक तकनीकी और वित्तीय सहायता से जोड़ता है।
- यह देशों को वितरण साझेदारों के नेटवर्क से जोड़ता है, तथा औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन प्रयासों के लिए व्यापक तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- ये साझेदार राष्ट्रों को नीति निर्माण, नवीन प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण तथा उत्सर्जन लक्ष्यों को बढ़ाने में सहायता सहित शून्य और निम्न-उत्सर्जन औद्योगिक प्रथाओं में परिवर्तन लाने के लिए निवेश को सुविधाजनक बनाने जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहायता करते हैं।
- यह तंत्र देशों को अपने डीकार्बोनाइजेशन मार्गों को अनुकूलित करने की अनुमति देता है, साथ ही साझेदार संगठनों द्वारा प्रदान किए गए मार्गदर्शन और संसाधनों तक पहुंच को सुव्यवस्थित करता है ताकि उत्सर्जन में भारी कमी लाई जा सके।
- उद्योग डीकार्बोनाइजेशन के लिए जीएमपी को जलवायु क्लब के समर्थन तंत्र के रूप में बनाया जा रहा है, जिसका सचिवालय यूएनआईडीओ द्वारा संचालित किया जाएगा।
- इसकी गतिविधियों को जलवायु क्लब के अंतरिम सचिवालय द्वारा भी समर्थन दिया जाता है, जिसकी मेजबानी आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) द्वारा संयुक्त रूप से की जाती है।

स्रोत: डाउन टू अर्थ

"बाल विवाह मुक्त भारत अभियान"

खबरों में क्यों?

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने हाल ही में "बाल विवाह मुक्त भारत अभियान" का शुभारंभ किया।

'बाल विवाह मुक्त भारत' अभियान के बारे में:

- इसे भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया।
- इसका उद्देश्य भारत में बाल विवाह को समाप्त करने के लिए सामूहिक प्रयास में विभिन्न हितधारकों को शामिल करना है ।
- इसमें सात उच्च बोझ वाले राज्यों - पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, राजस्थान, त्रिपुरा, असम और आंध्र प्रदेश - तथा लगभग 300 उच्च बोझ वाले जिलों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा , जहां बाल विवाह की दर राष्ट्रीय औसत की तुलना में अधिक है ।
- अभियान में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से 2029 तक बाल विवाह की दर को 5% से नीचे लाने के उद्देश्य से कार्य योजना तैयार करने का आह्वान किया जाएगा।
- सरकारी आंकड़ों के अनुसार, बाल विवाह की दर 2006 में 47.4% से घटकर 2019-21 में 23.3% हो गई।
- इस पहल की एक प्रमुख विशेषता बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल का शुभारंभ है , जो जागरूकता बढ़ाने, मामलों की रिपोर्ट करने और प्रगति की निगरानी करने के लिए एक मंच है ।
- पोर्टल को बाल विवाह निषेध अधिकारियों (सीएमपीओ) की प्रभावी निगरानी की सुविधा के लिए डिजाइन किया गया है , ताकि पर्यवेक्षण और मूल्यांकन तंत्र को मजबूत किया जा सके, ताकि बाल विवाह को रोकने और प्रभावित व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने में उनकी सक्रिय भूमिका सुनिश्चित की जा सके।
- लोग बाल विवाह से संबंधित अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे और ये शिकायतें सीधे देश में कहीं भी संबंधित सीएमपीओ को भेजी जाएंगी।
- सभी राज्यों को पोर्टल पर लॉग ऑन करने और सीएमपीओ को पंजीकृत करने का निर्देश दिया गया है ताकि मामलों की वास्तविक समय पर निगरानी हो सके।
- पोर्टल की निगरानी के लिए केंद्र में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे।
- इसका उद्देश्य सूचना तक जनता की पहुंच बढ़ाना तथा इसे आसानी से उपलब्ध कराना है ताकि बेहतर संचार और सहायता संभव हो सके।

स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स

ई-दाखिल पोर्टल

खबरों में क्यों?

उपभोक्ता मामले विभाग ने हाल ही में ई-दाखिल पोर्टल के सफल राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की घोषणा की, जो अब भारत के प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में चालू है।

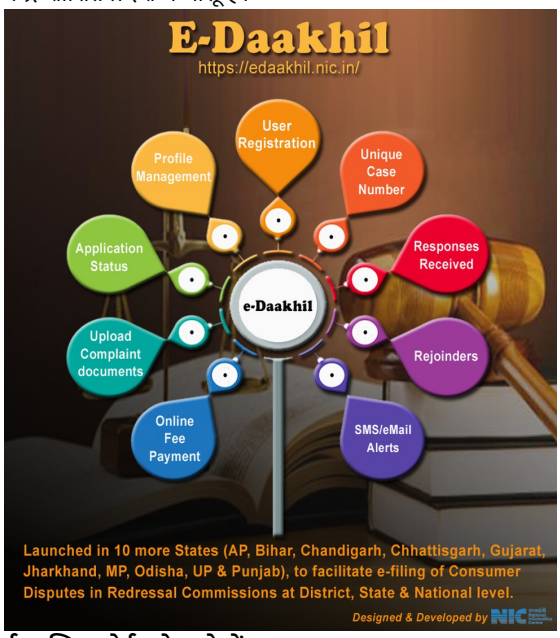

ई-दाखिल पोर्टल के बारे में:

- इसे उपभोक्ता शिकायतें दर्ज करने के लिए एक सस्ती, त्वरित और परेशानी मुक्त तंत्र के रूप में पेश किया गया था।
- इसे पहली बार 2020 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा लॉन्च किया गया था।

ई-दाखिल पोर्टल की विशेषताएँ:

- यह एक अभिनव ऑनलाइन मंच है जिसे उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है , जो उपभोक्ताओं को संबंधित उपभोक्ता फोरम तक पहुंचने के लिए एक कुशल और सुविधाजनक तरीका प्रदान करता है, जिससे उन्हें अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए यात्रा करने और शारीरिक रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होती है।
- पोर्टल एक सहज और आसान नेविगेशन वाला इंटरफेस प्रदान करता है , जिससे उपभोक्ता न्यूनतम प्रयास से शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
- शिकायत दर्ज करने से लेकर उनकी स्थिति पर नज़र रखने तक, ई-दाखिल मामला दर्ज करने के संबंध में कागज़ रहित और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करता है ।
- कोई भी उपभोक्ता या अधिवक्ता अपने पंजीकृत सेल फोन पर एक ओटीपी या अपने पंजीकृत ईमेल पते पर एक एक्टिवेशन लिंक प्राप्त करके आवश्यक प्रमाणीकरण के साथ ई-दाखिल प्लेटफॉर्म पर साइन अप कर सकता है । इसके बाद वे शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
- पोर्टल ने सभी पीड़ित उपभोक्ताओं को अपने घर बैठे ही ऑनलाइन उपभोक्ता आयोगों में शिकायत प्रस्तुत करने, उचित शुल्क का भुगतान करने तथा मामले की प्रगति पर ऑनलाइन नजर रखने की सुविधा प्रदान की है।
- यह भारत के सभी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिए सुलभ है , महानगरों से लेकर दूरदराज के क्षेत्रों तक।

स्रोत: पीआईबी

एकलव्य डिजिटल प्लेटफॉर्म

खबरों में क्यों?

हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख ने भारतीय सेना के लिए "एकलव्य" नामक एक ऑनलाइन शिक्षण मंच लॉन्च किया।

एकलव्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में:

- इसका विकास मुख्यालय सेना प्रशिक्षण कमान के तत्वावधान में किया गया है तथा प्रायोजक एजेंसी आर्मी वार कॉलेज है।
- इस प्लेटफॉर्म को "भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भूसूचना विज्ञान संस्थान" (बीआईएसएजी-एन), गांधीनगर द्वारा सूचना प्रणाली महानिदेशालय के सहयोग से विकसित किया गया है।
- इस प्लेटफॉर्म को आर्मी डेटा नेटवर्क पर होस्ट किया गया है और इसमें एक स्केलेबल आर्किटेक्चर है। यह मुख्यालय आर्मी ट्रेनिंग कमांड को भारतीय सेना के किसी भी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान को सहजता से एकीकृत करने में सक्षम बनाता है, जिनमें से प्रत्येक व्यापक श्रेणी के पाठ्यक्रमों की मेजबानी करने में सक्षम है।
- यह पहल भारतीय सेना द्वारा स्वयं को "परिवर्तन के दशक" में आगे बढ़ाने के साथ संरेखित है, जैसा कि सीओएएस द्वारा परिकल्पित है और साथ ही 2024 के लिए भारतीय सेना की थीम "प्रौद्योगिकी अवशोषण का वर्ष" के अनुरूप है।
- छात्र अधिकारियों को एक साथ कई पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकरण करने की अनुमति है।
- **तीन श्रेणियों के पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं**
  - ○'प्री-कोर्स प्रिपरेटरी कैप्सूल': इसमें विभिन्न श्रेणी 'ए' प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में आयोजित किए जा रहे सभी ऑफ़लाइन भौतिक पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन सामग्री है । इसका उद्देश्य "मूल बातें" को ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में स्थानांतरित करना है ताकि भौतिक पाठ्यक्रमों में "अनुप्रयोग भाग" पर ध्यान देने के साथ अधिक से अधिक समकालीन सामग्री हो।
  - ○नियुक्ति या विशिष्ट कार्यभार से संबंधित पाठ्यक्रम: इस श्रेणी के पाठ्यक्रम अधिकारियों को अपनी पसंद के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त करने में सक्षम बनाएंगे, जिससे उनकी रोजगार योजना बनाने में सहायता मिलेगी।
  - ○व्यावसायिक विकास सुइट: इसमें रणनीति, परिचालन कला, नेतृत्व, संगठनात्मक व्यवहार, वित्त, पढ़ने की कला, शक्तिशाली लेखन, उभरती प्रौद्योगिकी आदि पर पाठ्यक्रम शामिल होंगे।
- एकलव्य में खोज योग्य "नॉलेज हाईवे" की कार्यक्षमता भी है , जिसमें विभिन्न पत्रिकाएं, शोध पत्र और लेख आदि एक ही विंडो के अंतर्गत अपलोड किए जाते हैं।
- यह मंच अधिकारियों में सतत व्यावसायिक सैन्य शिक्षा को प्रोत्साहित करने, मौजूदा शारीरिक पाठ्यक्रम को समृद्ध बनाने, विशेषज्ञ नियुक्तियों के लिए अधिकारियों को तैयार करने और डोमेन विशेषज्ञता को प्रोत्साहित करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा।

स्रोत: पीआईबी

RACE IAS

शीस्टेम 2024

खबरों में क्यों?

नीति आयोग के अंतर्गत अटल नवाचार मिशन (एआईएम) और स्वीडन दूतावास में विज्ञान एवं नवाचार कार्यालय को शीस्टेम 2024 के सफल समापन की घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

शीस्टेम 2024 के बारे में:

- शीस्टेम (SheSTEM) अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) और स्वीडन दूतावास के विज्ञान एवं नवाचार कार्यालय द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है ।
- यह विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) में महिलाओं के योगदान का जश्न मनाता है और युवा मस्तिष्कों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) में करियर तलाशने के लिए प्रोत्साहित करके अगली पीढ़ी के नवप्रवर्तकों को प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है।
- शीस्टेम 2024 चुनौती में भारत भर के कक्षा 6-12 के विद्यार्थियों को बैटरी प्रौद्योगिकी और ऊर्जा भंडारण (बेस्ट) प्रणालियों पर केंद्रित नवीन विचार प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया था।
- भारत-नॉर्डिक बेस्ट परियोजना के भाग के रूप में , इस चुनौती का उद्देश्य ऊर्जा समाधानों को आगे बढ़ाकर स्थिरता को बढ़ावा देना है।
- प्रतिभागियों को दो मिनट के वीडियो प्रारूप में ऊर्जा भंडारण और स्थिरता के लिए अपने प्रोटोटाइप या अवधारणाएं प्रस्तुत करने का कार्य सौंपा गया था।
- प्रतियोगिता को असाधारण प्रतिक्रिया मिली, जिसमें 1000 से अधिक प्रविष्टियाँ प्राप्त हुईं, जिनमें भारत के युवाओं की रचनात्मकता, समस्या-समाधान कौशल और अग्रगामी सोच का प्रदर्शन किया गया।

अटल नवाचार मिशन (एआईएम) के बारे में:

- यह 2016 में नीति आयोग द्वारा स्थापित एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य स्कूलों, शैक्षिक संगठनों , अनुसंधान संस्थानों और एमएसएमई सहित उद्योगों में नवाचार के साथ-साथ उद्यमशीलता का माहौल बनाना और प्रोत्साहित करना है।
- इन कार्यक्रमों के अलावा, एआईएम नवाचार का माहौल बनाने के लिए शिक्षाविदों, उद्योगों, गैर सरकारी संगठनों और व्यक्तियों के साथ सहयोग भी करता है।
- वर्तमान में एआईएम की सभी पहलों की निगरानी और प्रबंधन वास्तविक समय एमआईएस प्रणालियों और गतिशील डैशबोर्ड का उपयोग करके व्यवस्थित रूप से किया जाता है।
- इसके दो कार्य हैं:
  - ○नवप्रवर्तकों को वित्तीय सहायता के साथ-साथ मार्गदर्शन के माध्यम से उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहित करके उद्यमशीलता को बढ़ावा देना
  - ○एक ऐसा मंच बनाकर नवाचार को बढ़ावा देना जहां समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के माध्यम से विचार उत्पन्न हों
- एआईएम ने इन कार्यों के समर्थन के लिए चार कार्यक्रम बनाए हैं :
  - ○अटल टिंकरिंग लैब्स
  - ○अटल इन्क्यूबेशन केंद्र
  - ○अटल न्यू इंडिया चुनौतियां और अटल ग्रैंड चुनौतियां
  - ○मेंटर इंडिया

स्रोत: पीआईबी

पनडुब्बी केबल लचीलेपन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार निकाय

खबरों में क्यों?

हाल ही में, बढ़ती चुनौतियों से निपटने और पनडुब्बी संबंधी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की निरंतर लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए पनडुब्बी केबल लचीलेपन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार निकाय की शुरुआत की गई।

पनडुब्बी केबल लचीलेपन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार निकाय के बारे में:

- इसे अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) और अंतर्राष्ट्रीय केबल संरक्षण समिति (आईसीपीसी) द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था।
- इस पहल का उद्देश्य पनडुब्बी केबलों की लचीलापन को मजबूत करना है , जो वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था के कामकाज के लिए आवश्यक हैं।
- इसमें विश्व भर से 40 सदस्य शामिल हैं - जिनमें मंत्री, नियामक प्राधिकरणों के प्रमुख और दूरसंचार के वरिष्ठ विशेषज्ञ शामिल हैं - यह निकाय एक विविध वैश्विक परिप्रेक्ष्य को प्रतिबिंबित करता है।
- सलाहकार निकाय अंतर्राष्ट्रीय नीतियों, बुनियादी ढांचे और पनडुब्बी केबल लचीलेपन में सुधार के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं पर परामर्श करने के लिए द्विवार्षिक बैठक करेगा

कार्य:

- यह केबल लचीलेपन में सुधार, क्षति के जोखिम को कम करने, तथा इन महत्वपूर्ण प्रणालियों की शीघ्र मरम्मत और स्थापना सुनिश्चित करने के लिए सरकारों और उद्योगों में सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने की दिशा में काम करेगा ।
- इस निकाय का सामूहिक अनुभव उन लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेगा जिनकी आजीविका पनडुब्बी केबलों पर निर्भर करती है, साथ ही उन लोगों की भी मदद करेगा जो इस महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की तैनाती, रखरखाव और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं।

- सलाहकार निकाय बढ़ते यातायात, पुराने बुनियादी ढांचे और पनडुब्बी केबलों के लिए बढ़ते पर्यावरणीय खतरों से संबंधित चुनौतियों का समाधान करने के लिए रणनीतिक मार्गदर्शन भी प्रदान करेगा ।

अंतर्राष्ट्रीय केबल संरक्षण समिति क्या है?

- इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और यह पनडुब्बी केबल उद्योग से जुड़ी सरकारों और वाणिज्यिक संस्थाओं के लिए एक वैश्विक मंच है।
- इसका प्राथमिक मिशन तकनीकी, कानूनी और पर्यावरणीय सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करके समुद्र के नीचे केबलों की सुरक्षा को बढ़ाना है।

स्रोत: पीआईबी

पीएम ई-विद्या

खबरों में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने नई दिल्ली में भारतीय सांकेतिक भाषा (आईएसएल) के लिए पीएमईविद्या डीटीएच 24x7 चैनल नंबर 31 का शुभारंभ किया।

पीएम ई-विद्या के बारे में:

- इसे 17 मई 2020 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था ।
- इसका उद्देश्य डिजिटल विभाजन को पाटना तथा देश भर में सभी विद्यार्थियों के लिए समावेशी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है।
- अपने विविध घटकों के माध्यम से, यह छात्रों और शिक्षकों दोनों को डिजिटल शिक्षण वातावरण के अनुकूल होने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करता है।
- यह शिक्षण हानि को न्यूनतम करने के लिए डिजिटल, ऑनलाइन और ऑन-एयर प्लेटफार्मों के माध्यम से शिक्षा तक बहु-मोड पहुंच प्रदान करता है ।
- यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के दृष्टिकोण का समर्थन करता है, जो पूरे देश में समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करता है।
- यह पहल डिजिटल संसाधनों, पाठ्यक्रमों और इंटरैक्टिव सामग्री की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध कराकर, ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों सहित सभी छात्रों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाती है।

घटक:

- दीक्षा (स्कूल शिक्षा के लिए डिजिटल अवसंरचना): यह एक राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो सभी ग्रेडों के लिए क्यूआर-कोडेड एनर्जाइज्ड पाठ्यपुस्तकों सहित उच्च गुणवत्ता वाली ई-सामग्री प्रदान करता है (एक राष्ट्र, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म)।
- पीएम ई-विद्या डीटीएच टीवी चैनल: इसमें शुरू में 12 डीटीएच चैनल थे, जिन्हें अब 200 चैनलों तक विस्तारित किया गया है, जो राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कक्षा 1-12 के लिए कई भारतीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान करते हैं।
- स्वयं (स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव-लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स): यह एक राष्ट्रीय MOOC प्लेटफॉर्म है जो क्रेडिट ट्रांसफर प्रावधानों के साथ उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम प्रदान करता है। यह NIOS और NCERT के माध्यम से स्कूली पाठ्यक्रम (9वीं-12वीं) भी प्रदान करता है। वर्तमान में, 10,000 से अधिक पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं, जिनमें 4.1 लाख छात्र NCERT पाठ्यक्रमों के लिए नामांकित हैं।
- रेडियो, सामुदायिक रेडियो और सीबीएसई पॉडकास्ट - शिक्षा वाणी: इन प्लेटफार्मों का उपयोग शैक्षिक सामग्री को व्यापक दर्शकों तक प्रसारित करने के लिए किया जाता है , विशेष रूप से सीमित इंटरनेट पहुंच वाले क्षेत्रों में।
- शिक्षकों के लिए ई-सामग्री: यह स्कूल और शिक्षक शिक्षा के लिए विभिन्न ई-पाठ्यक्रम और डिजिटल संसाधन प्रदान करता है, जिसमें शिक्षकों और छात्रों के लिए इंटरैक्टिव वीडियो, ऑडियोबुक और क्विज़ जैसे डिजिटल कार्यक्रम शामिल हैं।

पीएम ई-विद्या डीटीएच चैनल 31 के बारे में:

- यह भारतीय सांकेतिक भाषा को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है, इसकी संकल्पना आईएसएल को एक भाषा के साथ-साथ एक स्कूल विषय के रूप में बढ़ावा देने के लिए की गई है, ताकि बड़ी आबादी को भाषा सीखने की सुविधा मिल सके।
- यह एक 24x7 चैनल है जो स्कूली बच्चों (केन्द्रीय एवं राज्य पाठ्यक्रम), शिक्षकों, अध्यापक प्रशिक्षकों और अन्य हितधारकों के लिए शिक्षण सामग्री का प्रसार करेगा।

स्रोत: पीआईबी

रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप (RuTAG) पहल

खबरों में क्यों?

हाल ही में, रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप (आरयूटीएजी) 2.0 परियोजनाओं की पहली वार्षिक समीक्षा बैठक शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एसकेयूएएसटी), श्रीनगर, कश्मीर में आयोजित की गई।

RuTAG पहल के बारे में :

- ग्रामीण प्रौद्योगिकी कार्य समूह (आरयूटीएजी) भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (पीएसए) के कार्यालय की एक पहल है जिसे 2004 में शुरू किया गया था।
- इसकी संकल्पना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप और समर्थन का उच्चतर स्तर प्रदान करने के तंत्र के रूप में की गई थी ।
- इस पहल के तहत, हस्तक्षेपों को मुख्य रूप से मांग-संचालित बनाया गया है, जिसमें जमीनी स्तर पर प्रौद्योगिकी अंतराल को

पाटने , प्रौद्योगिकी को उन्नत करने और नवीन परियोजनाओं के माध्यम से प्रशिक्षण और प्रदर्शन प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

- पीएसए कार्यालय ने अप्रैल 2023 में RuTAG 2.0 लॉन्च किया , जिसका उद्देश्य उत्पादों के रूप में विकसित प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण और व्यापक प्रसार पर ध्यान केंद्रित करना है, जिससे व्यापक पहुंच और सामाजिक-आर्थिक प्रभाव सुनिश्चित हो सके।
- RuTAG 2.0 पहल नवाचार को बाजार-तैयार उत्पादों में बदलने पर जोर देती है , जो ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तनकारी बदलावों को आगे बढ़ाने और सतत विकास के लिए समुदायों को सशक्त बनाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

स्रोत: पीआईबी

अमृत ज्ञान कोष पोर्टल

खबरों में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्री ने "अमृत ज्ञान कोष" पोर्टल लॉन्च किया।

अमृत ज्ञान कोष पोर्टल के बारे में:

- इसे क्षमता निर्माण आयोग और कर्मयोगी भारत द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है ।
- यह शासन प्रशिक्षण में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और शासन प्रशिक्षण को मजबूत करने का एक मंच है।
- इसे iGOT प्लेटफॉर्म पर विकसित किया गया है, जो शासन और नीति कार्यान्वयन में सर्वोत्तम प्रथाओं के व्यापक भंडार के रूप में कार्य करता है।
- यह 17 सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में से 15 के अनुरूप है, तथा इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और डिजिटल शासन जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं।
- चयनित संसाधन संकाय को भारत की अद्वितीय प्रशासनिक चुनौतियों का समाधान करते हुए अपने शिक्षण को वैश्विक मानकों के अनुरूप ढालने में सक्षम बनाते हैं।

कर्मयोगी भारत क्या है?

- मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत कार्यक्रम के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए एक व्यापक संस्थागत ढांचा तैयार किया गया है।
- कर्मयोगी भारत , एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी), संस्थागत ढांचे का एक प्रमुख स्तंभ है, जिसका उद्देश्य आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म को संचालित करना, इसके समग्र शासन का प्रबंधन करना और यह सुनिश्चित करना है कि यह सिविल सेवा अधिकारियों के लिए किसी भी समय, कहीं भी, किसी भी डिवाइस पर सीखने के उद्देश्य को पूरा करता है ताकि उनकी समग्र योग्यता में वृद्धि हो सके।
- एसपीवी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अंतर्गत कर्मयोगी भारत के नाम से 100% सरकारी स्वामित्व वाली गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में शामिल किया गया है।

स्रोत: पीआईबी

बीमा सखी योजना

खबरों में क्यों?

भारत के प्रधान मंत्री ने हाल ही में हरियाणा के पानीपत में बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया।

बीमा सखी योजना के बारे में:

- यह राज्य के स्वामित्व वाली जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की एक पहल है।
- इसे 18-70 वर्ष की आयु की उन महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बनाया गया है , जिन्होंने 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की है।
- वित्तीय साक्षरता और बीमा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए उन्हें पहले तीन वर्षों के लिए विशेष प्रशिक्षण और वजीफा दिया जाएगा।
- प्रशिक्षण के बाद, वे एलआईसी एजेंट के रूप में काम कर सकते हैं और स्नातक बीमा सखियों को एलआईसी में विकास अधिकारी की भूमिका के लिए अर्हता प्राप्त करने का अवसर मिलेगा ।
- महिला एलआईसी एजेंटों को पहले वर्ष 7,000 रुपये प्रति माह , दूसरे वर्ष 6,000 रुपये प्रति माह और तीसरे वर्ष 5,000 रुपये प्रति माह का वजीफा मिलेगा ।
- बीमा सखियों को पहले वर्ष 48,000 रुपये (बोनस को छोड़कर) का कमीशन भी मिलेगा ।
- योजना तीन वर्ष की अवधि में दो लाख बीमा सखियों की नियुक्ति करने की है।
- मौजूदा एजेंटों और कर्मचारियों के रिश्तेदार इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं और सेवानिवृत्त कर्मचारी भी अपात्र हैं।

स्रोतः बिजनेस टुडे

ब्लूटूथ लो एनर्जी गेटवे

खबरों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) रोपड़ में आईहब – एडब्ल्यूएडीएच (कृषि और जल प्रौद्योगिकी विकास केंद्र) ने राष्ट्रीय अंतःविषय साइबर-भौतिक प्रणाली मिशन (एनएम-आईसीपीएस) के तहत ब्लूटूथ लो एनर्जी गेटवे और नोड सिस्टम लॉन्च किया।

ब्लूटूथ लो एनर्जी गेटवे और नोड सिस्टम के बारे में:

- यह अपनी तरह की पहली लागत प्रभावी प्रणाली है जो ब्लूटूथ-सक्षम सेंसरों को क्लाउड प्लेटफार्मों से जोड़ती है।
- यह कृषि, लॉजिस्टिक्स और पर्यावरणीय लचीलेपन जैसे विविध क्षेत्रों में निर्बाध डेटा संचरण, वास्तविक समय पर्यावरण निगरानी और उन्नत विश्लेषण को सक्षम बनाता है ।

बीएलई गेटवे की मुख्य विशेषताएं:

- **मजबूत कनेक्टिविटी:** लचीली नेटवर्किंग के लिए 4G, WiFi और LAN संगतता प्रदान करता है।
- **लंबी दूरी का संचार:** लाइन-ऑफ-साइट (LOS) परिदृश्यों में 1 किमी तक डेटा संचरण का समर्थन करता है।
- **डेटा एकत्रीकरण:** एकाधिक जुड़े हुए नोड्स से डेटा एकत्रित और संसाधित करता है, विश्लेषण और निर्णय लेने को सुव्यवस्थित करता है।
- **मौसमरोधी और कॉम्पैक्ट डिजाइन:** कॉम्पैक्ट और उपयोगकर्ता के अनुकूल रूप को बनाए रखते हुए चरम मौसम की स्थिति में स्थायित्व प्रदान करना।
- **वायरलेस कनेक्टिविटी:** व्यापक वायरिंग की आवश्यकता को समाप्त करती है, स्थापना लागत को कम करती है और दूरस्थ तैनाती का समर्थन करती है।
- **कम बिजली की खपत:** लंबे समय तक संचालन के लिए ऊर्जा-कुशल प्रदर्शन प्रदान करता है।
- **स्केलेबिलिटी:** 100 से अधिक कनेक्टेड BLE नोड्स का प्रबंधन करता है, जो बड़े पैमाने पर IoT नेटवर्क के लिए आदर्श है।
- **फर्मवेयर ओवर-द-एयर (FOTA):** न्यूनतम मैनुअल हस्तक्षेप के साथ सिस्टम को अद्यतन रखने के लिए दूरस्थ फर्मवेयर अपडेट की अनुमति देता है।
- **अनुकूलता:** बेहतर लचीलेपन के लिए मोबाइल ऐप्स, क्लाउड प्लेटफॉर्म और विविध सेंसर के साथ एकीकरण का पूर्ण समर्थन करता है।

संभावित अनुप्रयोग

- **कृषि:** यह मृदा नमी और वायु गुणवत्ता जैसे महत्वपूर्ण कारकों की निगरानी करके परिशुद्ध खेती को समर्थन प्रदान करता है , जिससे बेहतर नियंत्रण और टिकाऊ प्रथाओं को संभव बनाया जा सके।
- **रसद:** यह शीत भंडारण और परिवहन में शीघ्र खराब होने वाले सामानों के लिए अनुकूलतम पर्यावरणीय स्थिति सुनिश्चित करता है, तथा खराब होने के जोखिम को कम करता है।
- **स्मार्ट शहर और औद्योगिक स्थल:** वे परिचालन दक्षता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर निगरानी नेटवर्क के लिए प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं।
- **वास्तविक समय डेटा संचरण :** यह तापमान में वृद्धि या अनधिकृत गतिविधियों जैसे परिवर्तनों के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया की अनुमति देता है, जिससे संभावित नुकसान कम होता है और संसाधन प्रबंधन में वृद्धि होती है।

स्रोत: पीआईबी

डीएई- होमी भाभा चेयर योजना

खबरों में क्यों?

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने राज्य सभा को डीएई-होमी भाभा चेयर योजना के बारे में जानकारी दी।

डीएई- होमी भाभा चेयर योजना के बारे में :

- इसका प्रशासन परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा किया जाता है।
- यह प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों/प्रोफेसरों के लिए है, जिसका उद्देश्य उन उत्कृष्ट वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को मान्यता और अवसर प्रदान करना है, जिनमें वे सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त वैज्ञानिक/इंजीनियर भी शामिल हैं, जो संवेदनशील और/या महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के विकास में शामिल थे, ताकि वे अपनी पसंद के क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास कार्य कर सकें और परमाणु ऊर्जा विभाग के हित में काम कर सकें।
- डीएई-होमी भाभा चेयर योजना के अंतर्गत कार्यकाल चयन समिति के विवेक पर एक से पांच वर्ष की अवधि के लिए है।
- इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक पुरस्कार विजेता को 200000/- रुपये का मानदेय मिलेगा (यदि स्वीकृत मानदेय एवं पेंशन अंतिम प्राप्त वेतन से अधिक है, तो मानदेय सेवानिवृत्ति से पूर्व अंतिम प्राप्त वेतन तक सीमित रहेगा)।
- सचिवीय सहायता, टेलीफोन बिल और स्टेशनरी जैसे व्यय को कवर करने के लिए प्रति वर्ष 76000/- रुपये का आकस्मिक अनुदान।
- पुरस्कार विजेता को पूरे कार्यकाल के दौरान एकमुश्त उपकरण भत्ता (पुस्तक भत्ते सहित) भी उपलब्ध कराया जाएगा, जो वास्तविक उपयोग के अधीन 125000/- रुपये से अधिक नहीं होगा। उपकरण भत्ते में पुस्तक भत्ते के लिए 10000/- रुपये की राशि भी शामिल है।
- यदि योजना के तहत लाभार्थी को सरकारी वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उसे एक निश्चित मासिक परिवहन भत्ता भी प्रदान किया जाता है।

स्रोत: पीआईबी

समर्थ उद्योग भारत 4.0 पहल

खबरों में क्यों?

हाल ही में भारी उद्योग एवं इस्पात राज्य मंत्री ने राज्यसभा में समर्थ उद्योग भारत 4.0 पहल के बारे में जानकारी दी।

समर्थ उद्योग भारत 4.0 पहल के बारे में :

- यह भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने की योजना के तहत भारत सरकार के भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय की एक पहल है ।
- समर्थ उद्योग में निर्माता, विक्रेता और ग्राहक मुख्य हितधारक हैं।
- भारतीय विनिर्माण उद्योगों के बीच I4.0 के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए उद्योग 4.0 के लिए अनुभवात्मक और प्रदर्शन केंद्र प्रस्तावित किए गए हैं।
- इसके अंतर्गत 4 स्मार्ट एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग और रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हब (समर्थ) केंद्र स्थापित किए गए हैं:
  - ○सेंटर फॉर इंडस्ट्री 4.0 (सी4आई4) लैब, पुणे;
  - ○आईआईटीडी-एआईए फाउंडेशन फॉर स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, आईआईटी दिल्ली;
  - ○I-4.0 इंडिया @ आईआईएससी, बेंगलुरु; और
  - ○स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग डेमो एवं डेवलपमेंट सेल, सीएमटीआई, बेंगलुरु।
- समर्थ केंद्र एमएसएमई सहित उद्योगों को कार्यबल को प्रशिक्षित करने और उन्हें उद्योग 4.0 प्रौद्योगिकियों के बारे में जागरूक करने के

लिए निम्नलिखित तरीकों से सहायता प्रदान कर रहे हैं :

○उद्योग 4.0 पर जागरूकता सेमिनार/कार्यशालाएं और ज्ञान-साझाकरण कार्यक्रम आयोजित करना;

○उद्योग 4.0 के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए उद्योगों को प्रशिक्षण देना ;

○एमएसएमई सहित स्टार्ट-अप्स को परामर्श (आईओटी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर विकास और डेटा एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में) और इनक्यूबेशन सहायता प्रदान करना।

- योजना के समर्थ केंद्र पहल के तहत उद्योग 4.0-सक्षम प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए एमएसएमई सहित किसी भी उद्योग को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है।

स्रोत: द हिंदू

चरक पहल

खबरों में क्यों?

कोयला मंत्रालय के मार्गदर्शन में, सिंगरौली स्थित कोल इंडिया शाखा नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) ने 'चरक' पहल शुरू की है।

चरक पहल के बारे में:

- सामुदायिक स्वास्थ्य: कोयलांचल के लिए एक उत्तरदायी कार्रवाई (चरक) एक नवीन स्वास्थ्य-केंद्रित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल है।
- इस परियोजना का उद्देश्य सिंगरौली क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के चिन्हित जीवन-घातक रोगों से पीड़ित रोगियों को मुफ्त उपचार प्रदान करना है ।
- नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) अपने समर्पित अस्पताल या देश भर के विशेष पैनल वाले अस्पतालों में चिन्हित जीवन-घातक बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराएगा ।
- पात्रता: सिंगरौली और सोनभद्र जिले के निवासी जिनकी सभी स्रोतों से वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपये से कम है, वे इस योजना के तहत लाभ के लिए पात्र होंगे।
- कवर किए गए रोग: इस योजना के तहत, घातक बीमारी, टीबी और संबंधित जटिलताएं, एचआईवी और संबंधित जटिलताएं, हृदय रोग, अंग प्रत्यारोपण, स्थायी विकलांगता के कारण होने वाली जलन, यकृत विकार, अचानक सुनने की क्षमता में कमी, एआरडीएस, तीव्र सर्जिकल आपात स्थिति, तंत्रिका संबंधी विकार, न्यूरोवैस्कुलर विकार, आकस्मिक आघात, गंभीर विकलांगता, मल्टीसिस्टम विकार, संयोजी ऊतक विकार, अचानक दृष्टि हानि आदि शामिल हैं।

स्रोत: पीआईबी

विज्ञान और विरासत अनुसंधान पहल

खबरों में क्यों?

हाल ही में, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने विज्ञान एवं विरासत अनुसंधान पहल (एसएचआरआई) के पांच वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में कहा कि पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ मिलाने से भारत को दूसरों के मुकाबले बढ़त मिल सकती है।

विज्ञान और विरासत अनुसंधान पहल (एसएचआरआई) के बारे में:

- यह विरासत अनुसंधान पर एक नया कार्यक्रम है ।
- इसका उद्देश्य डेटा संग्रह और विश्लेषण के लिए विविध क्षेत्रों के विशेषज्ञों को शामिल करना , नए सहयोग बनाना और सांस्कृतिक विरासत से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए व्यवहार्य प्रौद्योगिकी प्रदान करना है।
- इस पहल का उद्देश्य पूरे देश में कार्यक्रम को क्रियान्वित करना है।
- नोडल मंत्रालय: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

विज्ञान और विरासत अनुसंधान पहल (एसएचआरआई) के लक्ष्य और उद्देश्य:

- विज्ञान और विरासत अनुसंधान पहल (एसएचआरआई) की परिकल्पना इस प्रकार की गई है -

○मानव संसाधन में क्षमता निर्माण करें और नए शोधकर्ताओं को इन क्षेत्रों में काम करने के लिए प्रोत्साहित करें।

○विरासत वस्तुओं के संरक्षण के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को बढ़ावा देना , जिसमें सामग्री क्षरण प्रक्रिया, संरक्षण तकनीक, हस्तक्षेप प्रौद्योगिकियां, नई सामग्रियां, बहाली की प्रक्रियाएं और नैदानिक प्रौद्योगिकियां शामिल हो सकती हैं।

○हमारी सांस्कृतिक विरासत के अभिन्न अंग के रूप में मान्यता प्राप्त उपयोग, प्रतिनिधित्व, अभिव्यक्ति, ज्ञान और तकनीकों, समुदायों, समूहों और कुछ मामलों में व्यक्तियों की सुरक्षा करना।

○पूर्व पीढ़ियों की विरासत और कला कृतियों को संरक्षित करने के लिए नए दृष्टिकोण, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का अन्वेषण करें , जो मानव सभ्यता के विकास और वृद्धि की गवाह हैं।

○विभिन्न क्षेत्रों में पुरातत्व विज्ञान के उन्नत ज्ञान के अनुप्रयोग को बढ़ावा देना ।

○मूल्य संवर्धन के लिए जनजातीय कलाओं में क्षेत्रीय विकास गतिविधियों और तकनीकी उन्नति को बढ़ावा देना ।

स्रोत: पीआईबी

स्माइल कार्यक्रम

खबरों में क्यों?

भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने मल्टीमॉडल और एकीकृत लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम (एसएमआईएलई) कार्यक्रम के दूसरे उप-कार्यक्रम के तहत 350 मिलियन डॉलर के नीति-आधारित ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए।

स्माइल कार्यक्रम के बारे में :

- मल्टीमॉडल और एकीकृत लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम

को सुदृढ़ बनाना (एसएमआईएलई) एक कार्यक्रम -आधारित नीति-आधारित ऋण (पीबीएल) है , जो भारत में लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में व्यापक सुधार करने में सरकार को सहायता प्रदान करता है।

- कार्यक्रमगत दृष्टिकोण में दो उपकार्यक्रम शामिल हैं, जिनका उद्देश्य भारत के विनिर्माण क्षेत्र का विस्तार करना और इसकी आपूर्ति श्रृंखलाओं की लचीलापन में सुधार करना है ।
- यह पहल वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) तथा एडीबी के सहयोग से की जा रही है।

कार्यक्रम के प्रमुख स्तंभ:

- संस्थागत ढांचे को मजबूत करना: मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे के निर्बाध एकीकरण के लिए राष्ट्रीय, राज्य और शहर स्तर पर क्षमता विकसित करना।
- भंडारण का मानकीकरण: आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुव्यवस्थित करने और निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए एकसमान मानक स्थापित करना।
- व्यापार रसद में सुधार: भारत के बाह्य व्यापार परिचालन की दक्षता में वृद्धि।
- स्मार्ट, कम उत्सर्जन प्रणालियों को बढ़ावा देना: पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हुए दक्षता बढ़ाने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना।

स्रोतः बिजनेस स्टैंडर्ड

RACE IAS

जापानी इन्सेफेलाइटिस

खबरों में क्यों?

आधिकारिक सूत्रों ने हाल ही में बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में जापानी इंसेफेलाइटिस का एक "पृथक" मामला सामने आया है।

जापानी इंसेफेलाइटिस के बारे में:

- यह जापानी इंसेफेलाइटिस (बी) वायरस के कारण होने वाला एक संभावित गंभीर वायरल जूनोटिक रोग है।

वायरस का संचरण :

- यह वायरस पशुओं , विशेषकर सूअरों और आर्डेइडे परिवार के पक्षियों, जैसे मवेशी बगुले, तालाब बगुले आदि से मनुष्यों में विष्णुई समूह के क्यूलेक्स मच्छर द्वारा फैलता है।
- इस वायरस का मानव-से-मानव संचरण नहीं होता है ।
- यह रोग एशिया के ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक पाया जाता है , विशेषकर मानसून के मौसम में जब मच्छरों का प्रजनन अधिक होता है।

वायरस के लक्षण:

- यह मस्तिष्क को प्रभावित करता है , जिसके परिणामस्वरूप बुखार, सिरदर्द, उल्टी और तंत्रिका संबंधी समस्याएं जैसे भ्रम, दौरे और पक्षाघात जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं।
- यद्यपि कई संक्रमित व्यक्तियों में हल्के लक्षण दिखाई दे सकते हैं या कोई लक्षण दिखाई नहीं दे सकते, लेकिन गंभीर मामलों में स्थायी मस्तिष्क क्षति या मृत्यु हो सकती है।

वायरस की रोकथाम और उपचार:

- टीकाकरण सबसे प्रभावी रोकथाम रणनीति है , विशेष रूप से स्थानिक क्षेत्रों में।
- प्रारंभिक निदान और सहायक उपचार से लक्षणों को प्रबंधित करने में मदद मिल सकती है, लेकिन जापानी एन्सेफलाइटिस के लिए कोई विशिष्ट एंटीवायरल उपचार नहीं है।
- केन्द्रीय सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार , 2013 से टीके की दो खुराकें सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम का हिस्सा रही हैं।

स्रोतः इंडियन एक्सप्रेस

कोरागा जनजाति

खबरों में क्यों?

केरल में राजस्व विभाग ने ऑपरेशन स्माइल नामक परियोजना के तहत कासरगोड और मंजेश्वरम तालुकों में कोरगा जनजाति (एसटी) समूह को भूमि का स्वामित्व (पट्टा) प्रदान करने के लिए कदम उठाए हैं।

कोरागा जनजाति के बारे में:

- कोरागा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) में से एक है जो भारत के दक्षिणी भाग, विशेषकर केरल और कर्नाटक में पाया जाता है।
- भाषा: वर्तमान में अधिकांश कोरागा तुलु भाषा बोलते हैं लेकिन उनकी अपनी स्वतंत्र भाषा भी है।
- कोरागा कई बहिर्विवाही कुलों या संप्रदायों में विभाजित हैं। इस कुल को बाली के नाम से जाना जाता है। कोरागा में 17 बाली पाए जाते हैं।
- अर्थव्यवस्था: कोराग मूलतः कृषक हैं और अपनी आजीविका के लिए बांस, बेंत, टोकरी बनाने के लिए लताओं जैसे वन उत्पादों पर निर्भर हैं।
- वे अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए गीत गाते हैं, लोक नृत्य करते हैं, अनुष्ठान करते हैं और जादू-टोना करते हैं, ताकि फसल अच्छी हो और महामारी दूर हो।
- ढोलू और वूटे (ड्रम और बांसुरी) कोरगा लोगों के दो महत्वपूर्ण संगीत वाद्ययंत्र हैं।
- कोरागा लोगों में परिवार मातृवंशीय होता है, जिसमें वंश का निर्धारण महिला वंश से होता है। लेकिन विवाह के बाद निवास पितृवंशीय होता है।
- संपत्ति बेटे और बेटियों दोनों के बीच बराबर-बराबर बांटी जाती है।
- कोरगा विभिन्न भुटा (भुटा कोला तुलु नाडु में एक अनुष्ठानिक लोक नृत्य है) जैसे पंजुरली, कल्लूरती, कोरथी और गुलिगा आदि के उपासक थे।

स्रोत: द हिंदू

अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 2024

खबरों में क्यों?

हर साल 3 दिसंबर को दुनिया भर से लोग अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाने के लिए एकत्रित होते हैं - यह दिन विकलांग व्यक्तियों की क्षमताओं, उपलब्धियों और अधिकारों को मान्यता देने के लिए समर्पित है।

अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस (आईडीपीडी) के बारे में:

- प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाने वाला आईडीपीडी दिवस , दुनिया भर में विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लचीलेपन, योगदान और नेतृत्व का जश्न मनाता है।
- यह दिन समावेशिता को बढ़ावा देने, दिव्यांगजनों के अधिकारों की वकालत करने तथा सभी के लिए समान अवसर सृजित करने की वैश्विक प्रतिबद्धता की याद दिलाता है।
- इस वर्ष का विषय है " समावेशी और टिकाऊ भविष्य के लिए विकलांग व्यक्तियों के नेतृत्व को बढ़ावा देना"।
- आईडीपीडी की घोषणा 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 47/3 द्वारा की गई थी।
- इसका उद्देश्य समाज और विकास के सभी क्षेत्रों में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देना तथा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन के हर पहलू में उनकी स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।

- विकलांगता के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र के कई दशकों के कार्य के आधार पर, 2006 में अपनाए गए विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन (सीआरपीडी) ने सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा और अन्य अंतर्राष्ट्रीय विकास ढांचे को लागू करने में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों और कल्याण को आगे बढ़ाया है।

भारत सरकार की पहल:

- भारत ने विभिन्न नीतियों और अभियानों के माध्यम से दिव्यांगजनों के अधिकारों और समावेशन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इनमें से कुछ पहल नीचे सूचीबद्ध हैं:
  - ○दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
  - ○सुगम्य भारत अभियान
  - ○दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस)
  - ○जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी)
  - ○दिव्यांग व्यक्तियों को सहायक उपकरण/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए सहायता (एडीआईपी) योजना।
  - ○दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के कार्यान्वयन हेतु योजनाएँ (एसआईपीडीए): यह एक व्यापक "केन्द्रीय क्षेत्र योजना" है जिसमें 10 उप-योजनाएँ शामिल हैं।

स्रोत: इंडिया टुडे

नाज़्का लाइन्स

खबरों में क्यों?

हाल ही में, शोधकर्ताओं ने पेरू में रहस्यमयी नाज़्का भू-आकृति की खोज के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग किया।

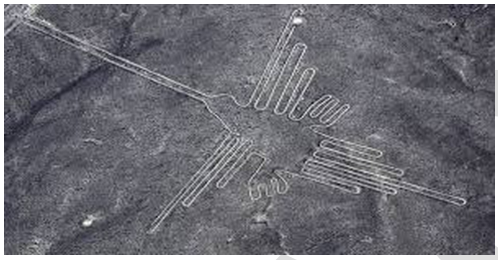

नाज़्का लाइन्स के बारे में:

- नाज़्का लाइन्स भू-आकृतियों या बड़े डिज़ाइनों का एक समूह है, जो रचनाकारों द्वारा पत्थर, बजरी, मिट्टी या लकड़ी जैसे परिदृश्य के तत्वों का उपयोग करके जमीन पर बनाए जाते हैं।
- ये लीमा से लगभग 400 किमी दक्षिण में शुष्क पेरू तटीय मैदान में स्थित हैं ।
- नाज़्का लाइनों की खोज 1920 के दशक के मध्य में पैदल यात्रियों द्वारा की गई थी और बाद में पेरू के पुरातत्वविद् टोरिबियो मेजिया ज़ेस्पे ने 1926 में उनका व्यवस्थित अध्ययन किया।
- अपने आकार, निरंतरता, प्रकृति और गुणवत्ता के कारण इन्हें सबसे बड़ी ज्ञात पुरातात्विक पहेली माना जाता है।
- वे प्राकृतिक दुनिया और मानव कल्पना दोनों से प्राणियों को चित्रित करते हैं।
  - ○इनमें मकड़ी, हमिंगबर्ड, बंदर, छिपकली, पेलिकन और यहां तक कि किलर व्हेल जैसे जानवर शामिल हैं। प्राचीन कारीगरों ने पौधों, पेड़ों, फूलों और विचित्र आकार की शानदार आकृतियों के साथ-साथ ज्यामितीय रूपांकनों , जैसे लहरदार रेखाओं, त्रिकोण, सर्पिल और आयतों को भी चित्रित किया।
- इनमें से अधिकांश रेखाएँ 200 ई.पू. से 500 ई. तक की हैं, जब नाज़्का नामक लोग इस क्षेत्र में निवास करते थे।
- पत्थरों को इकट्ठा करके बनाई गई सबसे पुरानी रेखाएँ 500 ईसा पूर्व की हैं
- 1994 में यूनेस्को द्वारा इन लाइन्स को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया ।

जियोग्लिप्ज क्या हैं?

जियोग्लिफ़्स (भूआकृति) सतह के पत्थरों, मिट्टी या बजरी को जोड़कर बनाई गई आकृतियाँ हैं ।

स्रोतः इंडियन एक्सप्रेस

स्वगृह रेटिंग

खबरों में क्यों?

हाल ही में, बिहार के कालूघाट स्थित भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के इंटरमॉडल टर्मिनल (आईएमटी) को गृह परिषद से पांच सितारा स्वगृह रेटिंग प्राप्त हुई है।

स्वगृह (SVAGRIHA) रेटिंग के बारे में:

- SVAGRIHA रेटिंग जिसका अर्थ है सरल बहुमुखी किफायती GRIHA - एकीकृत आवास मूल्यांकन (GRIHA) के लिए ग्रीन रेटिंग के तहत हरित भवनों और स्थिरता की अवधारणा का समर्थन करता है ।
- यह एक मार्गदर्शन-सह-रेटिंग प्रणाली है जिसे आवासों, वाणिज्यिक कार्यालयों, मोटलों, औषधालयों, स्कूलों आदि जैसी छोटी एकल इमारतों के लिए विकसित किया जा रहा है।
- इसे इन छोटे विकासों के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने में मदद करने के लिए विकसित किया गया है।

रेटिंग प्रणाली:

- यह केवल उन परियोजनाओं पर लागू होगा जिनका निर्मित क्षेत्रफल 2500 वर्ग मीटर से कम है।
- रेटिंग प्रणाली में 14 मानदंड हैं।
- मानदंड: मानदंडों को 5 व्यापक उप-समूहों में विभाजित किया गया है : वास्तुकला और ऊर्जा, जल और अपशिष्ट, सामग्री, परिदृश्य और जीवन शैली।
- प्रत्येक उप-समूह के अंतर्गत कुछ निश्चित बिंदुओं को प्राप्त करना अनिवार्य होगा। एक परियोजना द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले कुल अंक 50 हैं ।
- रेटिंग 1-5 स्टार पैमाने पर की जाएगी।
- इसे मार्गदर्शक मापदंडों के साथ एक सरल ऑनलाइन टूल के रूप में डिजाइन किया गया है, जो SVAGRIHA के संबंध में परियोजना के प्रदर्शन का मूल्यांकन सरल, समझने में आसान तरीके से करेगा।

कालूघाट इंटरमॉडल टर्मिनल:

- यह राष्ट्रीय जलमार्ग 1 - गंगा नदी की क्षमता वृद्धि के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) द्वारा किए गए कई बुनियादी ढाँचागत हस्तक्षेपों में से एक है ।
- टर्मिनल के निर्माण के दौरान फाइबर, रिसाइकिलेबल ग्लास, पेंट, सैनिटरी फिक्सचर आदि जैसी रिसाइकिलेबल सामग्रियों के उपयोग को सुनिश्चित करके पर्यावरणीय स्थिरता के लिए अपने प्रयासों के लिए इसे पांच सितारा रेटिंग प्राप्त हुई है ।

स्रोत: पीआईबी

घरचोलस साड़ी

खबरों में क्यों?

हाल ही में गुजरात के 'घरचोलों' को भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुआ है।

घरचोलस साड़ी के बारे में:

- इसे घाटचोला और घरचोलू के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें गुजरात का बेहतरीन बंधनी काम है
- इसका प्रयोग पारंपरिक रूप से गुजराती शादियों में वर्षों से किया जाता रहा है।
- 'घरचोला' नाम का अर्थ है ' घर के लिए पोशाक', जो नवविवाहित दुल्हन के अपने नए घर में शामिल होने का प्रतीक है।

घरचोलस साड़ी की विशेषताएँ:

- इसे रेशमी या जरी के धागों का उपयोग करके सूती या रेशमी कपड़े पर बड़े आकार में बुना जाता है।
- इसे आगे बांधनी या टाई एंड डाई तकनीक में रंगा जाता है । ये चेकर्ड पैटर्न मोर, कमल, मानव आकृतियों और पुष्प डिजाइनों के छोटे सुनहरे रूपांकनों से भरे होते हैं।
- इन्हें पारंपरिक रूप से लाल, मैरून, हरा और पीले जैसे शुभ रंगों में तैयार किया जाता है, जो हिंदू रीति-रिवाजों में विशेष महत्व रखते हैं।
- 12 वर्गों वाली घरचोला साड़ी को ' बार बाग' के नाम से जाना जाता है , जबकि 52 वर्गों वाली घरचोला साड़ी को ' बावन बाग' के नाम से जाना जाता है।
- डिजाइनों में अक्सर उर्वरता और समृद्धि के प्रतीक शामिल होते हैं , जैसे कलश और पान।
- हाल के समय में बुनकर अपने घरचोलों में आधुनिक डिजाइन और तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं , तथा परंपरा और समकालीन आकर्षण का मिश्रण कर रहे हैं।
- यह गुजरात को प्राप्त 27वां जीआई टैग है।

स्रोत: पीआईबी

भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम

खबरों में क्यों?

भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम (आईआईजीएफ) 2024 का आयोजन 9-10 दिसंबर, 2024 को भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में किया जा रहा है।

भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के बारे में :

- यह संयुक्त राष्ट्र इंटरनेट गवर्नेंस फोरम (यूएन आईजीएफ) का भारतीय अध्याय है।
- यह एक वैश्विक बहु-हितधारक मंच है जो इंटरनेट से संबंधित सार्वजनिक नीति मुद्दों पर संवाद को बढ़ावा देता है ।
- 2021 में स्थापित, इसका उद्देश्य संबंधित चुनौतियों और जोखिमों का समाधान करते हुए इंटरनेट के अवसरों को अधिकतम करना है।
- आईआईजीएफ सरकार, नागरिक समाज, उद्योग, तकनीकी समुदायों, थिंक टैंक और उद्योग संघों के प्रतिनिधियों के बीच सहयोगात्मक चर्चा को बढ़ावा देता है।
- यह 14 सदस्यीय बहु-हितधारक समिति, IIGF द्वारा समर्थित है। अपने समावेशी और सहयोगी दृष्टिकोण के लिए जाना जाने वाला IGF, खुले, सुरक्षित और सुलभ इंटरनेट के लिए नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, साइबर सुरक्षा, डिजिटल समावेशन, डेटा गोपनीयता और उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे मुद्दों को संबोधित करता है।

IIGF-2024 के बारे में मुख्य बातें:

- इसे इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) और भारतीय राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज (NIXI) द्वारा समर्थित किया गया है।
- भारत के बहु-हितधारक समुदाय द्वारा की गई इस पहल का उद्देश्य इंटरनेट शासन के महत्वपूर्ण पहलुओं का पता लगाना, सार्थक संवाद को बढ़ावा देना और वैश्विक डिजिटल परिदृश्य में भारत के नेतृत्व को उजागर करना है।
- यह एक सुरक्षित, समावेशी और टिकाऊ डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेगा। यह फोरम संतुलित, विकासोन्मुखी नीतियों को बनाने के लिए कानूनी और नियामक ढाँचों की खोज करेगा जो इंटरनेट शासन को मजबूत करते हैं।
- एक अन्य प्रमुख फोकस जिम्मेदार एआई है , जो सामाजिक लाभ के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नैतिक और प्रभावी उपयोग को बढ़ावा देता है ।

स्रोत: पीआईबी

RACE IAS

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार

खबरों में क्यों?

पंचायती राज मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सम्मान समारोह 2024, विज्ञान भवन, नई दिल्ली में होगा।

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के बारे में:

- ये पुरस्कार गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य, बाल कल्याण, जल संरक्षण, स्वच्छता, बुनियादी ढांचे, सामाजिक न्याय, शासन और महिला सशक्तिकरण में पंचायतों के प्रयासों को मान्यता देने और प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण हैं ।
- इन पुरस्कारों को नया रूप दिया गया है और इन्हें वर्ष 2022 के दौरान 17 सतत विकास लक्ष्यों (एलएसडीजी) के स्थानीयकरण के 9 विषयों के साथ संरेखित करते हुए लॉन्च किया गया है।
- इस प्रतियोगिता का प्राथमिक उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में पंचायतों के प्रदर्शन का आकलन करना, उनके बीच प्रतिस्पर्धात्मक भावना को बढ़ावा देना और 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करना है।
- ये 9 एलएसडीजी थीम हैं: गरीबी मुक्त और उन्नत आजीविका पंचायत, स्वस्थ पंचायत, बाल-अनुकूल पंचायत, जल-पर्याप्त पंचायत, स्वच्छ और हरित पंचायत, पंचायत में आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा, सामाजिक रूप से न्यायसंगत और सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत, सुशासन वाली पंचायत और महिला-अनुकूल पंचायत।
- यह पुरस्कार निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत प्रदान किया गया है:

  ○दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार (डीडीयूपीएसवीपी): यह पुरस्कार ऊपर उल्लिखित 9 पुरस्कार विषयों में से प्रत्येक के अंतर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शीर्ष-3 रैंकिंग वाली ग्राम पंचायतों/समकक्ष निकायों के लिए है।

  ○नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार: यह पुरस्कार डीडीयूपीएसवीपी के सभी 9 पुरस्कार विषयों के अंतर्गत उनके समग्र प्रदर्शन के लिए शीर्ष 3 ग्राम, ब्लॉक और जिला पंचायतों के लिए है।

पुरस्कारों की विशेष श्रेणियां:

○ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को अपनाने और उपयोग में उनके प्रदर्शन के लिए शीर्ष 3 ग्राम पंचायतों/समकक्ष निकायों को दिया जाता है।

○कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार अक्षय ऊर्जा स्रोतों को अपनाने और उनके उपयोग में उनके प्रदर्शन के लिए शीर्ष 3 ग्राम पंचायतों/समतुल्य निकायों के लिए है । इस वर्ष, इस श्रेणी के अंतर्गत कुल 3 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं।

○पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार देश भर के 3 संस्थानों के लिए है, जिन्होंने एलएसडीजी प्राप्त करने में जीपी को संस्थागत सहायता प्रदान की है।

स्रोत: पीआईबी

मेली-एमिली

खबरों में क्यों?

प्रतिष्ठित पत्रिका 'फूड फ्रंटियर्स' में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन में बताया गया है कि त्रिपुरा की पारंपरिक किण्वित बांस की किस्म, जिसे लोकप्रिय रूप से 'मेली-एमिली' कहा जाता है, और इसमे मोटापा-रोधी प्रभाव होता है।

मेली-एमिली के बारे में:

- यह त्रिपुरा की एक पारंपरिक किण्वित बांस की किस्म है।
- इसमें मोटापा-रोधी प्रभाव है और यह वजन प्रबंधन और चयापचय स्वास्थ्य के लिए एक समाधान प्रदान करता है।
- यह लिपिड संचयन को कम करता है और फैटी एसिड β-ऑक्सीकरण को बढ़ाता है।

शोध के मुख्य बिंदु:

- इन-विट्रो सेल कल्चर अध्ययनों के आधार पर, टीम ने पाया है कि 'मेली-एमिली' अंतरकोशिकीय लिपिड संचयन को कम कर सकता है।
- इस प्रक्रिया में लिपोलाइटिक (एचएसएल, एलपीएल, और एजीटीएल) और वसा ब्राउनिंग नियामक जीन (यूसीपी1, पीआरडीएम16, और पीजीसी1-अल्फा) की अभिव्यक्ति में वृद्धि शामिल थी।
- इसके अलावा, अध्ययन से पता चलता है कि मेलिए-एमिली के साथ उपचार से एएमपीके सिग्नलिंग मार्ग के माध्यम से थर्मोजेनिक प्रोटीन अभिव्यक्ति का उत्थान होता है।
- यह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रियल जैवजनन को उत्तेजित करती है और फैटी एसिड β-ऑक्सीकरण को बढ़ाती है, जिससे वजन प्रबंधन और चयापचय स्वास्थ्य के लिए एक बहुमुखी दृष्टिकोण मिलता है।
- इन निष्कर्षों से पता चलता है कि किण्वित बांस की टहनियों का अर्क श्वेत वसाकोशिकाओं में ऊर्जा व्यय को बढ़ाकर मोटापा-रोधी प्रभाव डालता है।

स्रोत: पीआईबी

भारत कौशल रिपोर्ट 2025

खबरों में क्यों?

भारत कौशल रिपोर्ट 2025' के अनुसार, भारत में स्नातकों के बीच रोजगार योग्यता 2025 तक 7

प्रतिशत बढ़कर 54.81 प्रतिशत तक पहुंचने की उम्मीद है।

भारत कौशल रिपोर्ट 2025 के बारे में:

- इसे उद्योग निकाय भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने व्हीबॉक्स (एक प्रतिभा मूल्यांकन एजेंसी) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के सहयोग से तैयार किया है ।
- यह रिपोर्ट भारत भर में ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट (जीईटी) में भाग लेने वाले 6.5 लाख से अधिक उम्मीदवारों के आंकड़ों पर आधारित है , साथ ही 15 विविध उद्योगों के 1,000 से अधिक निगमों से प्राप्त जानकारी पर भी आधारित है।

रिपोर्ट की मुख्य बातें:

- 2025 में लगभग 55 प्रतिशत भारतीय स्नातकों के वैश्विक स्तर पर रोजगार योग्य होने की उम्मीद है , जो 2024 में 51.2 प्रतिशत (सात प्रतिशत की वृद्धि) से अधिक है।
- इसमें कहा गया है कि प्रबंधन स्नातकों (78 प्रतिशत) की वैश्विक रोजगार संभावना सबसे अधिक है, इसके बाद इंजीनियरिंग छात्र (71.5 प्रतिशत), एमसीए छात्र (71 प्रतिशत) और विज्ञान स्नातक (58 प्रतिशत) का स्थान है।
- महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली जैसे राज्य रोजगार योग्य प्रतिभाओं के लिए प्रमुख केन्द्र के रूप में उभर रहे हैं , जबकि पुणे, बेंगलुरु और मुंबई जैसे शहर कुशल कार्यबल उपलब्ध कराने में अग्रणी हैं ।
- लिंग विश्लेषण से पता चलता है कि पुरुषों के लिए रोजगार दर 2024 में 51.8 प्रतिशत से बढ़कर 2025 में 5 प्रतिशत हो जाने की उम्मीद है।
- इस बीच, महिलाओं के लिए रोजगार योग्यता दर इसी अवधि के दौरान 50.9 प्रतिशत से घटकर 47.5 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है ।
- 2025 में, माध्यमिक और तृतीयक स्तर के 50 प्रतिशत छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त होने की उम्मीद है, जिससे भारत वैश्विक प्रतिभा बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित हो जाएगा।
- रिपोर्ट में व्यावसायिक प्रशिक्षण को उद्योग की जरूरतों के साथ एकीकृत करने के महत्व पर बल दिया गया है, विशेष रूप से एआई, साइबर सुरक्षा और हरित ऊर्जा जैसे उभरते क्षेत्रों में।

स्रोत: द हिंदू

उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण

खबरों में क्यों?

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नवीनतम उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण के अनुसार, सामान्य आर्थिक स्थिति, रोजगार परिदृश्य, अपनी आय और व्यय के बारे में भारतीय उपभोक्ताओं का विश्वास कमजोर हुआ है।

उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (सीसीएस) के बारे में:

- यह एक सर्वेक्षण है जो यह बताता है कि उपभोक्ता अपनी अपेक्षित वित्तीय स्थिति के संबंध में कितने आशावादी या निराशावादी हैं ।
- यदि उपभोक्ता आशावादी हैं, तो वे अधिक खर्च करेंगे, जबकि यदि वे इतने आश्वस्त नहीं हैं, तो उनके खराब उपभोग पैटर्न के कारण मंदी आ सकती है।
- इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा द्विमासिक रूप से जारी किया जाता है।

  ○उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण के संकेतक:

  ○वर्तमान स्थिति सूचकांक (सीएसआई)

  ○भविष्य प्रत्याशा सूचकांक (एफईआई)

उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण की मुख्य बातें:

- परिवारों ने कीमतों को छोड़कर प्रमुख आर्थिक मापदंडों के लिए एक वर्ष आगे के परिदृश्य पर कुछ अधिक आशावादी रुख प्रदर्शित किया।
- नवीनतम सर्वेक्षण में भविष्य अपेक्षा सूचकांक (एफईआई) 0.5 अंक बढ़कर 121.9 हो गया।
- सीसीएस सर्वेक्षण से पता चला है कि परिवारों को आवश्यक और गैर-आवश्यक खर्चों में वृद्धि के कारण एक वर्ष की अवधि में अधिक खर्च की उम्मीद है
- घरेलू खर्च को छोड़कर सर्वेक्षण मापदंडों में कमजोर भावनाओं के कारण वर्तमान अवधि के लिए उपभोक्ता विश्वास में मामूली गिरावट आई।
- वर्तमान स्थिति सूचकांक (सीएसआई) सितम्बर 2024 में 94.7 से 0.7 अंक घटकर नवम्बर 2024 में 94 हो जाएगा।

स्रोतः इंडियन एक्सप्रेस

भौगोलिक संकेत टैग किए गए उत्पाद

खबरों में क्यों?

हाल ही में, अष्टलक्ष्मी 2024 कार्यक्रम के दौरान कई भौगोलिक संकेत टैग वाले उत्पादों का प्रदर्शन किया गया।

हाल ही में भौगोलिक संकेत टैग वाले उत्पादों के बारे में:

आदि केकिर अदरक:

- यह अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी में आदि जनजाति द्वारा उगाया जाता है।
- यह सुगंधित अदरक अपने औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध है , जो पाचन संबंधी समस्याओं से लेकर मासिक धर्म के दर्द तक हर चीज में सहायता करता है।

दल्ले खुर्सानी:

- यह सिक्किम में उगाई जाने वाली तीखी लाल मिर्च है , जिसने भारत की सीमाओं से परे भी प्रसिद्धि अर्जित की है।
- इसे संरक्षित जैविक परिस्थितियों में उगाया जाता है ; यह मिर्च अपने तीखेपन के लिए प्रसिद्ध है, स्थानीय अचार और पेस्ट में प्रयोग की जाती है , तथा इसके औषधीय गुणों के लिए भी प्रसिद्ध है।
- 5,000 से अधिक स्थानीय परिवार अपनी आजीविका के लिए इस पर निर्भर हैं।

नागा राजा चिल्ली या राजा मिर्चा:

- यह नागालैंड में उगाया जाता है और यह दुनिया की सबसे तीखी मिर्चों में से एक है।
- यह नागा लोगों के अपनी भूमि और सांस्कृतिक विरासत से गहरे जुड़ाव को भी दर्शाता है।
- लगभग 100 परिवारों द्वारा सावधानीपूर्वक उगाई गई यह तीखी मिर्च नागालैंड के ऊंचे-ऊंचे, आर्द्र जलवायु में पनपती है , तथा इसका फल तीखेपन और स्वाद से भरपूर होता है।
- नागा व्यंजनों में मिर्च एक अभिन्न भूमिका निभाती है, जो पारंपरिक व्यंजनों में मसाला और गहराई जोड़ती है।

काजी निमु:

- यह नींबू की एक विशिष्ट किस्म है जो अपने आकार, सुगंध और तीखे स्वाद के लिए प्रसिद्ध है, तथा राज्य की समृद्ध कृषि विरासत को दर्शाती है।
- अन्य नींबू किस्मों की तुलना में बड़ा और अधिक स्वादिष्ट, काजी निमू असमिया व्यंजनों और पारंपरिक उपचारों में एक आवश्यक सामग्री है।

भौगोलिक संकेत के बारे में

- यह उन उत्पादों पर लगाया जाने वाला एक लेबल है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है और जिनकी विशेषताएं किसी विशेष स्थान से जुड़ी होती हैं।
- जीआई टैग भारत में भौगोलिक संकेत टैग का संक्षिप्त रूप है। यह 15 सितंबर 2003 को लागू हुआ।
- यह उन उत्पादों पर उपयोग किया जाने वाला एक चिन्ह है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है और उस उत्पत्ति के कारण उनकी गुणवत्ता या प्रतिष्ठा होती है।
- ऐसा नाम गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देता है जो अनिवार्य रूप से उस परिभाषित भौगोलिक इलाके में इसकी उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है।
- भारत में जिन उत्पादों को भौगोलिक संकेत टैग दिया जाता है, उन्हें अतुल्य भारत का अमूल्य खजाना माना जाता है।
- यह टैग 10 साल की अवधि के लिए वैध है जिसके बाद इसे नवीनीकृत किया जा सकता है।
- केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने भारत के भौगोलिक संकेतों (जीआई) के लिए लोगो और टैगलाइन लॉन्च की थी।
- भारत में जीआई टैग पाने वाला पहला उत्पाद 2004 में दार्जिलिंग चाय था।

स्रोत: पीआईबी

विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024

खबरों में क्यों?

विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024 के अनुसार, भारत में मलेरिया के मामले 2017 में 6.4 मिलियन से 2023 में 2 मिलियन तक 69% कम हो गए हैं। मृत्यु दर 68% घटकर 11,100 से 3,500 रह गई है।

विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024 के बारे में:

- यह विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा जारी की जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट है ।
- यह मलेरिया के विरुद्ध लड़ाई में वैश्विक प्रगति और अंतराल का आकलन करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करता है।

2024 रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं:

- रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पर 2023 में मलेरिया के अनुमानित 263 मिलियन मामले और 597,000 मौतें होने का उल्लेख किया गया है , जो 2022 की तुलना में 11 मिलियन मामलों की वृद्धि दर्शाता है , तथा मृत्यु दर लगभग समान रहेगी।
- अफ्रीका इस बीमारी का दंश झेल रहा है, जहां वैश्विक स्तर पर 94 प्रतिशत मामले और 2023 में मलेरिया से होने वाली 95 प्रतिशत मौतें होंगी , जिसमें 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर 76 प्रतिशत होगी।
- चार देशों - नाइजीरिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, नाइजर और तंजानिया - ने इस क्षेत्र की आधी से अधिक मौतों में योगदान दिया ।
- भारत के संबंध में रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि उच्च-स्थानिक राज्यों में मलेरिया की घटनाओं और मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी के कारण देश आधिकारिक तौर पर 2024 में उच्च बोझ से उच्च प्रभाव (HBHI) समूह से बाहर निकल जाएगा ।
- भारत में मलेरिया के अनुमानित मामलों की संख्या 2017 में 6.4 मिलियन से घटकर 2023 में 2 मिलियन हो जाएगी , जो 69% की गिरावट को दर्शाता है।
- इसी प्रकार, इसी अवधि में मलेरिया से होने वाली मृत्यु दर 11,100 से घटकर 3,500 रह गई, जो 68% की कमी है।
- इन प्रगति के बावजूद, 2023 में डब्ल्यूएचओ दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में मलेरिया के सभी मामलों में से आधे भारत के होंगे , जिसमें 82.4% की कमी देखी गई, जो 2000 में 22.8 मिलियन से 2023 में 4 मिलियन तक पहुंच गई।
- विश्व की एक-चौथाई आबादी का घर यह क्षेत्र 2023 में वैश्विक मलेरिया मामलों का 5% प्रतिनिधित्व करेगा।

स्रोत: द न्यू इंडियन एक्सप्रेस

रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024

खबरों में क्यों?

रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024, हाल ही में लोकसभा में व्यवधानों के बावजूद पारित हो गया।

रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024 के बारे में:

- इस विधेयक के माध्यम से, पूर्ववर्ती औपनिवेशिक युग के भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम, 1905 के सभी प्रावधानों को रेलवे अधिनियम, 1989 में शामिल करने का प्रस्ताव है ।
- इसका उद्देश्य कानूनी ढांचे को सरल बनाना तथा दो कानूनों का संदर्भ लेने की आवश्यकता को कम करना है ।
- विधेयक में रेलवे अधिनियम, 1989 में संशोधन का भी प्रस्ताव है , ताकि रेलवे बोर्ड को वैधानिक समर्थन प्रदान किया जा सके , जो अपने कार्य आरंभ करने के बाद से ही बिना किसी मंजूरी के कार्य कर रहा है।
- वैधानिक शक्तियों का उद्देश्य रेलवे बोर्ड की कार्यप्रणाली और स्वतंत्रता को बढ़ाना है ।
- यह विधेयक केंद्र सरकार को रेलवे बोर्ड की संरचना तय करने का भी अधिकार देता है।
- इसमें सदस्यों की संख्या, उनकी सेवा की शर्तें, उनकी योग्यताएं और अनुभव शामिल हैं ।
- स्वतंत्र नियामक : विधेयक में रेलवे में टैरिफ, सुरक्षा और निजी क्षेत्र की भागीदारी की निगरानी के लिए एक स्वतंत्र नियामक स्थापित करने का प्रस्ताव है।
- विधेयक में परिचालन क्षमता में सुधार लाने, शक्तियों का विकेंद्रीकरण करने तथा रेलवे जोनों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने का भी प्रस्ताव है ।
- इस संशोधन से ट्रेन सेवाओं के लिए अनुमोदन प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है , जिससे विभिन्न क्षेत्रों की लंबित मांगों को पूरा करने में मदद मिलेगी।
- यह विधेयक सरकार को बुनियादी ढांचे और सुपरफास्ट रेल परिचालन में तेजी लाने की अनुमति देगा।

स्रोत: द हिंदू

हाइपरलूप ट्रैक

खबरों में क्यों?

हाल ही में, आईआईटी मद्रास ने 410 मीटर का हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक पूरा किया है, जो भविष्य की परिवहन प्रणालियों की ओर भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

हाइपरलूप ट्रैक के बारे में:

- हाइपरलूप एक उच्च गति वाली परिवहन प्रणाली है , जिसमें पॉड्स, दबावयुक्त वाहनों के रूप में कार्य करते हुए, कम दबाव वाली नलियों के माध्यम से अविश्वसनीय गति से यात्रा करते हैं।
- हाइपरलूप अवधारणा को मूलतः 2012 में एलन मस्क द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था।
- कार्यविधि: ये रेलगाड़ियां वैक्यूम-सीलबंद ट्यूबों के भीतर संचालित होती हैं , जिससे घर्षण में काफी कमी आती है तथा यात्रा की गति और ऊर्जा दक्षता में अभूतपूर्व वृद्धि होती है।
- हाइपरलूप पॉड्स को 1,100 किमी प्रति घंटे तक की गति तक पहुंचने के लिए डिज़ाइन किया गया है , जिसकी परिचालन क्रूज़िंग गति लगभग 360 किमी प्रति घंटा है ।

प्रमुख घटकों में शामिल हैं:

- निम्न-दबाव ट्यूब: वायु प्रतिरोध को न्यूनतम करने के लिए सीलबंद।
- चुंबकीय उत्तोलन (मैग्लेव): पॉड्स चुम्बकों पर "तैरते" हैं, जिससे घर्षण समाप्त हो जाता है।
- रैखिक इलेक्ट्रिक मोटर्स: पॉड को सुचारू रूप से और कुशलतापूर्वक आगे बढ़ाता है।
- ये विशेषताएं मिलकर शून्य प्रत्यक्ष उत्सर्जन के साथ बेजोड़ गति और दक्षता प्रदान करती हैं - जिससे हाइपरलूप हरित परिवहन का सर्वोत्तम साधन बन जाता है।
- भारत की हाइपरलूप परियोजना भारतीय रेलवे, आईआईटी-मद्रास की आविष्कार हाइपरलूप टीम और टीयूटीआर (इनक्यूबेटेड स्टार्टअप) की एक संयुक्त पहल है।
- भारत के लिए महत्व: इस नवीन प्रणाली को कुशल और टिकाऊ परिवहन की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए एक आशाजनक समाधान के रूप में देखा जा रहा है।

स्रोत: द हिंदू

एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट (एबीपी)

खबरों में क्यों?

विश्व डोपिंग रोधी एजें सी (वाडा) ने एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट (एबीपी) के प्रबंधन के लिए एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई (एपीएमयू) के रूप में राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (एनडीटीएल) को मंजूरी दे दी है।

एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट (एबीपी) के बारे में:

- यह एक उन्नत एंटी-डोपिंग उपकरण है जो समय के साथ एथलीट के जैविक मार्करों पर नज़र रखता है।
- रक्त और स्टेरॉयड प्रोफाइल जैसे मापदंडों में भिन्नता का विश्लेषण करके , एबीपी खेलों में निष्पक्ष खेल सुनिश्चित करने और स्वच्छ एथलीटों की सुरक्षा करने में मदद करता है।
- यह उन्नत लक्ष्य परीक्षण और विश्लेषण , जांच, निवारण और निषिद्ध तरीकों या पदार्थों के उपयोग के लिए अप्रत्यक्ष साक्ष्य के माध्यम से डोपिंग के खिलाफ काम करता है।
  - ○इसका उपयोग असामान्य प्रोफाइल वाले एथलीटों पर लक्षित, पारंपरिक एंटी-डोपिंग परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है।
  - ○इसका उपयोग डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन मामले में डोपिंग के पुष्टि साक्ष्य के रूप में भी किया जा सकता है।

- वर्तमान में एबीपी कार्यक्रम में तीन मॉड्यूल कार्यान्वित किए गए हैं:
  ○हेमेटोलॉजिकल मॉड्यूल: यह रक्त डोपिंग के निशानों के बारे में जानकारी एकत्र करता है। इसका उद्देश्य ऑक्सीजन परिवहन या वितरण को बढ़ाने के लिए निषिद्ध पदार्थों और/या निषिद्ध तरीकों के उपयोग की पहचान करना है ।
  ○स्टेरॉयडल मॉड्यूल: यह मूत्र और/या सीरम में मापे गए स्टेरॉयड डोपिंग के मार्करों के बारे में जानकारी एकत्र करता है । इसका उद्देश्य बहिर्जात रूप से प्रशासित होने पर एंडोजेनस एनेबोलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड (ईएएएस) की पहचान करना है ।
  ○एंडोक्राइन मॉड्यूल: यह मानव विकास हार्मोन (एचजीएच) डोपिंग के साथ-साथ एचजीएच एनालॉग के उपयोग के मार्करों पर जानकारी एकत्र करता है ।

स्रोत: पीआईबी

खोज और बचाव सहायता उपकरण (SARAT)

खबरों में क्यों?

हाल ही में, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) के तहत भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS) ने अपने स्वयं के खोज और बचाव सहायता उपकरण (SARAT) का एक नया संस्करण विकसित किया है।

खोज और बचाव सहायता उपकरण के बारे में :

- इसे 2016 में संकटग्रस्त व्यक्तियों/जहाजों का कम से कम समय में पता लगाने के लिए समुद्र में खोज और बचाव कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए लॉन्च किया गया था।
- इसे मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया है तथा भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (आईएनसीओआईएस) द्वारा विकसित किया गया है।
- उपयोगकर्ता के पास 60 प्रकार की लुप्त वस्तुओं (आकार और उछाल के आधार पर) का चयन करने का विकल्प है।
- उपयोगकर्ता इंटरैक्टिव मानचित्र का उपयोग करके एक विशिष्ट बिंदु का चयन कर सकते हैं जहां वस्तु को अंतिम बार देखा गया था या वे तटीय स्थान, यात्रा की गई दूरी और दिशा कोण का भी चयन कर सकते हैं ताकि गुम वस्तु के अंतिम ज्ञात स्थान का अनुमान लगाया जा सके।
- उत्पन्न परिणामों को एक इंटरेक्टिव मानचित्र में प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें खोजे जाने वाले संभावित क्षेत्र को दर्शाया जाता है तथा उन्हें ईमेल/मोबाइल फोन पर टेक्स्ट संदेश के रूप में भी भेजा जाता है।
- सभी अनुरोध और प्रतिक्रियाएं तटीय राज्यों की भाषाओं में प्रदान की जाती हैं ताकि स्थानीय मछुआरे संकट में फंसे अपने साथी मछुआरों की खोज के लिए तुरंत उनका उपयोग कर सकें।
- SARAT संस्करण 2 में , जिस स्थान से खोज क्षेत्र का विस्तार होता है उसे अब वस्तु की अंतिम ज्ञात स्थिति के रूप में संशोधित कर दिया गया है।
- यह लुप्त वस्तु को खोजने के संभावित क्षेत्र के बेहतर निर्णय के लिए बेहतर दृश्यावलोकन , खोज क्षेत्रों की रंग-कोडिंग और वस्तु की अंतिम ज्ञात स्थिति की आसान पहचान के लिए मार्कर प्रदान करता है।

खोज एवं बचाव सहायता उपकरण की कार्यप्रणाली:

- यह उपकरण मॉडल संयोजन का उपयोग करता है, जो लापता वस्तु के प्रारंभिक स्थान तथा अंतिम ज्ञात समय की अनिश्चितताओं को ध्यान में रखता है, ताकि उच्च संभावना के साथ व्यक्ति या वस्तु का पता लगाया जा सके।
- लुप्त वस्तुओं की गति मुख्यतः धाराओं और हवाओं द्वारा नियंत्रित होती है।
- यह उपकरण , INCOIS के उच्च-प्रदर्शन कम्प्यूटरों पर संचालित, अत्यधिक उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाले क्षेत्रीय महासागर मॉडलिंग सिस्टम से प्राप्त मॉडल धाराओं पर आधारित है ।

स्रोत: द हिंदू

राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार

खबरों में क्यों?

हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित किया।

राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार के बारे में :

- यह विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) की एक पहल है ।
- इसकी स्थापना 1991 में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस (14 दिसंबर) की घोषणा के साथ की गई थी ।
- ये पुरस्कार उन औद्योगिक इकाइयों, संस्थाओं और प्रतिष्ठानों के असाधारण प्रयासों को सम्मानित करते हैं, जिन्होंने अपनी परिचालन दक्षता को बनाए रखते हुए या बढ़ाते हुए ऊर्जा की खपत को काफी कम कर दिया है।

चयन प्रक्रिया

○सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता वाली पुरस्कार समिति एनईसीए के लिए पात्र क्षेत्रों की समीक्षा और अनुमोदन करती है।
○प्रस्तुत आवेदनों का मूल्यांकन एक तकनीकी समिति द्वारा किया जाता है , जिसकी अध्यक्षता सदस्य (थर्मल), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) करते हैं, और जिसमें रेल मंत्रालय, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (ईईएसएल), राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी), केंद्रीय लुगदी और कागज अनुसंधान संस्थान (सीपीपीआरआई), और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।
○इसके बाद, तकनीकी समिति की सिफारिशें अंतिम विचार और अनुमोदन के लिए पुरस्कार समिति को प्रस्तुत की जाती हैं।
○विभिन्न क्षेत्रों से चयनित पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर सम्मानित और सम्मानित किया जाता है

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के बारे में मुख्य तथ्य

- इसकी स्थापना 1 मार्च 2002 को ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के प्रावधानों के तहत की गई थी ।
- ब्यूरो का मिशन स्व-नियमन और बाजार सिद्धांतों पर जोर देते हुए नीतियों और रणनीतियों को विकसित करने में सहायता करना है।
- इसका एक प्रमुख उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था की ऊर्जा तीव्रता को कम करना है ।
- यह नामित उपभोक्ताओं, नामित एजेंसियों और अन्य संगठनों के साथ समन्वय करता है।
- यह अधिनियम के तहत सौंपे गए कार्यों के निष्पादन में विद्यमान संसाधनों और अवसंरचना को मान्यता प्रदान करता है, उनकी पहचान करता है तथा उनका उपयोग करता है।
- अधिनियम में विनियामक और संवर्धनात्मक कार्यों का भी प्रावधान है।

स्रोत: पीआईबी

जलवाहक योजना

खबरों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से माल ढुलाई को प्रोत्साहित करने के लिए 'जलवाहक' योजना शुरू की।

जलवाहक योजना के बारे में :

- इसका उद्देश्य अंतर्देशीय जलमार्गों की व्यापार क्षमता को खोलना है, साथ ही रसद लागत को कम करना तथा सड़क और रेल नेटवर्क पर भीड़भाड़ कम करना है।
- कार्यान्वयनकर्ता: इसे भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) और अंतर्देशीय एवं तटीय शिपिंग लिमिटेड (आईसीएसएल) द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित किया जाता है।

जलवाहक योजना की विशेषताएँ:

- इस योजना के तहत, जलमार्ग के माध्यम से 300 किलोमीटर से अधिक दूरी तक माल परिवहन करने वाले कार्गो मालिकों को परिचालन लागत पर 35 प्रतिशत तक की प्रतिपूर्ति मिलेगी ।
- यह योजना तीन वर्षों तक वैध रहेगी और इसे प्रमुख शिपिंग कम्पनियों, माल भाड़ा अग्रेषणकर्ताओं और व्यापार निकायों के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं को अनुकूलित करने के लिए तैयार किया गया है।
- यह राष्ट्रीय जलमार्ग 1 (गंगा), 2 (ब्रह्मपुत्र) और 16 (बराक नदी) पर टिकाऊ और लागत प्रभावी परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है ।
- जलवाहक योजना लंबी दूरी के माल परिवहन को प्रोत्साहित करती है और नियमित माल सेवाओं के माध्यम से समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करती है।
- यह हल्दिया से एनडब्ल्यू 1 और एनडब्ल्यू 2 के लिए मालवाहक जहाजों की निश्चित अनुसूचित सेवा की शुरुआत है।
- निश्चित दिवस अनुसूचित नौकायन सेवा भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट (आईबीपीआर) के माध्यम से राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के कोलकाता-पटना-वाराणसी-पटना-कोलकाता खंड और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 पर कोलकाता और गुवाहाटी के पांडु के बीच जहाजों का परिचालन करेगी।

स्रोतः बिजनेस स्टैंडर्ड

शॉर्ट नेक क्लैम

खबरों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान (सीएमएफआरआई) के विझिंजम क्षेत्रीय केंद्र में उत्पादित शॉर्ट नेक क्लैम (पाफिया मालाबारिका) के तीन मिलियन बीज अष्टमुडी झील में छोड़े गए।

शॉर्ट नेक क्लैम के बारे में:

- आर्थिक दृष्टि से मूल्यवान बाइवाल्व मोलस्क, जिसे शॉर्ट-नेक क्लैम के नाम से जाना जाता है , केरल में खारे पानी की अष्टमुडी झील का प्रमुख मत्स्य संसाधन है।
- यह एक तेजी से बढ़ने वाली प्रजाति है, जिसका प्रजनन काल दिसंबर से फरवरी तक होता है तथा इसका अधिकतम जीवनकाल लगभग 3 वर्ष होता है।
- यह अपने पहले वर्ष में 30 मिमी की खोल लंबाई पर यौन परिपक्वता प्राप्त करता है।
- यह भारत का पहला समुद्री प्रबंधन परिषद (MSC) प्रमाणित मत्स्यपालन है।
- ये गोले अतिरिक्त आय प्रदान करते हैं , क्योंकि इनका उपयोग खनिज स्रोत के रूप में सीमेंट उत्पादन में तथा वेल्डिंग में उपयोग के लिए कार्बाइड बनाने में किया जाता है ।
- कैल्शियम कार्बाइड और रेत चूना ईंटों के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में क्लैम शैल का व्यावसायिक महत्व भी है ।
- इनका उपयोग निर्माण कार्यों में चूना जलाने, धान के खेतों और मछली फार्मों में अम्लीय मिट्टी को निष्क्रिय करने तथा बुझे चूने के रूप में भी किया जाता है।
- क्लैम्स को स्थानीय फैक्ट्री द्वारा खरीदा जाता है, गर्म किया जाता है, जमाया जाता है और खुदरा विक्रेताओं और रेस्तरांओं को बेचा जाता है, जिनमें से लगभग 80% वियतनाम, मलेशिया और थाईलैंड को निर्यात किया जाता है।
- हाल के वर्षों में, इस क्लैम के मत्स्य पालन में भारी गिरावट देखी गई है , जिससे इस संसाधन पर निर्भर हजारों मछुआरों की आजीविका खतरे में पड़ गई है।
- इसकी गिरावट के कारण पर्यावरण प्रदूषण, चारु मसल जैसी गैर-देशी प्रजातियों का आक्रमण , तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, जिनमें लवणता और पानी के तापमान में परिवर्तन आदि शामिल हैं।

स्रोत: द हिंदू

बैगा जनजाति: जोधइया बाई

खबरों में क्यों?

प्रसिद्ध बैगा आदिवासी कलाकार और पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित जोधैया बाई का लंबी बीमारी के बाद 15 दिसंबर, 2024 को 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनकी मृत्यु की खबर मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के उनके पैतृक गांव लोधा से मिली।

बैगा जनजाति के बारे में:

- बैगा जनजाति भारत के विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTGs) में से एक है । वे मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में रहते हैं ।

पारंपरिक प्रथाएँ:

- आजीविका : परंपरागत रूप से अर्ध-खानाबदोश, वे कटाई-और-जला खेती करते थे , जिसे स्थानीय रूप से "बेवर" कहा जाता था , और अब मुख्य रूप से लघु वनोपज पर निर्भर हैं ।
- गोदना : यह उनकी संस्कृति का अभिन्न अंग है, जिसमें अलग-अलग शरीर के अंगों और आयु समूहों के लिए विशिष्ट टैटू बनाए जाते हैं। टैटू रामतिला बीज (नाइजर बीज) से प्राप्त काजल का उपयोग करके बनाए जाते हैं ।
- महुआ वृक्ष : इन्हें किण्वित और आसवित करके मादक पदार्थ तैयार किया जाता है, जो इनके आहार और संस्कृति का एक अनिवार्य हिस्सा बन जाता है।

सांस्कृतिक पहचान:

- बांस : दैनिक जीवन में उपयोग होने वाला एक महत्वपूर्ण संसाधन।
- पर्यावास अधिकार : बैगा जनजाति भारत का पहला समुदाय है जिसे पर्यावास अधिकार प्रदान किया गया है , जो वनों के साथ उनके गहरे संबंध को दर्शाता है।

जोधइया बाई का योगदान:

- जोधइया बाई बैगा आदिवासी कला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी ।
- कला के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए उन्हें 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया ।
- कैनवास पर बैगा जनजातीय संस्कृति को चित्रित करने वाली उनकी कलाकृतियाँ दुनिया भर के कई देशों में प्रदर्शित की जा चुकी हैं।

स्रोत: द हिंदू

भारत वन स्थिति रिपोर्ट

खबरों में क्यों?

हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून में 'भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 (आईएसएफआर 2023) जारी की।

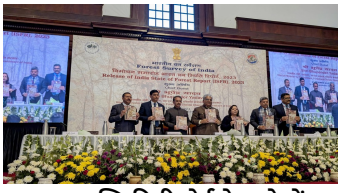

भारत वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में :

- इसे भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) द्वारा 1987 से द्विवार्षिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है।
- यह सुदूर संवेदन उपग्रह डेटा और क्षेत्र आधारित राष्ट्रीय वन सूची (एनएफआई) की व्याख्या के आधार पर देश के वन और वृक्ष संसाधनों का गहन मूल्यांकन करता है ।
- भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 इस श्रृंखला की 18वीं रिपोर्ट है।
- रिपोर्ट में वन आवरण, वृक्ष आवरण, मैंग्रोव आवरण , बढ़ते स्टॉक, भारत के वनों में कार्बन स्टॉक , वन आग की घटनाएं, कृषि वानिकी आदि के बारे में जानकारी शामिल है।

भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 की मुख्य विशेषताएं:

- भारत का वन एवं वृक्ष आवरण भौगोलिक क्षेत्र का 17 प्रतिशत है , जिसमें 21.76 % वन आवरण तथा 3.41% वृक्ष आवरण है।
- 2021 के आकलन की तुलना में देश के वन एवं वृक्ष आवरण में वृद्धि हुई है।
- वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष चार राज्य छत्तीसगढ़ , उत्तर प्रदेश , ओडिशा और हैं ।
- वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष तीन राज्य मिजोरम, गुजरात और ओडिशा हैं ।
- क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले शीर्ष तीन राज्य मध्य प्रदेश , अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र हैं
- क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले शीर्ष तीन राज्य मध्य प्रदेश , अरुणाचल प्रदेश और हैं ।
- कुल भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में वन आवरण के प्रतिशत के संदर्भ में , लक्षद्वीप (91.33 प्रतिशत) में सबसे अधिक वन आवरण है, उसके बाद मिजोरम और अंडमान एवं निकोबार द्वीप हैं
- वर्तमान आकलन से यह भी पता चलता है कि 19 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 33 प्रतिशत से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वन क्षेत्र में है। इनमें से आठ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों अर्थात् मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर में 75 प्रतिशत से अधिक वन क्षेत्र है।
- देश में कुल मैंग्रोव आवरण 4,992 वर्ग किमी है ।
- देश में बांस वाले क्षेत्र की सीमा 2021 में किए गए अंतिम आकलन की तुलना में बढ़ गई है ।
- पिछले आकलन की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में वृद्धि हुई है ।
- भारत का कार्बन स्टॉक 30.43 बिलियन टन CO_2 समतुल्य तक पहुंच गया है; जो दर्शाता है कि 2005 के आधार वर्ष की तुलना में, भारत पहले ही 2.29 बिलियन टन अतिरिक्त कार्बन सिंक तक पहुंच चुका है, जबकि 2030 तक 2.5 से 3.0 बिलियन टन का लक्ष्य रखा गया है।

स्रोत: पीआईबी

भारत समुद्री विरासत सम्मेलन

खबरों में क्यों?

बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रथम भारत समुद्री विरासत सम्मेलन (आईएमएचसी 2024) में भारत की समुद्री विरासत और वैश्विक व्यापार में योगदान का जश्न मनाया गया तथा भविष्य के नवाचारों पर चर्चा की गई।

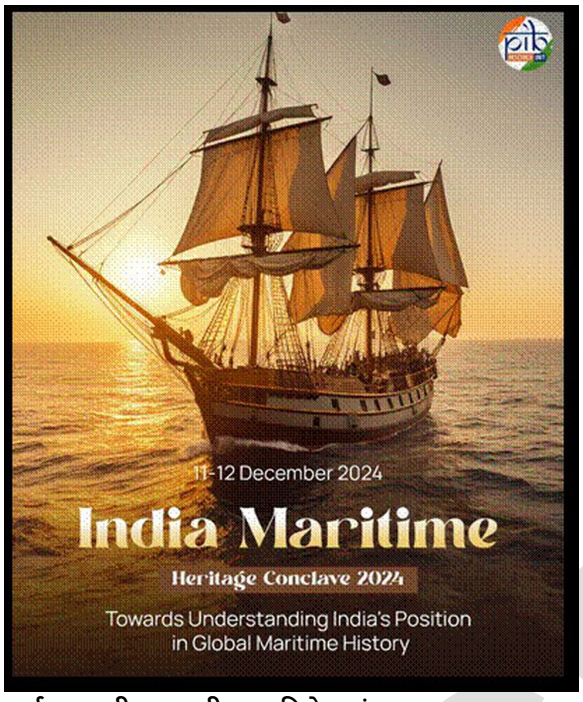

आईएमएचसी 2024 की मुख्य विशेषताएं:

- सम्मेलन का विषय था "वैश्विक समुद्री इतिहास में भारत की स्थिति को समझना" तथा वैश्विक समुद्री व्यापार, संस्कृति और नवाचार में भारत के योगदान पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- इसमें 20 से अधिक स्टालों के माध्यम से प्राचीन जहाज निर्माण तकनीक, नौवहन उपकरण और ऐतिहासिक व्यापार मार्गों का प्रदर्शन किया गया।
- ग्रीस, इटली और ब्रिटेन जैसे देशों ने इस सम्मेलन में भाग लिया और भारत के समुद्री इतिहास के वैश्विक महत्व पर जोर दिया।
- एक जीवंत सांस्कृतिक कार्यक्रम में भारत की तटीय परंपराओं का जश्न मनाया गया, जिसमें उत्सव के साथ विद्वता का मिश्रण था।
- इसमें भारत के समुद्री इतिहास और इसकी भविष्य की आकांक्षाओं पर चर्चा की गई, जिसमें समुद्री क्षेत्र में युवाओं की भूमिका, कौशल विकास और टिकाऊ प्रथाओं पर चर्चा की गई।

राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (एनएमएचसी), लोथल के बारे में मुख्य तथ्य:

- स्थान और ऐतिहासिक महत्व :
  - ○लोथल, गुजरात में स्थित , एक प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता स्थल (2600 ईसा पूर्व)।
  - ○पुरातात्विक साक्ष्यों में दुनिया का सबसे पुराना मानव निर्मित गोदी-बाड़ा भी शामिल है , जो 5,000 वर्ष से भी अधिक पुराना है ।
- एनएमएचसी की विशेषताएं : इसका लक्ष्य ऐतिहासिक और आधुनिक समुद्री गतिविधियों को एकीकृत करते हुए विश्व के सबसे बड़े समुद्री परिसरों में से एक बनना है।
- मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:
  - ○14 विषयगत दीर्घाएँ .
  - ○जलीय गैलरी और प्रकाश स्तंभ संग्रहालय खोलें .
  - ○इको-रिसॉर्ट्स , थीम पार्क और समुद्री अनुसंधान संस्थान ।

स्रोत: पीआईबी

स्पीड गन

खबरों में क्यों?

स्पीड गन का उपयोग कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा यातायात की गति पर नजर रखने तथा विभिन्न अन्य उद्योगों में व्यापक रूप से किया जाता है।

स्पीड गन के बारे में :

- यह एक ऐसा उपकरण है जो किसी गतिशील वस्तु की गति को उस वस्तु के संपर्क में आए बिना मापता है।
- इसे प्राप्त करने के लिए, उपकरण एक विशिष्ट आवृत्ति के विद्युत चुम्बकीय विकिरण को वस्तु से टकराता है, परावर्तन को पकड़ता है तथा वस्तु की गति का अनुमान लगाने के लिए डॉप्लर प्रभाव का उपयोग करता है।
- स्पीड गन इलेक्ट्रॉनिक होती हैं, तथा माप लेने के लिए विकिरण उत्सर्जित करने हेतु जटिल सर्किटरी का उपयोग करती हैं।
- स्पीड गन को मूलतः द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सैन्य उपयोग के लिए विकसित किया गया था, तथा यह ध्वनि तरंगों के स्थान पर रेडियो तरंगों का उपयोग करके प्रभाव उत्पन्न करती है।

यह काम किस प्रकार करता है?

- स्पीड गन में एक रेडियो ट्रांसमीटर और एक रिसीवर होता है ।
- ट्रांसमीटर रेडियो तरंगें उत्सर्जित करता है, जिसे स्पीड गन पकड़े हुए व्यक्ति किसी वस्तु पर निर्देशित कर सकता है। रिसीवर वस्तु द्वारा परावर्तित तरंगों को स्पीड गन की दिशा में वापस एकत्रित करता है।
- यदि वस्तु स्पीड गन के पास आ रही है, तो वापस लौटने वाली तरंगों की आवृत्ति प्रेषित तरंगों की आवृत्ति से थोड़ी अधिक होगी। गन में लगा एक साधारण कंप्यूटर इस अंतर के आधार पर वस्तु की गति का अनुमान लगा सकता है।

गति और प्रभाव आपस में कैसे जुड़े हैं?

- ○सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगों की एक निश्चित गति होती है - जो उस माध्यम में प्रकाश की गति के बराबर होती है।
- ○निर्वात में, इस मान को c: 299,792,458 m/s से दर्शाया जाता है। स्पीड गन द्वारा पता लगाई गई आवृत्ति में कोई भी परिवर्तन सीधे ऑब्जेक्ट की गति के कारण होने वाले डॉपलर शिफ्ट से मेल खाता है।
- ○यह सिद्धांत शक्तिशाली है क्योंकि यह स्पीड गन को वायु प्रतिरोध से प्रभावित हुए बिना, दूरियों और वेगों की एक विस्तृत श्रृंखला पर सटीकता से काम करने की अनुमति देता है।
- ○एक स्पीड गन, किसी गतिशील वस्तु की गति की गणना, अंतर (प्राप्त और उत्सर्जित आवृत्तियों के बीच) को c से गुणा करके तथा उत्सर्जित आवृत्ति को 2 से भाग देकर कर सकती है।

RACE IAS

○यह संबंध दर्शाता है कि अंतर वस्तु की गति के सीधे आनुपातिक है : वस्तु जितनी अधिक तेजी से चलेगी, अंतर उतना ही अधिक स्पष्ट होगा।

- उपयोग: इसका व्यापक रूप से कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा यातायात की गति पर नजर रखने के लिए, प्रशिक्षकों द्वारा अपने खिलाड़ियों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए, तथा सटीक गति ट्रैकिंग की आवश्यकता वाले विभिन्न अन्य उद्योगों में उपयोग किया जाता है।

स्रोत: द हिंदू

डार्क पैटर्न

खबरों में क्यों?

उपभोक्ता मामले विभाग उपभोक्ताओं को डार्क पैटर्न से बचाने के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2024 पर सार्वजनिक उपयोग के लिए 'जागो ग्राहक जागो ऐप', 'जागृति ऐप' और 'जागृति डैशबोर्ड' लॉन्च कर रहा है।

डार्क पैटर्न के बारे में:

- डार्क पैटर्न को किसी भी प्लेटफॉर्म पर उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस/उपयोगकर्ता अनुभव इंटरैक्शन का उपयोग करके किसी भी भ्रामक डिज़ाइन पैटर्न के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- यह शब्द 2010 में हैरी ब्रिग्नुल द्वारा गढ़ा गया था।
- वे उपयोगकर्ताओं को गुमराह करने या धोखा देने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं ताकि वे कुछ ऐसा कर सकें जो वे मूल रूप से नहीं करना चाहते थे;
- यह उपभोक्ता की स्वायत्तता, निर्णय लेने या विकल्प को नष्ट या क्षतिग्रस्त करके किया जाता है; जो भ्रामक विज्ञापन या अनुचित व्यापार व्यवहार या उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन के बराबर है।
- केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने 2023 में डार्क पैटर्न की रोकथाम और विनियमन के लिए दिशानिर्देश अधिसूचित किए और 13 डार्क पैटर्न निर्दिष्ट किए, अर्थात्:
- झूठी तात्कालिकता, बास्केट स्नीकिंग, कन्फर्म शेमिंग, बलपूर्वक कार्रवाई, सदस्यता जाल, इंटरफ़ेस हस्तक्षेप, चारा और स्विच, ट्रिप मूल्य निर्धारण, प्रच्छन्न विज्ञापन और सता, ट्रिक वर्डिंग, सास बिलिंग और दुष्ट मैलवेयर।

'जागो ग्राहक जागो ऐप', 'जागृति ऐप' और 'जागृति डैशबोर्ड' के बारे में मुख्य बातें

- ये एक बुद्धिमान साइबर-भौतिक प्रणाली का हिस्सा हैं , जो वास्तविक समय में संचालित होता है और एआई और डेटा एनालिटिक्स के लिए राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन के तहत ऐरावत एआई सुपरकंप्यूटर पर चलता है।
- यह नवीन प्रणाली ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों पर मौजूदा पाठ और डिजाइन तत्वों का विश्लेषण करती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि उनका उपयोग उपभोक्ता मनोविज्ञान को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है या नहीं।
- 'जागो ग्राहक जागो ऐप: यह उपभोक्ता की ऑनलाइन गतिविधियों के दौरान सभी यूआरएल के बारे में आवश्यक ई-कॉमर्स जानकारी प्रदान करता है, तथा उन्हें सचेत करता है कि कोई यूआरएल असुरक्षित हो सकता है और सावधानी बरतने की आवश्यकता है।
- जागृति ऐप: यह उपयोगकर्ताओं को ऐसे URL की रिपोर्ट करने की अनुमति देता है जहाँ उन्हें संदेह है कि एक या अधिक डार्क पैटर्न की मौजूदगी को अवैध घोषित किया गया है। इन रिपोर्टों को फिर संभावित निवारण और बाद की कार्रवाई के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) में शिकायत के रूप में पंजीकृत किया जाता है।
- 'जागृति डैशबोर्ड' : इसका उपयोग उपरोक्त डार्क पैटर्न की उपस्थिति के लिए ई-कॉमर्स यूआरएल पर वास्तविक समय की रिपोर्ट तैयार करने के लिए किया जाता है, जिससे ऑनलाइन उपभोक्ता इंटरैक्शन की निगरानी और विनियमन करने की क्षमता बढ़ जाती है।
- महत्व: यह समाधान सीसीपीए को डार्क पैटर्न की पहचान करने, उपभोक्ता विवादों के समाधान में तेजी लाने में सहायता करेगा और उपभोक्ता हितों के लिए हानिकारक प्रथाओं पर अंकुश लगाने में सहायक होगा।

स्रोत: पीआईबी

पनामा नहर

खबरों में क्यों?

हाल ही में, अमेरिका के नव-निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने संकेत दिया है कि उनका प्रशासन पनामा नहर पर पुनः नियंत्रण पाने का प्रयास कर सकता है।

पनामा नहर के बारे में :

- यह एक मानव निर्मित जलमार्ग है जो पनामा के इस्तमुस के पार अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ता है।
- इसका स्वामित्व और प्रशासन पनामा के पास है, तथा यह तटरेखा से तटरेखा तक 40 मील लंबा है।
  ○इसका निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया गया था और अगस्त 1914 में पूरा हुआ था ।
  ○यह विश्व के दो सर्वाधिक रणनीतिक कृत्रिम जलमार्गों में से एक है, दूसरा स्वेज नहर है।

○1914 में इसके उद्घाटन से लेकर 1979 तक पनामा नहर पर पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका का नियंत्रण था, जिसने इसका निर्माण किया था।

○तथापि, 1979 में नहर का नियंत्रण पनामा नहर आयोग, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और पनामा गणराज्य की एक संयुक्त एजेंसी थी, को सौंप दिया गया और 31 दिसम्बर 1999 को दोपहर में पूर्ण नियंत्रण पनामा के पास चला गया।

- यह एक परिष्कृत, उच्च-इंजीनियरिंग प्रणाली है जो जहाजों को एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाने के लिए ताले और लिफ्ट की प्रणाली का उपयोग करती है।
- ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि पनामा नहर जिन दो महासागरों को जोड़ती है वे एक ही ऊंचाई पर स्थित नहीं हैं, तथा प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर से थोड़ा ऊंचा है।
- इस अंतर का मतलब है कि अटलांटिक के माध्यम से नहर में प्रवेश करने वाले जहाज को प्रशांत महासागर की यात्रा के दौरान ऊंचाई हासिल करने की आवश्यकता होती है। यह एक लॉक सिस्टम का उपयोग करके प्राप्त किया जाता है जो नहर के दोनों छोर पर जहाजों को आवश्यक समुद्र स्तर तक उठाता और गिराता है।
- मूल रूप से, तालों को या तो पानी से भर दिया जाता है (ऊंचाई बढ़ाने के लिए) या पानी को निकाल दिया जाता है (ऊंचाई कम करने के लिए), और वे पानी को ऊपर उठाने का काम करते हैं। कुल मिलाकर, इस प्रणाली में तालों के तीन सेट शामिल हैं - कुल 12 ताले - जिनकी सेवा कृत्रिम झीलों और चैनलों का उपयोग करके की जाती है।

स्रोतः इंडियन एक्सप्रेस

ऑर्डर ऑफ मुबारक अल-कबीर

खबरों में क्यों?

हाल ही में, भारत के प्रधान मंत्री को कुवैत के अमीर शेख मेशाल अल-अहमद अल-जबर अल-सबा द्वारा विसाम मुबारक अल-कबीर, या ऑर्डर ऑफ मुबारक द ग्रेट से सम्मानित किया गया।

ऑर्डर ऑफ मुबारक अल-कबीर के बारे में :

- यह कुवैत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है ।
- यह सम्मान कुवैती सरकार द्वारा राष्ट्राध्यक्षों, विदेशी देशों के शासकों तथा विदेशी शाही परिवारों के सदस्यों को मित्रता और सद्भावना के प्रतीक के रूप में प्रदान किया जाता है।

ऑर्डर ऑफ मुबारक अल-कबीर का इतिहास:

- यह पुरस्कार 1974 में मुबारक अल सबा की याद में स्थापित किया गया था - जिन्हें मुबारक अल-कबीर या मुबारक महान के नाम से भी जाना जाता है - जिन्होंने 1896 से 1915 तक कुवैत पर शासन किया था।
- उनके शासनकाल में कुवैत को ओटोमन साम्राज्य से ज़्यादा स्वायत्तता मिली। 1899 में मुबारक ने अपने राज्य को तुर्की से बचाने के लिए ब्रिटेन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे वह प्रभावी रूप से ब्रिटिश संरक्षित राज्य बन गया। मुबारक को कुवैत के भविष्य को आकार देने में एक प्रमुख भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है।
- वर्ष 1992 में कुवैत के इराक से आजाद होने के बाद इस पुरस्कार का स्वरूप बदल गया।
- अन्य प्राप्तकर्ता: इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज एच. डब्ल्यू. बुश और बिल क्लिंटन, सऊदी अरब के राजा सलमान, पूर्व फ्रांसीसी राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी।

स्रोतः इंडियन एक्सप्रेस

असंगठित क्षेत्र के उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण

खबरों में क्यों?

हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने 2023-24 के लिए असंगठित क्षेत्र उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण (ASUSE) के परिणाम जारी किए हैं।

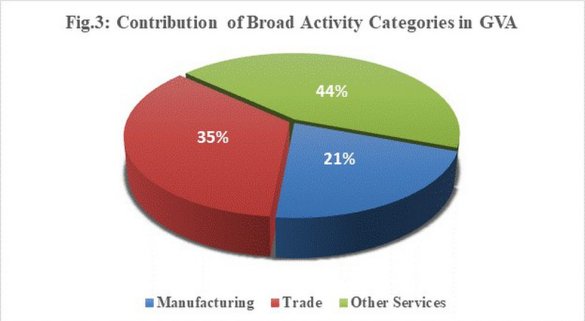

असंगठित क्षेत्र उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण के बारे में :

- इसका प्राथमिक उद्देश्य विनिर्माण, व्यापार और अन्य सेवा क्षेत्रों (निर्माण को छोड़कर) में असंगठित गैर-कृषि प्रतिष्ठानों की विभिन्न आर्थिक और परिचालन विशेषताओं को मापना है।
- सर्वेक्षण में इस क्षेत्र की विभिन्न आर्थिक विशेषताओं पर डेटा एकत्र किया जाता है, जिसमें श्रमिकों की संख्या, जीवीए, भुगतान किए गए पारिश्रमिक, स्वामित्व वाली अचल संपत्ति , बकाया ऋण, इसके अलावा विभिन्न प्रकार की परिचालन विशेषताएं जैसे स्वामित्व का प्रकार, संचालन की प्रकृति, पंजीकरण की स्थिति, आईसीटी का उपयोग आदि शामिल हैं।
- महत्व: यह डेटा नीति निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट के रूप में कार्य करता है, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी का समर्थन करता है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई), कपड़ा, श्रम और रोजगार मंत्रालय जैसे मंत्रालयों की आवश्यकताओं को पूरा करता है, और हितधारकों को सूचित, डेटा-संचालित निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाता है।

असंगठित क्षेत्र उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण की मुख्य बातें:

- ASUSE 2023-24 के परिणाम असंगठित गैर-कृषि क्षेत्र में प्रतिष्ठानों, रोजगार और उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि को उजागर करते हैं।
- इस क्षेत्र में प्रतिष्ठानों की कुल संख्या 2022-23 में 6.50 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 7.34 करोड़ हो गई, जो 12.84% की अच्छी वृद्धि दर्शाती है।
- कवर किए गए व्यापक क्षेत्रों में, "अन्य सेवा" क्षेत्र में प्रतिष्ठानों की संख्या में 23.55% की वृद्धि दर्ज की गई, जिसके बाद विनिर्माण क्षेत्र में 13% की वृद्धि देखी गई।
- इसी अवधि के दौरान सकल मूल्य वर्धन (जीवीए), जो आर्थिक प्रदर्शन का एक प्रमुख संकेतक है, 16.52% बढ़ा , जो अन्य सेवा क्षेत्र में 26.17% की वृद्धि से प्रेरित था ।
- महिला स्वामित्व वाले स्वामित्व प्रतिष्ठानों का प्रतिशत 2022-23 में 22.9% से बढ़कर 26.2% हो गया है

- प्रति नियोजित कर्मचारी का औसत पारिश्रमिक भी पिछले वर्ष 2022-23 की तुलना में 2023-24 में 13% बढ़ गया, जो वेतन स्तर में सुधार का संकेत है।
- इंटरनेट का उपयोग करने वाले प्रतिष्ठानों का प्रतिशत भी 2022-23 में 21.1% से बढ़कर ASUSE 2023-24 में 26.7% हो गया है।

स्रोत: पीआईबी

ग्रीनलैंड

खबरों में क्यों?

हाल ही में, अमेरिका के नव-निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एक बार फिर ग्रीनलैंड खरीदने में रुचि व्यक्त की है।

ग्रीनलैंड के बारे में :

- यह विश्व का सबसे बड़ा (गैर-महाद्वीपीय) द्वीप है, जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में उत्तरी अमेरिका और यूरोप महाद्वीपों के बीच स्थित है।
- भौगोलिक दृष्टि से इसे उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप का हिस्सा माना जाता है।
- यह उत्तर में आर्कटिक महासागर , पूर्व में ग्रीनलैंड सागर, दक्षिण-पूर्व में उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिण-पश्चिम में डेविस जलडमरूमध्य तथा पश्चिम में बफिन खाड़ी से घिरा हुआ है।
- ग्रीनलैंड कभी डेनमार्क का उपनिवेश था और अब डेनमार्क का एक स्वायत्त प्रांत है।
- जलवायु: ग्रीनलैंड ध्रुवीय क्षेत्र में है, जहाँ सर्दियों में तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और गर्मियों में तापमान शायद ही कभी 10-15 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। हालाँकि, इसके आकार के कारण, देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में तापमान में काफी अंतर हो सकता है।
- उच्चतम बिंदु: गुन्बजॉर्न का फजेल्ड
- राजधानी: नुउक

यह अमेरिका के लिए क्यों मायने रखता है?

- शीत युद्ध के दौरान इसका सामरिक महत्व बढ़ गया था और अमेरिका का वहां एक बड़ा एयर बेस है, पिटफिक स्पेस बेस, जिसे पहले थुले एयर बेस कहा जाता था। ग्रीनलैंड से अमेरिका रूस, चीन या यहां तक कि उत्तर कोरिया से आने वाली किसी भी मिसाइल पर नज़र रख सकता है और उसे रोक सकता है।
- ग्रीनलैंड दुर्लभ खनिजों से समृद्ध है , जिनका उपयोग मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक वाहनों और अन्य उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा बम और अन्य हथियारों में भी किया जाता है।
- चूंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण बर्फ पिघल रही है, इसलिए आर्कटिक क्षेत्र में नए जलमार्ग खुल सकते हैं और सभी प्रमुख शक्तियां यहां अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं।

स्रोतः इंडियन एक्सप्रेस

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार

खबरों में क्यों?

भारत के राष्ट्रपति आज 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करेंगे।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के बारे में :

- इसका आयोजन हमारे बच्चों की ऊर्जा, दृढ़ संकल्प, क्षमता, उत्साह और जोश का जश्न मनाने के लिए किया जाता है।
- यह भारत में बच्चों के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है।
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार
- यह पुरस्कार प्रतिवर्ष सात श्रेणियों में असाधारण उपलब्धियों के लिए बच्चों को प्रदान किया जाता है:
- कला एवं संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, खेल और पर्यावरण।
- पुरस्कारों की संख्या 25 होगी, तथापि, राष्ट्रीय चयन समिति के विवेकानुसार इस अधिकतम संख्या में कोई छूट दी जा सकती है।
- प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक पदक, प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पुस्तिका मिलेगी।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की पात्रता:

- बच्चा भारतीय नागरिक होना चाहिए।
- 5 वर्ष से अधिक तथा 18 वर्ष से अधिक आयु का बच्चा (संबंधित वर्ष की 31 जुलाई तक)।
- कार्य/घटना/उपलब्धि विचाराधीन वर्ष के लिए आवेदन/नामांकन प्राप्ति की अंतिम तिथि से 2 वर्ष के भीतर होनी चाहिए।

स्रोतः इंडियन एक्सप्रेस

RACE IAS®

Since 2010

सत्यमेव जयते

FOUNDATION BATCH IAS/PCS

Dr. Rajesh Shukla
Chairman, RACE Group

With Complete Study Material, Library Facility & Test Series

1 Year Batch for Graduate Students

3 Years Batch for 12th Passed Students

OFFLINE / ONLINE BATCH
English / Hindi Medium

OUR TOPPERS IN IAS

HIMANSHU GUPTA
UPSC (IAS), AIR 27

ANIMESH VERMA
UPSC (IAS), AIR 38

SHIVAKSHI DIXIT
UPSC (IAS), AIR 64

CHINTAN DOBARIYA
UPSC (IAS), AIR 376

PARICHAY KUMAR
UPSC (IAS), AIR 410

AJAY KUMAR GAUTAM
UPSC (IAS), AIR 415

PARMANAND PRAVIN
UPSC (IAS), AIR 439

VIVEK RAJPOOT
UPSC (IAS), AIR 588

YASHLOK K DUTT
UPSC (IAS), AIR 680

PRABAL GARG
UPSC (IAS), AIR 703

and many more----

OUR TOPPERS IN UPPCS

SATWIK SRIVASTAVA
DEPUTY COLLECTOR

PURNENDU MISHRA
DEPUTY COLLECTOR

SUNISHTHA SINGH
DEPUTY COLLECTOR

SHUSHANT SANWAREY
DEPUTY COLLECTOR

AKANKSHA GAUTAM
DEPUTY SP

SHAMBHAVI TRIPATHI
DEPUTY SP, 2022

KAUSTUBH TRIPATHI
DEPUTY SP, 2022

VISHAL GUPTA
DEPUTY SP, 2022

RISHIKA SINGH
DEPUTY SP, 2022

JUHI PRASAD
Deputy Collector
RANK 41, UPPCS 2021

SHIVAKSHI DIXIT
DEPUTY COLLECTOR, RANK 2, UPPCS 2020

SANT RANJAN
DEPUTY COLLECTOR, RANK 32, UPPCS 2019

AKANKSHA GAUTAM
DEPUTY COLLECTOR, RANK 68, UPPCS 2018

SUPRIYA GUPTA
DEPUTY COLLECTOR, RANK 78, UPPCS 2018

NEHA
ASSTT. COMMISSIONER UPPCS 2020

and many more----

CALL : 7388114444, 8917851448, 9044241755

LUCKNOW : ALIGANJ | INDIRA NAGAR | ALAMBAGH

KANPUR : COCA COLA CROSSING, G.T. ROAD, CALL : 9044327779

अभी डाउनलोड करें - RACE IAS मोबाइल ऐप

GET IT ON Google Play | Available on Windows Store

Follow us on :

www.raceias.com